

विषय सूची

१. अन्न-समस्या	९
२. यनपासी	३३
३. बरार-छाहुकारों का स्वर्ग	४३
४. बम्पारन में जमीनों की लूट	५७
५. खेत पैदावार के दामों के जरिये किसानों का शोषण	७३
६. सगाजवाद और किसान	८९

अन्न-समस्या

अन्न की समस्या मौजूदा हिन्दुस्तान की प्रधान समस्या तो है ही, उसका समाधान भारत की भावी - उन्नति की आधारशिला भी है। समस्या बहुत पुरानी है। एक शताब्दी पहले तक ही भारत में जनसंख्या की आवश्यकता के अनुपात से भूमि थी। पूरी उन्नीसवीं शताब्दी में महाकाश की प्रचंड ज्वालाला जलती रही। परन्तु उसकी प्रचंडता १८९० से १९४० के बीच के पचास वर्षों में घीमी पड़ गई। फिर भी अधिकांश आबादी भूख और अर्ध भोजन की पीड़ा से तड़पती रही। इसी बीच देश में यातायात के साधनों का विकास तथा बम्बों-चाबल के आयात की वृद्धि के कारण देश संमला और यन्त्र-यन्त्र विस्तृत होनेवाला विपन्न रोग नियंत्रण में रखा जा सका। परन्तु रोग कितना गहरा था, यह बंगाल के दुर्मिच्छ पर चूर्णिक दृष्टिपात से ही शायद हो जाता है। सरकारी आँकड़ों के हिसाब से अन्न की सिर्फ दो प्रतिशत कमी ने उस प्रांत के पन्द्रह लाख प्राणियों को मृत्यु की घाट में ढकेल दिया। तब से देश का ध्यान अन्न-समस्या की ओर आकृष्ट हुआ। केन्द्रीय और प्रांतीय दोनों,

किमानों की समस्याएं

सरकार वर्षों से 'अधिक अन्न उपजाना' आन्दोलन चलाने की चेष्टा कर रही हैं, फिर भी, अत्यवहारिक योजनाएँ, अपूर्ण वायदे और अन्न-आयात के केवल खर्चालि बिल ही मंत्रियों और सरकारी हुकूमतों की मेजों का सौन्दर्य बढ़ा रहे हैं ।

अन्न संकट की व्याधि दिनों दिन बढ़ती ही चली जा रही है । एक और जनसंख्या प्रत्येक वर्ष हजार में चौदह की दर से बढ़ रही है, अर्थात् हर वर्ष चालीस लाख से ज्यादा खानेवाले पैदा हो रहे हैं, दूसरी ओर जमीन की पैदावार बढ़ती ही नहीं है । निम्न लिखित आंकड़े इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं :—

वर्ष	जनसंख्या (करोड़ में)	जोती गई कुल जमीन (करोड़ एकड़ में)	प्रति व्यक्ति जोती गई जमीन
१९११	२३.१६	२०.८	०.९० एकड़
१९२१	२३.३६	२०.५	०.८९ "
१९३१	२५.८९	२१.१	०.८२ "
१९४१	२९.५८	२१.५	०.७२ "

१९११ से १९४१ के बीच प्रतिव्यक्ति जोती जाने वाली कुल जमीन ९० एकड़ से घटकर ७२ एकड़ हो गई । व्याधितो पुरानी है ही, निम्नांकित कारणों ने तंगी को चरम सीमा तक पहुँचा दिया । यह द्वन्द्व-वाद के विख्यात सिद्धान्त—परिमाण्वात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन का ज्वलन उदाहरण है ।

हमें इस बढ़ती हुई तंगी की पृष्ठ-भूमि में नीचे लिखी घटनाओं के व्यापक प्रभाव पर विचार करना होगा :—

१. वर्मा से चावल-आयात का बन्द होना ।
२. मूले या अधपेटे रहने के खिलाफ स. य. नरोध ।

३. भारत के विभाजन का खाद्यान्न की पूर्ति पर बुरा प्रभाव ।

तीसरी बात के प्रमाण में नीचे आंकड़े दिये जा रहे हैं :—

खाद्यान्न-उत्पादन १९४५-१९४६ में : लाख टनों में :—

	चावल	गेहूँ	अन्य खाद्यान्न	योगफल
भारत (हैदराबाद सहित)	१८.५	५.९	१६.६	४१.०
पाकिस्तान	८.२	३.१	२.०	१३.३
कुल उपज	२६.७	९.०	१८.६	५४.३

पाकिस्तान को एक ओर अरब हिन्दुस्तान की कुल पैदावार का २४.५ प्रतिशत हिस्सा मिला, दूसरी ओर जनसंख्या का सिर्फ १९.५ प्रतिशत । परिणाम स्वरूप अविभाजित भारत के बनिस्सत खंडित भारत में ३० प्रतिशत खाद्यान्न की कमी हो गई । अब कि अविभाजित भारत में हम प्रत्येक बयस्क को प्रतिदिन १७ औंस अन्न दे सकते थे, विभाजित भारत में केवल १३ औंस ही दे सकते हैं । भारत सरकार द्वारा ५० लाख टन गन्ने की अनुमानित कमी का, उत्पादन और उरभाग के आकड़ों से कोई सम्बन्ध नहीं है । सरकारी घोषणा केवल राशन की जिम्मेदारियों की आवश्यकताओं के ऊपर आधारित है ।

आकाल नाव समिति की निम्नलिखित राय की ओर तो सरकार का ध्यान गया ही नहीं है । “देश की पूरी आवादी के लिये काफी अन्न की व्यवस्था करना सरकार का कर्तव्य है । केवल भूखमरी और अकाल रोकने के लिये ही नहीं, बल्कि देशवासियों को स्वस्थ तथा शक्तिशाली बनाने के लिये ऐसा करना लाजमी है । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये सरकार को अपनी सारी शक्ति लगा देनी चाहिये ।”

समस्त देश की जनता के लिये अन्न की आवश्यकता का निम्न दृष्टिकोण से होना चाहिये :—

१. ऐसा पौष्टिक भोजन जो पूरा माना जाय ;

किस्तानों की समस्याएं

२. ऐसा भोजन जिसे खाकर मनुष्य काम चला सकता है; और
३. ऐसा भोजन जिसके बल पर मनुष्य केवल प्राण की रक्षा कर सकता है।

हम पहिले को पौष्टिक भोजन, दूसरे को आवश्यक भोजन और तीसरे को सुधार्य भोजन कहेंगे।

यदि किसी व्यक्ति को ३-४ औंस ही भोजन दिया जाय, तो किसी प्रकार वह जिन्दा तो रह सकता है; पर! इस सुधार्य भोजन का असर, आनेवाली नस्ल पर बहुत बुरा होगा। सुधार्य-भोजन की दृष्टि से ही, प्रधानमन्त्री के कथनानुसार, देश में काफी अनाज है, पर वह भी प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने के लिये नहीं। देश के किसी ऐसे इलाके में जहाँ केवल उपर्युक्त दृष्टि से ही काफी अनाज हो, जय सी गङ्गबड़ी के कारण भयंकर संकट उपस्थित हो सकता है। फिर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये देश की जनता में उत्साह भी तो नहीं पैदा किया जा सकता है। सुधार्य-भोजन के आधार पर देश की आवश्यकता की पूर्ति करने की योजना से बाढ़, अविवृष्टि आदि साधारण प्राकृतिक दुर्घटनाओं से भयंकर डलट फेर हो सकते हैं।

इस तरह की सरकारी गणनासे कई हास्यास्पद परिणाम निकले हैं। भारत में चूहों की संख्या ८० करोड़ कही गई है। यह मान कर कि प्रत्येक चूहा प्रतिदिन ३ औंस अन्न खा जाता है, एक सरकारी पच्चे में बताया गया है कि प्रति वर्ष ७८ लाख टन अन्न चूहे घट कर जाते हैं। अतः क्यों न चूहों को मारने का आन्दोलन चलाया जाय और अन्न का आयात बन्द किया जाय? नाशक गैसों का प्रयोग लोगों को समझाया जाय और भी भुंशी साहब वन महोत्सव के साथ भूमिका - विध्वंसक यज्ञ प्रारम्भ करें। आज से ६००० वर्ष पूर्व जनमेजयने भी तो सर्प-विध्वंसक यज्ञ किया था।

अन्न को व्यर्थ नष्ट होने से बचाने के लिये जो भी उपाय किये

यह, मेरा उनसे कोई मतभेद नहीं है। चूहे भी हमारे अन्न को बर्बाद न करें।
इस प्रकार की गणना से अन्न की कमी कतई दूर नहीं की जा सकती।

पोष्टिक भोजन की (जो भारतवर्ष की अधिकांश जनता को उप-
लब्ध नहीं है) चर्चा तो छोड़ ही दीजिये। यदि आवश्यक भोजन का भी,
तो कम से कम २५०० कैलोरी यूनिट दे सके, प्रबन्ध किया जाय, तो भी
५० लाख टन, नहीं बल्कि २ करोड़ टन अन्न की आवश्यकता पड़ेगी।
आज आवश्यक भोजन के लिये भी जितने अन्न की आवश्यकता है,
उसका ७० प्रतिशत ही भारत उपजा सकता है। हाँ, यदि हम अधिक दूध,
माँस, अंडे, सरकारियाँ और अन्याय वस्तुएँ उपजाने लगें, तो निःसन्देह
अन्न की आवश्यकता कम पड़ेगी। अन्न के उपभोग में हम मात्रा एवं
गुण का विरोधी अनुपात पाते हैं। यदि अन्न उच्चकोटि का नहीं है तो
उसकी मात्रा अधिक होनी चाहिये। जिस भोजन में चर्बी और प्रोटीन की
कमी रहती है उसमें स्टार्च का भाग अधिक रहता है। सामाजिक आव-
श्यकताएँ, बीज की जरूरत, अन्न का सूखना आदि बातों का विचार करने
पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिये प्रति दिन साफ
किये हुए आधा सेर अनाज की आवश्यकता पड़ेगी। यानी हर एक व्यक्ति
के लिये हमें ४॥ मन अनाज की जरूरत है इसका अर्थ यह हुआ कि ६
करोड़ टन अन्न की आवश्यकता है। इसके अलावे आधा करोड़ टन हमें
प्रति वर्ष अन्न मंडार के बनाने में लगाना चाहिये। इस तरह पूरा आव-
श्यकता ६॥ करोड़ टन की हुई। समी प्रकार के अन्नो का उत्पादन यदि हम
४॥ करोड़ टन बूँटें, तो हमें २ करोड़ टन अन्न की कमी पड़ेगी। इस
बात को ध्यान में रखना चाहिये कि ६ करोड़ टन के आँकड़े में दाल
और अन्यान्य पूरक वस्तुएँ भी शामिल हैं। इस प्रकार ८० विशत
व्यक्तियों के भोजन में प्रत्येक के लिये प्रति दिन १६ औंस अनाज, ४ औंस
दाल और अन्यान्य पूरक वस्तुएँ शामिल कर ली गई हैं। इस भोजन की

किसानों की समस्याएँ

केलोरी यूनिट २४०० से अधिक नहीं होगी ।

अब इस बात पर विचार करें कि अन्न की इतनी कमी रहने पर भी हमलोग जीवन निर्वाह कैसे कर पाते हैं ? भारतीय समाज को शैलीबद्ध किये बिना हम इस रहस्य को नहीं समझ सकते हैं । यहाँ की जनता निम्न वर्गों में विभाजित है तथा पूरी जनसंख्या के साथ उनकी संख्याओं का अनुपात इस प्रकार है—

१. शहरी लोग	...	१५ प्रतिशत
२. जमींदार और धनी किसान	...	५ "
३. मध्यम किसान	...	१० "
४. गरीब किसान और खेडमजदूरों का एक हिस्सा	३०	"
५. देशांत के गैर-खेतिहर	...	२० "
६. खेतिहर मजदूर	...	२० "

१ और २ वर्ग के व्यक्तियों को पूरा भोजन मिलता है । ३ को पूरे भोजन से कुछ ही कम मिल पाता है । अतः ४, ५ और ६ वर्ग के लोगों को ही अभावभाष के कारण सबसे अधिक कष्ट उठाना पड़ता है । नीचे विभिन्न वर्गों के लोग कितना खाते हैं और प्रत्येक वर्ग के हर एक व्यक्ति को कितना भोजन मिलता है, उसकी तालिका दी जा रही है ।

श्रेणी	कुछ जनसंख्या का प्रतिशत	जन-संख्या करोड़ में	ग की सत्या करोड़ में	प्रतिव्यक्ति प्रति दिन सुर्कि अ स में	प्रति बालिका, प्रति दिन सुर्कि औस में	दरमा लाख टन में
--------	-------------------------	---------------------	----------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	-----------------

१ शहरवासी १५ ५.४ ४.३ १६ २० ८६

२. जमींदार तथा

घनी किसान	५	१८	१४४	१९	२४	३५
३. मध्यम किसान	१०	३६	२९	१६	२४	७०
४. गरीब किसान	३०	१०८	८६४	१२	१५	१३०
५. ग्रामीण गैरसेविहर	२०	७२	५८६	१२	१५	८९
६. सेव मजदूर	२०	७२	१७६	९	१२	७०
	१००	३६	२८८	१३	१६ १/२	४८०

औसत औसत

अन्न उपभोग की उपर्युक्त तालिका से, हमें यहाँ की दरिद्रता का भी एक चित्र मिल जाता है। यह तालिका साफ बतलाती है कि ४ करोड़ ८० लाख टन अन्न में ७० प्रतिशत जनता को प्रति मनुष्य प्रतिदिन १२ औंस का भोजन भी नहीं मिल पायगा।

अगर उत्पादन ४ करोड़ ८० लाख टन हो तो हर धेड़ी के लोगों को ऊपर दी गई तालिका के मुताबिक खुराक मिल जायगी। और अगर यही मकसद हो, जैसा कि श्रीके० एम० कुंशीने कहा है कि १२ औंस अन्न फाम नहीं करकेवाले और १६ औंस अन्न काम करनेवाले बालूगोंके लिये आवश्यक है, तब तो समस्या हल हो ही जाती है। केवल ३० लाख टन गन्ना जो बाहरसे मंगाया जाता है, उसे पैदा करने की बात रह जाती है। इसी आधार पर हमारे प्रधान मंत्री कहते हैं कि देश में काफी खाद्यान्न मौजूद है, समस्या सिर्फ गन्ने को छुपाये रखने की है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि उनका यह हिसाब जुघार्थ भोजन के आधार पर लगाया गया है ऊपर की तालिका में मान लिया गया है कि आबादी के २० प्रतिशत हिस्से की राशन की आवश्यकता नहीं होगी। अर्थात् १६ औंस राशन, अगर परिवार के बालिगों को दिया जाय, तो उस परिवार के बच्चों की भी आवश्यकता पूरी हो जायगी। दूसरी बात यह है कि उसके पास आगे के लिये कुछ बच नहीं जायगा। यह स्थिति, खास कर ऐसे समय के लिये, जब कि प्रकृति प्रतिकूल हो जाय, बड़ी ही खतरनाक है।

विज्ञानों की समस्याएँ

ग्राम देश में कुछ खाद्यान्न की जो पैदावार है तथा बाहर से जो गन्ना भंगया जाता है, उससे प्रति वर्ष, प्रति बालिग को ३४० से ३५० पाउण्ड, से अधिक नहीं दिया जा सकता है । इसका अर्थ यह हुआ कि ७० प्रतिशत से अधिक आवादी प्रतिदिन १४०० से १६०० यूनिट कैलरी से अधिक का भोजन नहीं कर पाती । यह औसत मी, जो हम लोगों ने कागज पर लगाया है, व्यवहारिक जीवन में नहीं पाया जाता । चौथी और पाँचवीं श्रेणी के लोगों को प्रतिदिन १६ प्रॉक्स मी खाद्य सामग्री नहीं मिलती । जब इस तथ्य के लोगों को पूरा अनाज मिल जाता है, तब वे भर पेट भोजन कर लेते हैं और इसका नतीजा यह होता है कि आगे आनेवाले दिनों में या तो वे आधा पेट खाते हैं या भूले रहते हैं । यही कारण है कि मैं इसको हिन्दुस्तान का भूख-बजट के नाम से पुकारता हूँ । इसी बजट को पूरा करने के लिये प्रधान मंत्री ने जी जनता से अपील की है ।

इस आधारभूत तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि आधा पेट भोजन पानेवाले लोगों को वर्ष के उन महीनों में, जब फसल तैयार नहीं होती, जिसे हम सूखा महीना कहते हैं, भूखें रहना पड़ता है और इस अवस्था में मामूली प्राकृतिक प्रकोप के कारण अगर अन्न की पैदावार में साधारण भी क्षति पहुँच जाय तो भूख मरने वालों की संख्या में वृद्धि होने लगती है । और इस बड़े पैमाने पर भूख से मरने की स्थिति का नाम अकाल है ।

यह बराबर याद रखना चाहिये कि इस “भूख-बजट” में जनता को आगे के लिये कुछ बचाकर रखने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है । फलतः गल्ले का मंदार मायब हो जाता है और जनता भविष्य के लिये अपने को सुरक्षित नहीं पाती । अन्न का मंदार तो रखना ही पड़ेगा चाहे सरकार रखे, या गाँव की सहयोग समितियाँ या व्यक्ति रखें ।

अब हम उपज के आँकड़ों को लें। सम्पूर्ण देश में कुल २४ करोड़ एकड़ जमीन जोत के अन्दर आ चुकी है, जिसमें आज केवल १७ करोड़ एकड़ में ही खाद्यान्न पैदा किया जाता है। १९४७-४८ में साढ़े बारह प्रतिशत बीज, यर्वादी आदि को छोड़कर कुल ४१० लाख टन खाद्यान्न पैदा हुआ, जिसमें चावल और गेहूँ का सम्मिलित उत्पादन २४० लाख टन है। न रोती का विस्तार हो रहा है और न उत्पादन वृद्धि का कोई लक्षण हो दीख पड़ता है। यह निराशाजनक परिस्थिति देश की आर्थिक व्यवस्था को अत्यन्त घटा कर जनता को उन्नति का मार्ग ही अवरुद्ध कर रही है। १९४१-४४ में खाद्यान्न की अधिक उर्ज अवश्य हुई थी, किन्तु उसके बाद से ही उत्पादन का हास होने लगा है। निम्नांकित सारिका इसे बतला रही है :-

	१९३६-३९	४१-४२	४३-४४	४६-४७	४७-४८
खाद्यान्न	१००	९३	१०७	९७	९६
कपास	१००	१०९	८९	५१	५२
जूट	१००	८२	७७	६६	८३
तेलहन	१००	९४	१०४	१००	१०१
विविध	१००	११२	११६	१२१	१२२
औषध	१००	९५	१०६	९६	९७

उत्पादन और आवश्यकता की इतनी जोड़ी खाई खेदान्न - पूर्ति की समस्या को तो विपन्न बना ही रही है, औद्योगिक उत्पादन को भी अवरुद्ध कर रही है। हिन्द-सरकार ने खाद्यान्न पूर्ति के लिये अत्यधिक अत्यधिक आयात की नीति अपनाई है। साधनों के अभाव में एवं गति शून्य अर्थ व्यवस्था ने भारत की विदेशी मुद्रा-बचत को अत्यधिक कम कर दिया है। विगत वर्षों में हिन्द के संचित स्टर्लिंग बचत में ८०० करोड़ रुपये की कमी हो गई है। हिन्द सरकार के रिजर्व बैंक के डिपोजिट

में भी कई सौ करोड़ रुपये कम हो गये हैं। अन्तर्राष्ट्रिय जगत में दान भेंट की रिस्तेदारी सर्वदा नहीं चलती। इस अत्यधिक निर्धन ने, विदेशी विनिमय को अत्यन्त दुष्कर बना दिया है। ऐसी परिस्थिति पैदा हो चुकी है कि भारत या तो अधिक लायान्न उपजाये या मृत्यु का आह्वान करे।

सन् १९४९ में सरकार ने ५५ लाख टन अधिक गन्ना पैदा करने की घोषणा की थी, पर अभी तक वह भी पूरी नहीं हो सकी है। गलत आंकड़ों और रिपोर्टों के चक्कर में पड़कर, भारत सरकार ने अन्न समस्या के साथ जो मछौल किया है, उससे तो स्थिति और रंगीन हो गई है। बिहार का ही उदाहरण ले लें। विकास विभाग ने अपने सबसे हाल की रिपोर्ट में दावा किया है कि विभिन्न विकास योजनाओं की मदद से उन्होंने १६६ हजार टन अधिक गन्ना पैदा किया है। लेकिन राज्य के कुछ हिस्सों में वास्तव में गलने का दावार गिर गई हैं प्राकृतिक कारणों से नहीं, आवश्यकता के आ साधन थे, उन्हें ठीक हालत में नहीं रखने के कारण केवल गया और पटना के जिले में सिंचाई के साधनों के बिगड़ जाने से काफी पैदावार भट गई है। अतः इस तरह के हिसाब से कोई लाभ नहीं होता।

अन्न संकट को हल करने के लिये अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाओं और सामाजिक तथा आर्थिक सुधारों को एक साथ मिलाकर रास्ता निकाला जा सकता है। अन्न की गिनती अभी दीर्घकालीन योजना में की जाती थी उसे आज ही पूरा करने का सवाल बन गया है, और जिसे हम अल्पकालीन योजना में शुमार करते थे, उसे तत्काल हमल में खाने की आवश्यकता उठ खड़ी हो गई है। जैन अमीन की बेदखली को रोकने तथा उचित लगान निर्धारित करने के प्रश्न को हम एक दिन भी टाल नहीं सकते। 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन का तब तक की नहीं जा नहीं निकलेगा, जब तक सारे देश के गांव के

गरीबों को यह भरोसा नहीं दिलाया जाय कि उनके कब्जे की जमीन से उन्हें कोई बेदखल नहीं कर सकता, तथा पैदावार का मुनाफ़ा हिस्सा ही लगान के रूप में लिया जायगा। उद्देष्ट कमीशन ने भी इस सवाल को अन्नाये. सवाल से सम्बन्धित माना था। फेमिन कमिशन की रिपोर्ट का यह अंश हम नीचे दे रहे हैं :—

“गैर फायदी कार्टकारों के लिये जमीन पर उनके अधिकार का समय तथा लगान की रकम ऐसी होनी चाहिये, जिससे अच्छी खेती करने पर उनमें उत्साह पैदा हो सके। इस आवश्यक सिद्धांत पर ही फार्मकारों का कानून को आधारित रहना चाहिये। किसी क्षेत्र के फार्मकारों का कानून से यहां के रैयतों को खेती करने की प्रेरणा मिलती है या नहीं, या किसी क्षेत्र में प्रचलित फार्मकारी कानून पैदावार बढ़ाने के रास्ते में रुकावट तो नहीं पैदा करता, इन बातों की जांच सावधानी से की जानी चाहिये।”

यह कितने दुख की बात है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कृषि-सुधार तथा अन्न की पैदावार से कोई सम्बन्ध ही नशा मालूम पड़ता। अभी हाल में ही दिल्ली के एक प्रेस प्रतिनिधि से उन्होंने कहा कि उसका (कृषि सुधार सम्बन्धी कानूनों का) अन्न-समस्या से क्या सम्बन्ध है ?

अन्न उत्पादन की बाधाएं अब तरु बढ़ती ही चली गई हैं। अर्थ, खेतीका तरीका तथा कृषि प्रणालीकी अनेक समस्याओंका समाधान निकालना है। व्यक्तिगत चेष्टा के सिवा सम्मिलित प्रयत्न भी अत्यावश्यक है। किसी भी सरकार के लिये ऐसे विशाल देश में इतने कम समय में लाखों सिंचाई योजनाओं को खड़ा करना और उन्हें व्यवस्थित रीति से चलाते रहना असंभव सा है। यह तभी संभव हो सकता है, जब गांधी जी उनका प्रोत्साहित हो और सिंचाई कार्यों को सम्मिलित रूप से अपने हाथ में ले। इसके लिये...

१. राज और खेतिहरों के बीचवाले सभी मध्यवर्तियों को मिटा देना

२. कब्जे की गारंटी, और

३. भूमि का पुनर्वितरण; आवश्यक है।

खेती के लिये पानी का इन्तजाम करने के ग्रहण सवाल पर भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। १९ वीं सदी के आरम्भ में एक अमरीकी पत्र को अपनी रिपोर्ट देते हुए कार्ल मार्क्स से कहा था कि अंग्रेजी साम्राज्यवादियों ने हिन्दुस्तान में सिंचाई के साधनों की, जिनसे वर्षा की खेती निर्भर करती है, मरम्मत की घोर उपेक्षा की है। खेती के सम्बन्ध में इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि सिंचाई के अभाव में अच्छे बीज, खाद, तथा अन्य चीजें भी बेकार हो जाती हैं। कभी कभी तो पानी के अभाव में दो-दो या तीन-तीन बार खेत में बीज लल जाते हैं या अति-वृष्टि से दह जाते हैं। अतः पानी के लिये अगर साधारण गारंटी भी किसानों को नहीं रहे, तो फिर उनके लिये अच्छे बीज, खाद आदि पर खर्च करना कठिन हो जाता है।

प्राचीनकाल में ऋषि, राजाओं को बराबर समझाते थे कि वे खेतों को नक्षत्र के भरोसे न रखें। नक्षत्र के भरोसे यानी वर्षा के भरोसे खेतों को रखने की वेद की भाषा में “देवमातृका” कहते हैं। “न कश्चित् देवमातृका” — कोई राजा खेतों को नक्षत्र के भरोसे न रखे। यह उपदेश बार-बार प्राचीन ग्रन्थों में आया है। नारद ने हस्तिनापुर के राज-मन्त्र-उद्घाटन के समय में बोला था।

“कश्चिद्राष्ट्रं नकाग नि पूर्णानिच वृहन्ति च
मानशो विनियिष्टानि न हृषि देवमातृका”

— महामारव समाप्य

सिंचाई के साधनों के अभाव तथा किसानों की माली हालत खराब रहने के कारण व्यापक जमीनों की पैदावार नहीं बढ़ पाती है। अगर इन दोनों कठिनाइयों को दूर कर दिया जाय, तो किसानों में एक

नई आशा एवं उत्साह पैदा होगा और वे अपने कठिन परिश्रम से देश की पैदावार को कम से कम २० प्रतिशत तो अवश्य ही बढ़ा देंगे। आबाद जमीन की पैदावार बढ़ाने के साथ साथ कम से कम १० करोड़ एकड़ नयी जमीन को भी हमें खेती के अन्दर लाना होगा, तभी जमीन पर जो आज भारी बोझ पड़ा हुआ है, उसे हम कम कर सकते हैं। 'एक घटा देश को' कार्यक्रम के आधार पर गांव की जनता को संगठित कर आबाद जमीन की पैदावार बढ़ाना तथा सरकार द्वारा खेतिहर पलटन की भर्ती कर, नयी जमीन को खेती के अन्दर लाना ये दोनों ही आज हमारी अन्न योजना के मुख्य अंग होने चाहिये। आज हमारे देश में मुख्य प्रश्न पैदावार का है।

कंट्रोल सम्बन्धी नियम चाहे कितने भी सफल क्यों न हों, उनमें समस्या हल नहीं हो सकती। अन्तवोगत्वा वस्तुकी कमी को दूर करके ही परिस्थिति पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें अन्न उत्पादन में अन्न युद्ध की नीति अपनानी है, तो हमें तत्काल २० लाख व्यक्तियों की एक किसान सेना संगठित कर आवश्यक औजारों को जुटा लेना चाहिये। हमारे कारखाने कृषि के औजार बनाने लग जायें। सभी प्राप्य टैंकों को मशीन इलों में परिणत कर देना चाहिये। नई भूमि को जीव में लाने की योजना को सफल बनाने के लिये जितनी सैन्य शक्ति और मेकैनिक्ल फौज की आवश्यकता है, उतनी जुटा ही लेनी चाहिये। विदेशी विभाग को अपनी सारी शक्ति से विदेशों से ज्यादा से ज्यादा कृषि के आवश्यक औजारों को प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिये।

इस महान कार्य के लिये राष्ट्र को तैयार करने के लिये हिन्दुस्तान के ग्रामीण जीवन से सामन्तवादी व्यवस्था के चिन्हों को मिटाना नितान्त आवश्यक है। मौजूदा सरकार में न तो राष्ट्र को ही इसके लिये तैयार

किमानों की समस्याएँ

करने की क्षमता है और न अर्न्तुह्न सामाजिक वातावरण हो पैदा करने की। असली लड़ाई तो प्रकृति और शरमायादारी से है। आज शासन की बागडोर जिनके हाथों में है, वे न तो कोई ऐसी लड़ाई ही छेड़ना चाहते हैं और न ऐसी लड़ाई छेड़ने की क्षमता ही रखते हैं। युद्ध के पैमाने पर अक्ष समस्या को हल करने का जो नारा आज सरकार दे रही है, वह बिलकुल ही ग्योखला है। सरकार के पास इस समस्या को हल करने के लिये न तो योजना है और न दृढ़ मानना ही।

दिल्ली में मुख्य-अधियों का सम्मेलन इस निश्चय पर पहुँचा कि अगर गल्ला बख्शी का काम सकल-गपूरक चलाया जाय तो, समस्या हल हो जायगी। लेकिन इस प्रश्न पर भी सरकार विशेष चिन्तित नहीं है। ऐसे संकटकाल में जब कि पैदावार कम हो, गल्ला छिपाने की प्रवृत्ति देश के लिये अत्यधिक घातक सिद्ध हो सकती है। सन् १९४१ में और आज भी, जिस प्रकार गहने की कीमत बढ़ती जा रही है, वरन तो उस समय ही और न आज ही व्यापकगत मानी जा सकती है। आर्थिक-संकट के साथ ही सामाजिक घटना का संयोग स्थापित होता है, तथा मूल्य में इस प्रकार की वृद्धि होती है। सरकार का या तो लगातार-महीने तक बाजार में इतना गल्ला उतारना पड़ेगा कि शर्मों का पैर स्पष्ट दृष्ट जाय, अथवा बीज के आश्रयक पदार्थों में दक्षिण व्यापार को बिलकुल रोक देना होगा। इन दोनों के बाट का कोई तरज्जु नहीं सकता। परन्तु हल यावद आर्थिक दृष्टि से सम्भव न हो सके, अतः दूसरे मुद्दे पर अमल करना ही एकमात्र रास्ता रह जाता है। ऐसा साहसपूर्ण कदम उठाना यावद भारत सरकार के बूते के बाहर है। लेकिन हमें याद रखना चाहिये कि "जेमिन कमोशन" ने अपने शुक्राक्षी ॥ इस तरह की धर्म-धर्म के लिये जोरदार सिद्धांत की की।

व्यापार में यह बात लायित हो चुकी है कि छोटे दिवस के ल गू

किये गये नियन्त्रण से नियन्त्रण नहीं लागू करना ही अच्छा है। आज की हालत में नियन्त्रण के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं, लेकिन रास्ते में न छोड़कर इसे वहाँ तक लागू करना चाहिये, जहाँ तक वास्तव में उसकी आवश्यकता है। सरकार इस रास्ते पर उतनी दूर तक नहीं जाना चाहती, जितनी की उसे चाहिये। फलतः राशनिंग और तथाकथित गल्ला बस्ती, दोनों कामों में सरकार अब तक असफल रही है। हम जरा विस्तार से इस प्रश्न पर विचार करें। वर्तमान राशनिंग द्वारा देश की ४१ प्रतिशत आबादी की भाजन - व्यवस्था की जाती है, जिसका व्यौरा इस प्रकार है :—

१९४७

नियमानुसार निर्धारित राशनिंग (स्टेचुटरी राशनिंग)	५ करोड़ ३६ लाख
अनियमित राशनिंग (ननस्टेचुरी राशनिंग)	६ करोड़ ९२ लाख
नियन्त्रित वितरण (कन्ट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन)	२ करोड़ ८ लाख

लेकिन वास्तव में यह केवल पहली श्रेणी अर्थात् नियमानुसार निर्धारित राशनिंग क्षेत्र के लोगों तक ही सीमित है, जिनकी संख्या कुल आबादी का १५.४ प्रतिशत मात्र ही है। इसमें ८० प्रतिशत शहरों के लोग हैं और २० प्रतिशत मात्र गाँव के। लेकिन इस तथ्य के को जिताने के लिये भी, जिनमें ५ करोड़ ३६ लाख आदमी आ जाते हैं, १२ और हर बालिंग के हिसाब से हमें ५० लाख टन गल्ले की आवश्यकता पड़ेगी। सरकार इस मांग को गल्ला बस्ती तथा बाहर से अनाज मंगा कर इस प्रकार पूरी करती है :—

	देश की पैदावार (लाख टन में)	गल्ला बस्ती (लाख टन में)	आयात (लाख टन में)
१९४७	३८५	३८	२३
१९४८	४२६	२५	२८

‘अन्न समस्या’ — लोज परिषद्

किसानों की समस्याएं

लेकिन आबादी के १५४ प्रतिशत लोगों को भी १२ अंश की गारटी सरकार के लिये देना सम्भव नहीं हो सका। सरकार की पर्याप्त अनाज प्राप्त नहीं हुआ। अनाज आज बागी हो गया है और जैसा कि हर सरकार 'बागी' को गिरफ्तारी के लिये हुक्मनामा निकालती है, वैसे ही दिल्ली सरकार ने 'बागी' अनाज की गिरफ्तारी के लिये 'गल्ला बसूली' नामक वॉरंट जारी किया है।

सरकार ने अनाज को जितना ही अपने पास लाने की कोशिश की, अनाज उतना ही सरकार से दूर भागता गया। ऐसा क्यों हुआ? अनाज के विदेशी व्यापार पर सरकार का एकाग्र एकाधिकार और अन्य देशी व्यापार पर भी आंशिक एकाधिकार है। कंट्रोल रहने के बावजूद इस तरह अनाज के गायब होने के कारण पर सरकार ने कभी भी गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया। ऐसी आर्थिक तथा मानवीय स्थिति का हल केवल शक्ति प्रयोग द्वारा नहीं हो सकता। सब से पहिले इस बात को धृष्टी वह समझ लेना चाहिये कि गल्ला बसूली नाम ही गलत है। यह तो जबरन जप्ती है और इसके लिये जो हथकड़ी लगाया जाता है उसकी शकल तो मुद्रावले की है, इसे हम मूल्य नहीं बढ़ सकते।

सस्ते हथ पर, इस जबरन गल्ला-जप्ती से अगर समाज को कोई हानि पहुंचता तो कुछ खतोप भी होगा, लेकिन सरकारी नीति से किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई, न तो (क) अनुत्पादक वर्ग को १२ अंश प्रतिदिन के अनाज से राशन मिल सका (ख) न अन्न की कमी की बराबरी हो सकी (ग) न मूल्य ही नीचे गिर सका (घ) न गहले का भंडार ही जम सका और (च) और न उत्पादन ही बढ़ सका। केवल (क) अपने बादाको पूरा करने में ('बढ़ने हुए बादा' करना बपाटा टीक न होगा) (ख) अनाज की शेक रखने में (ग) दाम का बोझ एक ठपके (१५.४ प्रतिशत आबादी) के अनुत्पादक लोगों के कंधों से

हटाकर दूसरे तबके (१८.६ प्रतिशत आबादी) के अनुसूचक लोगों के कंधों पर ढालने में (घ) और कुछ जमीनों में खेती बन्द कर देना पड़ने में ही, सरकार सफल हो सकी है ।

इस असफलता का क्या कारण है ? शक्ति प्रयोग के आधार पर आर्थिक नीति को आगे बढ़ाना कठिन ही नहीं असम्भव है । 'हिन्दुस्तान की अन्न समस्या' नाम की पुस्तक में श्री प्रभाकर सेन ने ठीक ही कहा है :—

“तब हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सरकार ने गन्ना बखूली के लिये अनाज का जो दाम रखा, उसमें तथा चालू बाजार-दर में कोई मेल ही नहीं था । अतः जितना गन्ना सरकार बखूल करना चाहती थी उतना गन्ना सरकार को नहीं मिला सका । फूडप्रेन पालिषी कमिटी ने भी अपनी इन्टरिम रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि इस बात की आम खर्चा लोगों में है कि गन्ने का जो मूल्य किसानों को दिया जाता है, वह उत्पादन के लागत खर्च के बराबर भी नहीं होता । न लागत पूंजी तथा भ्रम पर ही उसमें कोई लाभ की गुंजाइश होती है, और न रोज बढ़ती हुई मंहगी से ही उसका कोई सम्बन्ध रहता है ।”

परन्तु हिन्द सरकार पूंजीपतियों का इतना ज्यादा गुलाम हो चुकी है कि अब उसे कृषि जन्य वस्तुओं का मूल्य घटाने में कोई संकोच नहीं है । हार्दिक इच्छा रखते हुए भी, औद्योगिक श्रम की मजदूरी नहीं घटा सकती है, क्योंकि मजदूर ज्यादा संगठित और सचेत हैं । वह शायद मजदूरों की छुट्टी भर कर सकेगी । वह जीवन-व्यय को कम करने का अभासमक नाश लगा कृषि जन्य वस्तुओं के मूल्य कम करने में मजदूरों का सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा भी कर सकती है । आम तौर पर मूल्य घटाने का कोई विरोध न हो सकता । परन्तु सभी वस्तुओं का मूल्य ज्यों का त्यों रखते हुए केवल कृषि जन्य वस्तुओं का मूल्य कम करने से

किसानों की समस्याएँ -

ग्रामीण उत्पादकों का अत्यधिक शोषण ही होगा ।

इस्टर्न इकानामिस्ट (पूंजीवादी पत्रिका) ने निर्मम हो १२ अगस्त १९४६ को लिखा था "हमें उद्योग और कृषि जन्य वस्तुओं के मूल्यों के विषय सम्बन्धों को बढ़ाते ही जाना चाहिये । क्योंकि इसी से पूँज, धारिणिक विधान सम्भव है । दुनियाँ प्रत्येक के देश में कृषि का लाभ औद्योगिक लाभ से आधा रहता है । कृषि और उद्योग के विषय सम्बन्ध को, भारत जैसे पिछड़े देश को उन्नति के पथ पर अग्रसर करने के लिये, और अधिक विषम बनाये रखना ही आवश्यक है । यह वितरण नीति दूषित अवश्य मालूम पड़ती है किन्तु यह विषमता जानबूझ कर सदा कायम रखी जाती रही है । "हमें, पूंजीवादी अर्थ-शास्त्रियों तथा उनके उच्च हुकूमतों के और रोप को समझने के लिये विभिन्न अर्थों के उत्पादन आँकड़ों को अपने अपने मूल्य की दृष्टि से देखना चाहिये ।"

कृषि आमदनी का व्योरेवार विवरण

(करोड़ रुपये में)

अन्न	१९४१-४२	१९४६-४७
१. चावल	१,५९७	८,१६४
२. गेहूँ	१,०१२	२,००७
३. ज्वार	१७८	८७६
४. बाजरा	१७६	१७३
५. मक्का	१५०	२६५
६. रागी	९७	१४७
७. जौ	१८१	४८४
८. चन्ना	३५८	१०६१
९. ईल	६२	३१०
१०. तिल	६१	२०६

११. मूंगफली	२३०	८५९
१२. सरसो	१२८	५५६
१३. अलसी	६९	१०२
१४. अंडा दूध		१४
१५. दई	४४१	७०१
१६. जूट	२३३	५५६
१७. चाय	६२३	५६४
१८. काफी	१०	४०
१९. तम्बाकू	२००	४७२
सभी अन्नों का कुल मूल्य	७,९८३	१७,६७५
अन्य अन्नों का मूल्य	६१९	९४६
कुल मूल्य	८,६०२	१८,६२१

मैंने उपर्युक्त वारिका में केवल दो वर्षों को लिया है। कृषि जग्य वस्तुओं का मूल्य १९४२ में जान बूझ कर कम रखा गया। १९४३ में अर्थात् लड़ाई शुरू होने के ३ वर्ष के बाद, मूल्य को बढ़ाया गया। किन्तु मूल्य बढ़ाने पर भी कृषि की आमदनी में केवल ३ प्रतिशत की ही वृद्धि हो पाई है। निम्नलिखित वारिका इस बात को स्पष्ट करती है :—

१९३९—४० १९४२—४३

कृषि आय. करोड़ रुपये में:	९५२७	१७४०२
प्रति व्यक्ति कृषि आय: रुपये में:	४९	८३
कुल आय	१९९४३	२३७३४
कुल आय में कृषि आय का प्रतिशत	४९	६३

३ प्रतिशत की छोटी आय-वृद्धि भी भारतीय पञ्जीपतियों को बर्हा-
स्त नहीं। कृषि जग्य वस्तुओं का मूल्य घटाने की मयकर सानिधे चल

किसानों की समस्याएँ

रही है। गांव, उपनिवेश की तरह, पूँजीपतियों की वृद्धि और शोषण का विशाल क्षेत्र है। इसके बिना उनकी आय दर उंची रह ही नहीं सकती।

इसके अतिरिक्त अगर ४० लाख टन गन्ना बाजार से निकाल कर ४० प्रतिशत अनुत्पादक तबके में बांट दिया जाय, तो बाकी ६० प्रतिशत अनुत्पादक समूह को चोरबाजारी में अनाज खरीदने की प्रतियोगिता करनी होगी, जिससे महले का दाम बढ़ ही जायगा। फिर ४० लाख टन अनाज का मूल्य अगर ९० प्रतिशत की दर से दिया जाय, तो बाकी १० से ६० लाख टन, जो किसानों के पास बच जाता है उसे यह साधारण दाम से ९० प्रतिशत अधिक मूल्य पर बेचेंगे ही। अतः इस प्रकार की गन्ना बखली से, जो हकीकत में गन्ना जती है, दामों की वृद्धि होती है।

ऐसा करना निर्मम और अन्यायपूर्ण है। जब तक किसानों की आवश्यकता की चीजें उन्हें उरी अनुपात में सस्ते दाम पर देने की व्यवस्था नहीं की जाती है, तब तक उनसे सस्ते दाम पर गन्ना लेने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। खेतिहर तथा औद्योगिक वस्तुओं के मूल्य में एक न्यायसंगत समतुलन कायम करना सर्वथा उचित है। अब तक इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण किसानों के लिये अधिक गन्ना पैदा करने में कोई दित्तचस्ती नहीं रह गई है। उत्पादन के नीचे गिरने के अनेक कारणों में, यह भी एक कारण रहा है।

ज्वरन गन्ना जती के कारण किसानों को कितना नुकसान हुआ है, इसका ठीक ठीक अनुमान लगाना कठिन है, लेकिन मोटे तौर पर हर ६० लाख टन पर २ करोड़ रुपये का घाटा किसानों को सहना पड़ा है। इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि किसान इस घाटे की पूर्ति खुले बाजार में गन्ना बेच कर कर लेता है। हाँ, यह घाटा अवश्य पूरा कर लिया जाता है, लेकिन किसानों के उरी तबके इनाम नहीं। गन्ना बखली की नीति ऐसी है कि इसका मुख्य बोझ गरीब तबके पर पड़ा है और जो

लाम होता है वह घनी बर्ग की जेब में जाता है। मुझे आज भी एजरापाने के उस गरीब किसान की कहानी अच्छी तरह याद है, जिसके पास १० एकड़ जमीन थी और जिसे फी एकड़ २ मन के हिसाब से २० मन बाजरा ७ रुपये मन की दर से सरकारको देनेका हुक्म हुआ था। लेकिन उस गरीब के पास कुल ४ या ५ मन बाजरा था। बाजार में बाजरे की कीमत १४ रुपया मन थी। उस गरीब के पास पैसे नहीं थे। उसने अपने लड़के को एक सेठ के पास २०० ६० में नौकर के रूप में गिरवी रख कर बाजार में बाजरा खरीद कर सरकारी अफसरों के हुक्म की तामिज की। उसने फिर धनाज नहीं पैदा करने की कसम खाई। बहुत किसानों ने इसी प्रकार की कसमें ली है।

इस तरह की गल्ला-बसुली से स्वयं उसके उद्देश्य पर ही कुठार-पात होता है। इसके अलावा १५ से २० लाख गल्ले के व्यापारियों का र्घधा इसके चलते मारा गया है। इस घाटे की पूर्ति वे हर सम्भव उपाय से करना चाहते हैं। या तो उनकी जीविका का प्रपन्ध किया जाना चाहिये या उन्हें अपना कारबार बन्द करने की आशा मुना दी जानी चाहिये। गल्ला बसुली तभी सफल हो सकती है, जब कि गल्ले का उचित मूल्य दिया जाय, सभी प्रकार के गल्ले का व्यक्तिगत व्यापार बन्द कर दिया जाय तथा १६ अग्रेस के हिसाब से १५ बालिंग अनुसूचक-तबके के लोगों को राशन देने की व्यवस्था की जाय।

अतः खेती की पैदावार के क्षेत्र में हमारा लक्ष्य होना चाहिये; १. औद्योगिक कच्चे मालों की आयात को कम करना २. गल्ले के आयात को बन्द करना ३. परिमाण और गुण दोनों दृष्टियों से खाद्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाना और ४. तीन करोड़ पच्चीस लाख टन गल्ले का स्टॉक (जो महीनेकी खुराकके रूपमें) जमा रखना। मैं इस समस्या के हलके लिये निम्नलिखित सुझाव दिशा-निर्देशनके तौर पर, देना चाहता हूँ।

किसानों की समस्याएं

उत्पादन के लिये—

१. ग्राम पंचायतों द्वारा साधारण सिंचाई की व्यवस्था करनी, २. स्वयंसेव की आधार पर सरकार द्वारा प्रस्तुत योजना के मुताबिक छोटी छोटी सिंचाई योजना को पूरा करना ३ जटिल सिंचाई योजना से सरकार तथा जनता के पारस्परिक सहयोग द्वारा पूरा करना ४. बड़ी बड़ी योजनाओं की स्वतंत्र संगठनों द्वारा पूरा करना ५. सामान के रूप में आवश्यकता के मुताबिक कर्ज देना । ६. १० करोड़ एकड़ नई जमीन खेतिहर पलटन द्वारा खेती के अन्दर लाना और कुल ३५ करोड़ एकड़ जमीन को अधिक न्यायसंगत एवं आयोजित ढंग पर उपयोग में लाना ७. खाद तैयार करने के लिये सक्रिय आन्दोलन चलाना । ८. सभी प्रकार की बेदखली बन्द करना तथा उचित लगान निर्धारित करना ९. ग्राम पंचायतों को गैर आबाद जमीन को आबाद करने का अधिकार देना ।

क्षयशक्ति पैदा करने के लिये—

१०. सहायक उद्योग ११. चावल मिलों की बढ़ती पर रोक और टेकुल द्वारा चावल छोटने की पद्धति पर जोर १२. हर गाँव में सूखे महीनों में गरीबों को सस्ते दर पर 'कर्ज' देने के लिये गल्ला बैंक की स्थापना ।

बँटवारे के लिये—

१३. आवश्यक पदार्थों में सभी प्रकार के व्यक्तिगत व्यापार का दाय १४. घास या बचत का लेखा—जोखा लगाने के लिये गाँव को इकाई मानना १५. सभी अनुत्पादक तबक के लोगों को प्रति दिन १६ औंस के दिसाब से अनाज की व्यवस्था करना १६. गल्ले का भंडार बनाना १७. गाँव की आवश्यकता की चीजों को कट्टोस दर पर गाँव की जनता को देने की व्यवस्था १८. संसार के विभिन्न केन्द्रों में गल्ला का स्टॉक जमा रखना ।

मूल्य के लिये—

१९. खेतिहर और औद्योगिक वस्तुओं के दामों में संतुलन रखते हुए सभी आवश्यक पद्यों की कीमत कम करना २०. सरकार सभी बालिग भ्रमजावियों को, चाहे वह काम पर हो या बेकार, अन्न की गारंटी दे।

जनसंख्या की वृद्धि पर रोक—

२१. सन्तति निग्रह का पूरे जोर से प्रचार २२. देश के अन्दर आबादी का परिवर्तन।

भारत सरकार ऐसा साहस पूर्ण कदम नहीं उठा सकती। स्थिर स्वार्थ वर्ग के साथ सरकार के सूत्रधारों का जो गठबन्धन हो गया है उसके फलस्वरूप वे इनके वर्ग स्वार्थों के खिलाफ कोई कदम उठा भी कैसे सकते हैं। फलतः इस गरुला - बसली के शिकार गाँव के गरीब ही होने वाले हैं। इसलिये जैसा कि मैंने ऊपर कहा है, दिल्ली-निर्णय ब्य-वहारिक रूप में भी सफल नहीं होगा। स्थिर स्वार्थ वर्ग की स्थिति काफ़ी सुदृढ़ है। मि० फजलुल हक को भी १९४३ में इनके हाथों से अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी थी। हमारे माननीय मंत्रियों को शायद यह हार स्वीकार करने का साहस न हो, लेकिन अन्न समस्या को उत्तरोत्तर गंभीर बनती ही जायगी। किसी वर्ष बिहार, हैदराबाद और मद्रास भर्यकर अन्न संकट से गुजरेंगे तो किसी वर्ष अन्य राज्य। लगातार के घाटे का “परिमाण” अब “गुण” में परिवर्तित होकर देश की भयानक अकाल की ओर ले जा रहा है।

क्या जनता भूख से तड़प तड़प कर मरने के लिये तैयार है।
-क्या इस अन्न संकट से बचने का कोई रास्ता शेष नहीं रह गया है।
हां, एक रास्ता है, जहाँ सरकार हार जाती है, वहाँ जनता आगे बढ़ कर जिम्मेदारी सम्भालती है। जनता के सामने एक ही रास्ता है और वह है अन्तिकारी नवनिर्माण का।

वनवासी

इतिहास की गति ने अनेक कबीलों एवं जन समुदायों को अपने ही घेर घरीके से रहने के लिये पीछे छोड़ दिया है। हजारों वर्ष पूर्व प्राचीन-समाज व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर शहर और गाँव की उत्पत्ति हुई। फिर भी अलंघ्य पर्वतों एवं बौद्ध वानों में कुछ टुकड़ियाँ जंगली पशुओं के साथ संघर्ष और प्राकृतिक लय-ताल पर नृत्य करती रह गईं। वैज्ञानिक उत्पत्ति के परिणाम-स्वरूप आवागमन के साधनों में प्रगति होने के कारण, ऐसे स्थान में उन लोगों की पहुँच आसानी से हो गई, जो जनसंख्या की वृद्धि के कारण, नये खेतों और आरगाहों की खोज में थे। भेड़ इधियाँ तथा उच्चतर साधनों से लैस इन नवागन्तुओं के सामने, वे आदिवासी टिक न सके और उन्होंने घनघोर जंगलों एवं गहन पर्वतों की शरण ली। नवीन व्यक्तिवादी समाज-व्यवस्था के अनुकूल अपने को बनाने में वे न समर्थ ॥ होसके और न जंगलों तथा पर्वतों में शिकार करना और नाच गान में लीन रहना ही छोड़ सके।

अठारहवीं शताब्दी में और खास तौर पर १९ वीं शताब्दी के

आरम्भ काल में यातायात के विकास ने, जब इन बनवासियों के भी सम्पर्क में नवागन्तुकों को लाया, तब से नई दुनिया के सामने व्यापक बन-वासी एक समस्या के रूप में रहे हैं। इस समस्या के हल का दृष्टिकोण अविवादी रहा है। एक ओर तो उनके सर्वथा विनाश की बात कही गई और दूसरी ओर मानव-विज्ञान के अध्ययन के लिये उन्हें अजायबघर के नमूने बना देने की सलाह दी गई। आज की दुनिया बनवासियों के साथ निर्जीव पदार्थ का बर्ताव कर, अपने सर पर महान पाप दो रही है। परन्तु इनके बड़े-बड़े दोस्त और सहायक भी कोई सही हल नहीं ढूँढ़ सके। चाहे उन्हें ईसाई बना लीजिये, चाहे उनकी समाज-व्यवस्था को तोड़ कर इस समाज में घसीट लाइये, उन प्रताड़ित जंगली कबीलों को इससे कोई भी सुख-संतोष नहीं मिलने को है। भी बेरियर एलबिन ने इस पर खेद प्रकट किया है कि किस तरह सया कथित नयी संस्कृति उन्हें हेष बना रही है। उनका कहना है.....

“एक नया जंगली सुरिया या उरावि बालक जब परले-परल हमारे बीच आता है, तो कितना सुन्दर दीखता है, लम्बे-लम्बे गुंथाले लट, गले में लटकता हुआ कंठा और गुंथे बालों पर पंख एवं फूल। लेकिन स्कूल शिक्षक उनके बालों से फूल और पंख छलम कर देते हैं, उनके बिछरे लटों को काट डालते हैं और उनके आभूषणों पर पश्चिमियाँ कसते हैं। सुन्दर पगड़ी के बदले छोटी गोला बोपी सर पर विराजमान हो जाती है और उनके भूरे शरीर पर नैसर्गिक एवं शाश्वत नम्रसौन्दर्य पर आवरण डालने वाली प्लास्टी कमीक और कोट विराजमान हो जाते हैं। नृत्य के स्थान पर ड्रामा, और सुन्दर तथा अकल्प “रैलों” के बदले होली की अदलीशवा आ पानी है।”

फिर भी इस देश में उनके अन्यतम मित्रों में से एक भी बेरियर एलबिन भी कोई हल नहीं ढूँढ़ सके। आधुनिक आदिवासी के सबसे

किसानों की समस्याएँ

सुन्दर उदाहरण के रूप में, उन्हें सारनगढ़ के गोंड राजा मिले। पर दुःख की बात तो यह है कि एक साधारण आदिवासी के लिये गोंड राजा होना संभव नहीं।

स्वर्गीय श्री ठक्करबापा [जिसे सन्ने और कर्मठ-व्यक्ति भी उनके लिये समाज-सेवा की योजना का सुझाव देने के सिवा और कुछ नहीं कर सके। इसके अलावा उनको हिन्दू-धर्म के अन्दर रखने की बाधुकता ने उनकी मुख्य-ध्वनि से दूर रखा। इसी तरह ईसाई मिशनरियों की भाव-नायें भले ही अच्छी रही हों और उनकी अग्रान्त आत्माओं को कुछ हद तक शान्ति भी मिली हो, पर उनके कार्यों से आदिवासियों का दुःख बढ़ बढ़ा ही है। इन सभी शुभाविवतों को वास्तविक रूप इसलिये नहीं मिल सका कि वे व्यक्तिवादी समाज के दायरे में इसका हल ढूँढ़ते थे, जहाँ इसका कोई हल ही नहीं है। जबतक इस आधारभूत तथ्य का, कि वे आदिम समाज व्यवस्था के अवशिष्ट अंग हैं, ग्रहण नहीं किया जाता और उसपर अमल नहीं होता, जबतक कोई हल मिल नहीं सकता। [इस हजार वर्षों से अपनी सामाजिक-व्यवस्था की व्यक्तिवादी समाज के आक्रमणों से बचाने के लिये वे सघर्ष करते आये हैं। न तो उच्चविशाल शहरों के प्रलोभन और न नवानातुकों की गोलियाँ ही उन्हें अपनी सामाजिक व्यवस्था से अलग कर सही।

श्री बेरियर एलगिन ने आदिवासियों के जीवन के इस मुख्य तथ्य की मान्यता दी है। उनका कहना है—

“आर्थिक सहयोग की भावना और सामूहिक जीवन की परम्परा के विचार की दृष्टि से उनके प्राचीनतम गाँव आधुनिक दुनियाँ से सेकड़ों वर्ष आगे है। जंगली लोगों का वह सामूहिक जीवन देखने में बहुत ही सुन्दर है—जिसमें हरेक वस्तु के भागी सभी हैं और जिसमें एक का सुख-दुख समूह का सुख-दुख है। परन्तु आधुनिक शिक्षा और विकास की

शीत वायु का स्पर्श होते ही उनका यह सौन्दर्य समाप्त हो जाता है और उनके स्वाभाविक गुण ; जैसे सरलता, ईमानदारी, स्पष्टवादिता और विनोद प्रियता आदि भी विनष्ट हो जाते हैं ।”

फिर भी पलायनवाद और पूर्व निश्चित धारणा ने ही, श्री बेरिय एलविन को इस तर्कसंगत हल तक पहुँचने से रोका है कि आदिवासियों को प्राचीन समाजवादी व्यवस्था से ऊपर उठा कर आधुनिक समाजवादी व्यवस्था में लाया जाय । वही पूर्व निश्चित धारणा और पलायनवाद की भावना बनवासियों के अन्य शुभचिंतकों को इस तर्कसंगत मानवीय और स्वाभाविक हल तक पहुँचने से मयमीत कर रही है । यदि इसकी स्वीकार नहीं किया गया, तो ये बनवासी आधुनिकता के “दुश्मन” की भाँति समूल नष्ट हो जायेंगे या उत्तरी अमेरिका के “रेड इण्डियन्स” की भाँति अजायब घर के नमूने के तौर पर रहेंगे या इस देश के संथाल, मील और मुँडा लोगों की भाँति समाज में सबसे पिछड़े रहेंगे ।

पिछले तीन सौ वर्षों से इनकी हालत इस देश में बराबर बिगड़ती ही जा रही है । इनका जीवन सुख-दुख का एक अजीब मिश्रण है । श्री एलविन के शब्दों में—

“वर्ष भर त्योहारों, विवाह और नृत्यपर्यटनों से जीवन उत्फुल्ल रहता है । लकड़ों और लकड़ियों एक ओर बालों में फूल और आम्रपत्र लगाकर खुरीसे नाचके लिए इकट्ठे होती हैं और दूसरी ओर उनके दुजुर्ग देवी-देवताओं की आराधना में लग जाते हैं । विवाह-समारोह तो एक प्रकार से बनमोहन की तरह ही आनन्ददायक होते हैं । अतिथियों के लिये एक खुसा घर रहता है, जहाँ सैकड़ों लोग भोज और नाच में सम्मिलित होने के किये जंगलों में इकट्ठे होते हैं । यह आश्चर्य की बात है कि इतने कम खर्च में इतने अधिक आनन्द और उत्साह की प्राप्ति होती है । कभी कभी अविवाहित युवक एक जगह से दूसरी प्रेयसी की खोज में नृत्य

पर्यटन करते हैं। कभी कभी लड़कियाँ भी प्रियतम की खोज में इसी तरह निकलती हैं।”

“फिर भी यह आनन्द कष्टों और अभाव के कारण नष्टप्राय होता जा रहा है। आदिवासियों को प्रकृति और बीमारी से निरन्तर संघर्ष करना पड़ता है, हर एक रात मच्छर मृत्यु से भी भयानक यन्त्रणा लिये आते हैं। सदियों से गाँवों में रात को घनचोर अन्धेरा छाया रहता है, क्योंकि उनमें दीयों के लिये तेल खरीदने का सामर्थ्य नहीं है। उनके लिये सर्वदा ‘राशनिंग’ की ही स्थिति रहती है, क्योंकि हर एक को खाद्यान्न का अभाव रहता है। उनकी आबादी पर बाहरी कानूनों द्वारा प्रतिबन्ध लगा रहता है। कुछ ही क्षण में आसमान की हरकत फसल को नष्ट कर दे सकती है और महीनों के काम को मिट्टी में मिला दे सकती है। दुर्घटना या बीमारी से जीवन का अन्त असमय ही हो जाता है। यद्यपि इस विनाश में युद्ध से कम विभीषिका रहती है, किन्तु अनिश्चितता ही उसनी रहती है।”

आखिर उन्हें समाजवाद के लक्ष्य तक पहुँचना ही है। फिर इसकी क्या आवश्यकता है कि उनकी सामाजिक व्यवस्था को तोड़ कर व्यक्ति-वादी समाज की स्थापना की जाय और तब उन्हें समाजवाद के पथ पर लाया जाय। सोवियत रूस उत्तरी अमरीकन द्वीप के आदिवासियों को प्राचीन समाजवाद से आधुनिक समाजवाद के पथ पर लाने का जो प्रयोग कर रहा है, वह विशेष ध्यान और अध्ययन के योग्य है।

पिछले दो सौ वर्षों से आदिवासियों के प्रति इस देश में विभिन्न सरकारों का व्यवहार हृदयहीन और उत्पीड़क रहा है। इस बात का ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक है कि उनके जीवन का जंगलों से बहुत ही घनिष्ठ सम्पर्क है। इसलिये जंगलों से सम्बन्ध रखनेवाली नीति आदिवासी-नीति के अनुरूप ही होनी चाहिये। इस दूसरी बुनियादी तथ्य को

हिंसा की समस्याएँ

शासकों ने कभी भी स्वीकार नहीं किया। वास्तविकता यह है कि इन मानव-आत्माओं की रक्षा की अपेक्षा कंगलों की सुरक्षा की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। राजनीतिक दृष्टि से अंगरेजी सरकार उनको अलग क्षेत्रों में बनाये रखने से अधिक सोच भी नहीं रखी। उन पहाड़ी जातियों के जीवन और उनकी सम्पत्ति को संक्रमक समझ कर बाहरी दुनिया से उनका कानूनी अलगगढ़ रखा। विशेष रूप से उन्हें सुरक्षित रखने की इस नीति ने उन्हें राष्ट्रिय आन्दोलन से भी अलग कर दिया।

स्वभावतः ही इस नीति का राष्ट्रिय-नेताओं ने विरोध किया। श्री चर्चिल के इस प्रसिद्ध कथन का, कि "समूचे हिन्दुस्तान को यदि पृथक क्षेत्र बना कर रखा जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं" वाले देश ने एक स्वर से विरोध किया। फिर भी संकीर्ण-विचारों से प्रभावित अंग्रेजी सरकार के लिये आदिवासियों के विरोध अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिये कोई चारा नहीं था। बाहर लोग बायबल या नाजायज तरीकों से आदिवासी क्षेत्रों में घुस कर उन्हें जमीन और कंगल से बेदखल कर रहे थे। कास्वकारी कानूनों के जरिये बाहरी लोगों पर, जमीन सम्बन्धी प्रतिवन्ध लगा कर और दूसरे सुरक्षात्मक कानूनों के द्वारा, बाहर के शोमी महाजनों से कुछ दूरतक ठंकी रखा हुई।

फिर भी यह न ठी कोई रस था और न कारगर सुरक्षा ही। उसने एक हाथ से जो कुछ दिया दूसरे हाथ से कंगल-सुरक्षा-कानून के द्वारा छेड़िया और बनवासियों के मुल का अंत सदा के लिये हो गया। योके से उन-गोनों को छोड़ कर जो "भूम" खेती करने के आदि हैं, समी, कंगल-सुरक्षा-कानूनों का श्रुति करते यदि उसकी मुनिवाद ठोस सिद्धान्त पर आभित और मानवीय विचारों से प्रेरित होती। एक ओर आदिवासी अपने अधिकार खोते गये और दूसरी ओर ठेकेदार और आसानीदार मरह खजा करते गये, एवं करोड़ों रुपये उन की

विधोरियों में समाते गये ।

आजादी के प्रभाव ने जनवासियों की भोपकियों में प्रकाश लाने के बदले उनके कष्टों और मुसीबतों को और भी बढ़ा दिया । माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय उनके वास्तविक और कानूनी अधिकारों को, प्रतिपूर्ति किये बिना ही, छीन कर विदेशी शासकों से भी एक कदम आगे बढ़ गये हैं । इस सम्बन्ध में कुछ और कहने के पहले हम विभिन्न प्रान्तों के आदिवासियों और जंगलों का एक पूरा चित्र अपने सामने रखें ।

निम्नलिखित आंकड़े विभिन्न प्रान्तों में १९४१ की जनगणना के अनुसार आदिवासियों की जनसंख्या दिखाते हैं ।

क्रम संख्या	राज्य	आदिवासियों की जनसंख्या हजार में	कुलजनसंख्या प्रतिशत
१	बम्बई	२२,७०	७
२	मध्य प्रदेश	३७,१०	२०
३	मद्रास	५,९०	१०
४	मैसूर	१०	
५	ट्रावणकोर	१,९०	२
६	हैदराबाद	९,८०	४
७	मोपास	७१	९
८	आसाम	२८,२५	२२
९	बंगाल	१६,२५	१
१०	बिहार	६१,९५	१६
११	उड़ीसा	३२,११	२४
१२	उत्तर प्रदेश	२,९८	२४

किताबों की समस्याएँ

	जंगलों का क्षेत्र		वर्गमील में
	क्षेत्र-पूरा	जंगल क्षेत्र	जंगल के प्रतिशत
अजमेर	२,३६७	५९३	२५,१
अन्धमन	२,५००	२,५००	१००,०
आसाम	५५,४४५	२१,६३७	३९,०
बिहार	६९,७४५	९,९४७	१४,०
बम्बई	७६,०२६	१२,८७२	१६,९
मध्यप्रदेश	९८,५७३	४७,०५७	४७,७
पंजाब	३८,७८०	४,७६१	१२,३
मद्रास	१,२५,१६३	३३,६६६	२६,९
उड़ीसा	३२,६९५	४,४९२	१३,७
उत्तरप्रदेश	१,०६,२४८	१७,३७२	१६,४
पश्चिम बंगाल	२८,२१५	४,२८४	१५,२
कुर्ग	१,५८२	१,१७५	७४,१

एक सरसरी नज़र डालने से ही स्पष्ट हो जायगा कि आदिवासियों का जीवन जंगल से कितना जुड़ा हुआ है और कितनी बड़ी सम्पत्ति उनके पास है। इस देश के तीन करोड़ आदिवासियों का जीवन जंगलों की पैदावार से मुली और सम्पन्न बनाया जा सकता है। राष्ट्रिय हित के लिये सुरक्षा की नीति आसानी से बनाया सियों को संतुष्ट रखने हुए निर्धारित की जा सकती है। जंगलों की सुरक्षा और वनवासियों के कल्याण के बीच द्वन्द्व नहीं, बल्कि वास्तव में ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कांग्रेसी मन्त्रियों की अश्रमवादी नीति ने ही इस द्वन्द्व का सृजन किया है।

सकड़ी जंगलके बनकर एक ह्योय सा अग है। पेड़ों की दिस्रजत के साथ, वनवासियों के हित में जंगली पैदावारों के वैज्ञानिक उपयोग,

उनकी आर्थिक कठिनाइयों को आसानी से श्रंत कर सकते हैं। अगर हम १८७८ के पहले जंगल कानून को देखेंगे, जो अब भी कांग्रेसी मंत्रियों का प्रवचन है, तो पता चलेगा कि बनवासियों के लिये कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। जंगली पैदावार की परिभाषा, कानून की दूसरी धारा में, इस प्रकार है :—

“धारा २, अनुच्छेद ४—जंगल की पैदावार के अन्तर्गत लकड़ी कोयला, काँचू, रेंचू, लकड़ी के तेल, रासन, प्राकृतिक वार्निश, छाल, लाह, महुआ के फूल और बीज, मीराकलास पेड़ पत्ते, ‘‘फूल फल’ आदि हैं, तथा ऐसे भी पौधे, जिन्हें वृक्ष नहीं कहा जा सकता जैसे घास, लत्ती, काई आदि। तथा इन पौधों के अन्य भाग तथा जंगली जानवर, चमड़े, हाथी दाँत, सीप, हड्डियाँ, रेशम, चर्बी, मधु आदि; पर्यर, खनिज पदार्थ, चूने के पर्यर, तेल और खानों की दूसरी पैदावार भी इसमें आते हैं।”

मूलतः यह कि खनिज पदार्थ और पेड़ों से लेकर गोबर तक सुरक्षा के दायरे में आजाते हैं। उनकी तकलीफों, दुर्गति तथा पतन के लिये कांग्रेसी मंत्रियों की यही आत्मघाती नीति, जो बदला लेने की भावना से प्रेरित होकर लागू की गई है, उत्तरदायी है। परम्परा तथा नैतिका के दृष्टिकोण से जंगल और जंगलों की पैदावार के मालिक बनवासी ही हैं। जब तक इस दूसरे बुनियादी तथ्य को मान कर इसके ही आधार-पर नीतियों का निर्धारण नहीं किया जायगा तब तक न तो जंगलों की रक्षा होगी और न बनवासियों की प्रगति।

कांग्रेसी मंत्रियों ने कहाँ एक ओर जंगलों और उनकी पैदावारों पर से बनवासियों के अधिकार छीन लिये हैं, वहाँ दूसरी ओर उत्पादन और व्यापार के अधिकार पूँजीपति ठेकेदारों दे दिये हैं। क्या कारण है कि कांग्रेसी सरकारों ने सहयोग समितियों का निर्माण कर जंगली पैदावारों का उत्पादन और व्यापार के अधिकार इनके या आदिवासियों के हनाले नहीं किया? स्मरण रहे कि उसके लिये बहुत कम पूँजी की आवश्यकता है। कुछ

योग्य व्यवस्थाओं की सहजता से कांटेसी सरकारें बनवावियों क
करोड़ों का काम कर सकती थीं ।

बनवावियों के शुभचिन्तकों को इस तीव्रगी बुनियादी तथ्य को
समझना अत्यावश्यक है कि वे कुछ बातों में समाज के अन्य श्रेणों से
भागे हैं नहीं बल्कि भेदुर हैं । उनकी समूह भावना और नृत्य एवं संगीत
में एक ऐसी उपयोगी वस्तु है जिसकी रक्षा तथा विसे विकसित करना
आवश्यक है । रांची के जूलियस यिंगा आदिवासी लड़के तथा लड़कियों
को उनकी प्राचीन संस्था "युनकडिया" के आधार पर शिक्षा देने का
प्रयोग कर रहे हैं । उनमें परिमार्जन एवं प्रगति लाने की आवश्यकता
है । किन्तु यह एक राष्ट्रिय दुर्भाग्य होगा, यदि उन्हें उन चीजों को परि-
त्याग करने को बाध्य किया गया जिनको रक्षा उन्होंने हजारों वर्षों के
समय संघर्ष के दरम्यान की है ।

यद्यपि एक बार इन तीन बुनियादी तथ्यों को, कि (क) वे
प्राचीनतम समाजवादी समाज के अवशिष्ट हैं और उन्हें छोड़े समाजवाद
के पथ पर लाया जा सकता है, (ख) वंगल और उसकी पैदावार पर
उनका परम्परागत तथा नैतिक अधिकार है और (ग) कुछ बातों में वे
हमारे व्यक्तिवादी समाज से भेदुर हैं; स्वीकार कर लिया जाय है, तो उन्हें
इच्छित लक्ष्य तक द्रुत गति से ले जाने में कोई, कठिनाई नहीं होगी,
और पहाड़ियों तथा वंगल ऐसे समाजिक क्षेत्र बन जायेंगे जहाँ प्राचीन
समाजवादी व्यवस्था के साथ आधुनिक औद्योगिक का सम्मिश्रण होगा ।
प्रकृति ने इन आदिवासियों को मुक्त हस्त हो घन और सोम्य देने हैं ।
लेकिन हमारी विचारधरा तथा भावनातेजस्वि मानवोंने इन अपूर्व स्वर्गों
को नरक दुन्य बना दिया है । इस देश के तीन करोड़ बनवावियों के
जीवन में आनन्द एवं मुक्त लाने के लिये आधुनिक समाजवाद के आधार
पर शरु को फिर से सुनाया जा सद्य है ।

वरार; साहुकारों का स्वर्ग

वरार भारत का केन्द्र-स्थल है। विगत शताब्दियों के इतिहास के सिंहावलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि वरार सदा से दुस्साहस, पदयंत्र और संघर्ष का केन्द्र रहा है। उसने साढ़े तीन सौ वर्षों की लम्बी जिन्दगी में शान्ति की छाया तक नहीं देखी। दक्षिणी-सामन्त १६ वीं शताब्दी में वरार पर अधिकार के लिये परस्पर युद्ध में जूझते रहे जब तक सम्पूर्ण वरार बादशाह अकबर के चरणों में १५९६ में समर्पित न कर दिया गया। सत्रहवीं शताब्दी में मुगल शासकों की बारी आई, परन्तु मुगल सल्तनत के दहते ही निजाम ने वरार पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। मराठों ने भी उस पर “चौथ और सरदेशमुखी” का दावा किया। दोनों ने अपने अपने जागीरदार बहाल किये। दोनों ओर से राज कर का दावा किया गया, जबरिया कर-बसुली प्रारम्भ हो गई। परिणाम स्वरूप किसान तंग हो खेतों को छोड़ पड़ोसियों के लूट-खसोट में लग गये।

यह दुर्दशा १८०३ ई० तक होती रही और तब तक ब्रिटिश हुकूमत ने पूरे वरार को निजाम के जिम्मे लगा दिया। किन्तु हैदराबाद दरबार के

किस्तानों की समस्याएं

मनमाने खर्च ने निजाम की कर्ज से बोझिल कर दिया और कर्ज चुमाने की विधि यह रही कि बरार के अधिकांश जिले कर्जदारों को खेतों के लिये मुफ्त दिये जाने लगे। इस तरह बरार अनेक लोभियों का केन्द्र बिन्दु बन गया। हैदराबाद के मशहूर सूफ़ी और पूरनमल तथा पारसी-कम्पनी पेस्टनजी ऐन्ड को० निजाम के नाम पर बहुत दिनों तक बरार के अधिपति बने रहे उन कर्जदारों को खेती से क्या वास्ता? उन्हें तो धन चाहिये था। धन लूटने की प्रतियोगिता पूरे बरार में चलती रही। जय चकला का चकला खेत परती रहने लगा, तब देशमुखों ने भागे हुए खेतिहरों को शासन के बल वापस लाने की कोशिश की। १८३५ में गांव गांव के खाली हो गये, अधिकांश खेत परती पड़ गये। १८६७ में केवल बर्गी जिले में ही ४३६ गांव वीरान हो चुके थे और २० लाख एकड़ जमीन परती रह गई थी। १८६७ में "परती भूमि कानून" के आधार पर "इजारा कानून" बना और जमीन का पुनः आगद करनेवालों को विशेष सहुलियतें दी जाने लगी।

भारतीय काश्तकारी पद्धति के विख्यात लेखक भी बेडेन पावेल ने अपनी पुस्तक में लिखा है—

"जय से नरार दो मालिकों के (निजाम और मराठे) के बीच आया तब से सभी स्थायी हट सतम कर दिये गये, या या कहिये कि नरार की जनता की कमर टूट गई। फिर मराठा का आधिपत्य स्थापित हुआ और उन्होंने मालगुजारी देनेवालों का तो ख्याल किया, किन्तु भगदालू जमीने ज्यों की त्यों पड़ी रह गई। लग्नी लड़ाइयों के बीच दाना सरकारें निर्भन बन गई और वे ज्यादा से ज्यादा मालगुजारी वसूलने में जुक्त पड़ीं। १८०३ में एक ही सरकार बच रही। पुराने कलहाका तो अन्न हो गया, किन्तु नई-नई समस्याएँ उठ खड़ी हुईं। देश थक गया था और जासक्या पगें हुई थी। कुछदिन बादही एक भयानक अराल पड़ा। पचास वर्ष बाद, जय हमने प्रान्त को अपने हाथ में लिया, तो कर बटुनी की जिम्मेदारी उन दिवान

मुखियाओं दे दी गई, जिन्होंने नन्द रुपये दिये थे। सालाना बन्दोस्ती तो की गई, परन्तु पहले से ज्यादा चढ़ी हुई मालगुजारी के दरपर। जिस किसान ने अपने खेतों को सुन्दर बनाया और अच्छी फसल उगाई उन्हें इसे सबसे बड़े इनामदार के यहाँ बेचना पड़ा। सम्पूर्ण ताल्लुका और परगना व्यवसायों के हाथ नरुद रुपये में बन्दोस्त कर दिये गये। ऐसी आर्थिक हालत में भूमि की पूरी उपज पर में ही भुगतान होती होगी।”

इस व्यवस्था का अन्त १८५३ में हुआ, जबकि अंग्रेजों के हाथ में शासनसूत्र आया, परन्तु निजाम का कानूनी आधिपत्य तब तक कायम था। इतिहासज्ञ ने तीन शताब्दी के इस काल को “दो अमली” कहा है। इस काल में नरार की जनता दो विरोधी राज शक्तियों की चक्की में पिसकर निल्कुल नरुद हो गई। अंग्रेजों का कहना है कि उन्होंने नरार को निजाम से छूटी हुई नारगी की हालत में पाया। किन्तु, क्या उन्होंने नरारकी हालत में थोड़ा भी सुधार किया। १९ वीं शताब्दी के आरंभ में, बहुत से ऐसे व्यक्ति थे, जो पहले के डबाडोल और कुत्र्यस्थित शासन को ही पसन्द करते थे। अंग्रेजी-राज में इस स्थिति में बहुत कुछ सुधार हुआ। तलवार की जगह, स्लाम्पदार कागजा और कचहरियों ने ली। एक शताब्दी के अंग्रेजी राज में ही सारा नरार साहूकारों का स्वर्ग बन गया।

नरार गजेठियर ने १९१० में लिखा —

“मारवाडी जो रुई तथा गल्ले के रोजगार में धनी बनकर प्रधानतः सूद पर रुपये लूटता करते हैं, गांव गांव में भरे पड़े हैं। पिछले पचास वर्षों में इन, क्रूर मूदखोरों ने पूरी रैयतवारी प्रथा को तोड़-मरोड़ कर अंग्रेजी नरार का हजम कर लिया।” असहाय जनता के जीवन में छल प्रपञ्च की यह दर्दमयी पार्श्विक कहानी सरकारी गजेठियर से ही साफ हो जाती है।

एक अनुमति अधिकारी ने कहा है कि गल्ले के व्यापारियों ने अकाल उत्पन्न करने के लिए वर्षा नन्द कराने का एक विचित्र उपाय ढूँढ निकाला

किसानों की समस्याएँ

या। “प्रसव-शीटसे मृत किसी स्त्री की हड्डी से एक चूखों बनाया गया और उसको एक बूढ़ी विधवा के द्वारा एक सूने सोते के किनारे सूर्य के सन्मुख चलाया गया।”

यूटिश संसद ने बरार को ऐसे ही हृदयहीन सुदखों के सुपुर्द किया। बरार की भूमि नदियों की लाई हुई अत्यधिक उपजाऊ, मिट्टी से बनी है। इसका क्षेत्रफल १७७८० वर्गमील है और इसकी आबादी ३ करोड़ है। इतनी बड़ी भूमि और इतनी विशाल आबादी निर्दयी साहूकारों के चरणों में लोट रही है। इसकी गरीबी का कारण न तो इसकी मिट्टी है, न इसकी आबादी (जो केवल १८० प्रति मील है) और न इसकी बर्बाद, जो ३५.२० इंच औसत है। भूमि का बर्गोकरण भी, जो नीचे दिया गया है, बलुतः गरीबी का कारण नहीं बन सकता है।

(३१ वीं मई, १९४९ को खतम होनेवाले वर्ष में आबाद भूमि के बर्गोकरण का बोध एकड़ में :—

	जिना व जोर में कुल रकबा		पर लगने-वाली जीवने सारफ परती
	फसल के अन्दर	बैरसल	
१. अन्नाला	१८०२०२	४०१९४६	७२७५
२. अमरापती	१५४४३४	२०९८१७	२४७५०
३. बुलशाना	१५४५७८०	४०७०२३	६५५१
४. मावतमाल	१७०७४७२	६२२६७३	१३९२
	६५९८८८८	१७४५१५९	४१९६८

किसानों की समस्याएं

लकड़ी, जलावन और घास भाली जमीन	जंगल के अलावा गांव के चारागाह और अन्य जमीन	सर्वे के बाहर बची जमीन	गैर आगद जमीन	कुल जोड़
१३९५६९	१९२५४४	५३०८१	१४०७४	२६०७६८३
८०३५३३	२४७३०७	५९६७७	२४३०५	३०१३७२३
१७३१२५	२१४०४६	४४१९९	२३९००	२४१४६२४
४९५१६७	३१९९६०	५७७४५	१३०६३९	३३४०७५३
१६११३९४	९७३५४७	२१४७०२	१९२९८१	११३७८५८३

क्राश्टकारी कानून के अनुसार क्षेत्रफल का विभाजन

	योगफल	क्षेत्र
खालसा	९१,७३,९५३	७३,६२,८९१
जंगल	१०,२५,५६२	३४८
इजारा	७,५१,३९३	६,५१,८०२
इनाम	४२,८०३	६,६२०
जागीर	३,६१,७५६	२,७३,४२८
पालमपेट	२१,०८५	१९,४१७
	१,१३,७६,५५१	८३,१४,५६६

खालसा में वह जमीन आती है, जो रैयतवारी प्रथा के अनुसार स्थायी रैयतों के हाथ चन्दोवस्त कर दी गई हैं। १८६७ और १८९७ के दो सर्वे में ९५ प्रतिशत जमीन जोतने वाले किसानों के पास थी। उसके बाद से ही साहूकारों के हाथ जमीन चली जा रही है। बंधक और

मिनी की तालिका गन ५० वर्षों में होनेवाली बेदखली का सही चित्र प्रदर्शित करती है।

विनी

	सख्या	एकड़	दाम
१९४५—४६	४१,२०६	२,०५,६९४	२,९४,१८,६८९
१९४६—४७	३३,२८१	१,६३,२५०	२,७५,६९,६९०

बंघक

	सख्या	कीमत
१९४४	७,९५६	२५,४४,७६२
१९४५	१३,३२,५९	४६,९४,६६९
१९४६	१४,४७३	५५,४१,६७७

इस तरह की बेदखली, मराठवाड़े के सिवा, देश के किसी अन्य हिस्से में नहीं पायी जाती है। इस केन्द्रीकरण का इलाज सरकार ही निराम सकती है। निम्न सरकार ने १९३८ में एक कमीशन गढ़ान किया निम्ने पड़ोस के मराठवाड़े में पना लगाया कि औसत २ प्रतिशत जमीन प्रतिवर्ष किसानों के हाथ से निकलती चली जा रही है। कमीशन के निरूपण के आँकड़े ये हैं—

औरंगाबाद, परमनी, नानडेर, नीर तिलों के आँकड़े —

१. बोई गना कुल जमीन	७९,४२,००० एकड़
२. बेची गई कुल जमीन १९२३, १९२७	२२,५०,००० "
३. कुल गॉन	४,८५५ "
४. १९३७ में कुल कर्ज	१५ करोड़ रुपये।

ये आँकड़े साफ बताते हैं कि किसानों के हाथ से २ प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से जमीन निकलती रही। चूँकि १९३१—३७ के वर्षों में मंदी रही, इसलिये बेदखली भी जोरों में हुई।

जमीन की ऐसी बेदखली आजादी के बाद भी जारी है। सरकारी जाँच पड़ताल के बिना यह कहना कठिन है कि कितनी रैयती जमीन साहूकारों या गैरजोतदारों के पास है। मैंने यावतमाल के निकट एक छोटी बन्ती चिमनपुर में देखा कि कुल भूमि—कर २४९ रु० १ आ० में २०६ रु० १५ आ० ६ पा० बाहर के गैरजोतदार द्वारा चुकाये जाते, ये और उनकी कुल जमीन स्थानीय रैयत बटाई पर जोता करते हैं।

मेरे अनुमान से मोटे तौर पर ५० प्रतिशत जमीन गैरजोतदार रैयतों के जिम्मे होगी। मध्यप्रदेश की एसेम्बली में प्रश्न पूछे जाने पर एक मंत्री ने बरार के सम्बन्ध में ये आरुढ़े दिये:—

श्रेणी	संख्या	कुल मालगुजारी रु० में
१. १० रु० से कम मालगुजारी देनेवाले	२,६७,८०१	२६,७८,०१०
२. १० रु० से अधिक और २५ रु० से कम देनेवाले	७६,५१२	१८,६२,८००
३. २५ रु० से अधिक और ५० रु० से कम देनेवाले	३५,४६६	१७,७३,३००
४. ५० से अधिक और १०० से— कम देनेवाले	१३,३९९	१३,३९,९००
५. १०० " " २०० " "	५,१२७	१०,२५,४००
६. २०० " " ५०० " "	१,२५५	६,२७,५००
७. ५०० " " २००० " "	४८१	९,६२,०००
८. २००० " " ३००० " "	१०२	३,०६,०००
९. ३००० " " ५००० " "	४०	२,००,०००
१०. ५००० " " १०००० " "	२७	२,७०,०००
११. १४००० " " २५००० " "	३	४२,०००
१२. २५००० रु०.....	१	२५,०००
	<u>३,९८,२१४</u>	<u>९,१९,१९,९१०</u>

फ़िस्तानों की समस्याएं

हम शोषण की मात्रा का केवल कुछ अन्दाजा लगा सकते हैं। वर्तमान बाजार-मूल्य के आधार पर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि औसत प्रति एकड़ ६०) की फसल तैयार होती है। चूंकि अभी करीब ६६ लाख एकड़ भूमि में उत्पादन होता है, बरार की फसल का कुल मूल्य ४० करोड़ रुपये के लगभग होगा। मध्यप्रदेश के भूमि-आकड़ा विभाग के डाइरेक्टर द्वारा प्रकाशित आंकड़ों से भी उपर्युक्त तथ्य की पुष्टि होती है। यदि हमारा यह अन्दाजा, तथ्य के निकट है कि ५० प्रतिशत भूमि बड़ाईदारों के द्वारा जोई जाती है, तो करीब १० करोड़ रुपये के हिस्सेदार वैसे लोग होते हैं, जो खेत पर काम किये बिना ही उसके मालिक हैं। यह एक प्रकार का चौथ होना है, जो प्रतिवर्ष साहूकारों द्वारा अभी वसूल किया जाना है। बरार की भूमि से कुल मालगुजारी जो सरकार को मिलती है, करीब एक करोड़ के बराबर है। साहूकारों को इससे कहीं अधिक मिलता है। बरार में "दो अमली" की प्रथा अभी भी चालू है।

रुपये लगाने के अलावे एक और कारण है जिससे साहूकारों का बदन कायम रहता है। वे रुई का व्यापार भी करते हैं। प्रत्येक साहूकार की, भूमिपति, महानन और रुई व्यापारी की, तीनों हैसियत साथ साथ रहती हैं। बरार के लिये कपास, जहाँ एक ओर बरदान है, वहाँ दूसरी ओर अभिशाप भी है। कपास उत्पादन के लिये काली मिट्टी, बहुत ही उपयुक्त है। अमरीकी यह युद्ध के समय तथा उसके बाद ग्रेटेन में कपास की पूर्ति रुक जाने के कारण वृत्ति-उत्पादकों को नये बाजार की तलाश में अपने एजेंटों को बरार भेजना पड़ा। सन् १८६७ में जी० आई० पी० रेलवे कम्पनी ने धम्पई और बरार के बीच लाईन निझा दी और महसूल में कमी करके कपास के वातायात को सुनिश्चित बना दिया। फलस्वरूप धम्पई के द्रव्य-वाजार से बरार के क्षेत्रों में रुपये की राढ़ आगयी और १९ वीं शताब्दी के अन्तिम २५ वर्षों में बरार ने अपने को रबी क्षेत्र से खरीफ क्षेत्र में बदल डाला।

किसानों की समस्याएं

नीचे के आँकड़ों से यह पता चलता है कि एक जिला में किस प्रकार यह परिवर्तन हुआ ।

यवतमाल जिला में : एकड़ में

वर्ष	खरीफ कपास के साथ	कपास
१८९१- ९२	१०,७०,२२५	४,०८,४३४
१८९५- ९६	११,७५,३७४	३,५०,१९८
१८९९-१९००	१०,३९,४४२	३,२३,८१५
१९०५-१९०६	१८,०१,७५३	७,१२,६६०
१९१५- १६	१६,००,४७८	७,०१,८६७
१९२०- २१	१६,५३,४९१	७,१७,४३०
१९२५- २६	१७,१४,१७४	८,०३,४९२
१९३०- ३१	१७,४०,६८७	८,५२,२८१
१९३५- ३६		
१९४१- ४२	१५,६९,२८८	६,४२,५६३
१९४५- ४६		५,८५,६३५
रक़्बा	प्रति रू० कपास का मूल्य सेर में	चैन
३,०१,४१०	२०	३,६५७
३,२२,५१९	२०	३,४४२
३,२,८७०	३१.१	२,७२३
१,९९,६९६	२.२	९,३२४
१,२९,३२८	२.४	१०,५११
४१,६९८		२,८२८
८०,१५७		२,८५७
७१,५०१		२,२०९
१,२४,५५३		
१,४१,७२७		४,०९६
		४,२२८

किमानों की समस्याएं

४. चमड़ा	२५०	४. मैनुषैचरिंग लोहा	४००
५. निविघ	१७५०	५. घातु	१६००
	<hr/>		
	२७,९००	६. चीनी	१६००
		७. मशाले	७००
		८. किरसन तेल	४००
		९. नमक	४००
		१०. मुपारी	५००
		११. नारियल	४००
		१२. अन्य	५१००
			<hr/>
			१,४८,००

इस प्रकार आयात की अपेक्षा १३० लाख के निर्यात की औसत अधिकता हुई है। आर्थिक प्रश्न अत्यधिक उलझे हैं, लेकिन यह समझ है कि जिला के शोषण के लिए निदेशियों द्वारा नफा के रूप में प्राप्त धन को यह निर्यात का नडा हिस्सा स्पष्ट करे।

ऊपर दिये आंकड़ों को देखकर पता लगता है कि उनमें ३० लाख से अधिक रुपये की मशीन मगयी गयी है। वे कपास-व्यापारी धीरे-धीरे महाजन बने फिर काफी जमीन के मालिक हो गये और अन्तमें कारखाने के मालिक हुए। इस वर्ग में चार पेशे के लोग हैं—महाजन, व्यापारी, मालगुजारी पर जमीन देनेवाले और उद्योगधधेवाले। इससे इनका प्रभाव सर्वव्यापी है। इनकी आमदनी की औसत तो ठीक नहीं बतायी जा सकती पर अन्दाजन यह २० करोड़ के नीचे कभी नहीं होगी। इसका केवल अनुमान किया जा सकता है।

३. कृषि और खेत की आमदनी

१० करोड़ रुपये

२. रुई का व्यापार

५ " "

३. सूद पर रुपये लगाना	३	”	”
४. कारखाने तथा अन्य उद्योग	२	”	”

कुल—२० करोड़ रुपये

महाजनी, जमीन्दारी और व्यापारमें एक साथ लगे इस वर्ग की और पूँजीपति की आय तो इस प्रकार है, और इसके निपरीत खेतिहर वर्ग की कुल ग्रामदानी ३० करोड़ रुपये हैं, जबकि ये कुल ग्रावादी का ७५ प्रतिशत हैं। १९३२ की मदी इतनी भयकर थी कि उस समय की सरकार को भी कर्ज सम्बन्धी कानून बनाने के लिये बाध्य होना पड़ा।

निम्न लिखित कानून इन ५ वर्षों में पास हुए।

१. १९३३ का मध्य प्रदेशीय ऋण सवधी कानून

२. १९३४ के चक्रवृद्धि ऋण निधान सशोधन

३. १९३६ का मध्य प्रदेशीय महाजनी कानून

४. १९३६ का मध्य प्रदेशीय औद्योगिक मजदूरी कानून

५. १९३७ का मध्य प्रदेशीय कर्जदार सरक्षण कानून

ये सभी वास्तविक लाभ देने में असफल रहे, क्योंकि ये जमाबन्दी की सुरक्षा की बुनियादी समस्या का स्पर्श भी नहीं कर सके। १८९६ में बरार भूमिकर कोड के निर्माण के साथ ही पहली गलती शुरू हुई। दर रैयतों के अधिकारों की रक्षा के लिये बहुत थोड़ी कोशिश हुई। इस कार्य के लिये १८६६ में दर रैयती नियम बनाये गये। पर वह आरम्भ से ही व्यर्थ रहा। १८५५ और १८६५ के बीच बरार में जमींदारी और रैयतगारी की पद्धति चालू करने के सवाल पर स्थानीय अपसरों और भारत सरकार में बड़ा मतभेद रहा। स्थानीय अपसर रैयतवारो चालू करने के लिये बहुत लड़े और अन्त में उनकी विजय भी हुई। लेकिन बरार की कृषि बुरी स्थिति में थी। १८६६ के बरार के दर रैयती कानून में निम्नलिखित व्यवस्थाएँ हैं—

नियम ६, उपनियम ४—जो बटाई की जमीन जोतता है वह दररैयत है।

फ़िस्तानों की समस्याएं

प्रमुख उपज, कपास के बाज़ार भाव का चढ़ाव उतार बहुत तेज़ और खतरनाक होता है। नीचे के चार्ट से मोटे तौर पर बम्बई के बाज़ार में कपास के मूल्य में घट-बढ़ का पता लगता है। यह चार्ट बम्बई की खान्डी को आधार मानकर बनाया गया है, जो ७८४ पौंड के बराबर है;

वर्ष	दर
१८६७ से ७५	२३० रुपये
१८७८ ,, ८८	२०३ "
१८८८ ,, ९८	१९० "
१९०३ ,, १९०४	२२२ "
१९०८ ,, १९०९	२४० "

बरादर के कपास व्यापार के महत्त्व पर गजेटीयर ने भी काफ़ी जोर दिया है। इसने बरादर में कपास के इतिहास का वर्णन इस प्रकार किया है—

“बरादर की व्यापारिक स्थिति में कपास का व्यापार बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इससे अनाज की खेती आधी हो गयी है और विदेशी व्यापार में आधा से अधिक कपास का स्थान रहता है। सारी अमुबिधाओं के बावजूद कपास की खेती के विकास में केवल एक शताब्दी लगी है।” यहाँ कपास पैदा करना पहले भी लाभदायक पाया जाता था। उत्पादकों की दयनीय अवस्था, उनके ऊपर कर्ज का बोझ, गैरमुस्तकिल बन्दोबस्ती; ये सभी उपज में समान रूप से बाधक थे। परन्तु कपास की खेती में तो और भी कठिनाइयाँ थीं क्योंकि विक्री केन्द्र दूर पड़ता था, कीमत कम थी और आरंभिक यातायात में सैकड़ों बाधाएँ थीं। सारादेश अशान्त था। १८२५, १८२६ में, जैसा कि कहा जाता है बम्बई और हैदराबाद के सौदागर, विकाजी और पेस्तनजी ने सर्व प्रथम सीधे बम्बई को कपास का निर्यात किया था। उसका कुल वजन १ लाख २० हजार पौंड और दाम २५-

हजार रुपए था। यह मुनने में तो थोड़ा लगता है, पर इसे दोने के लिये ५०० बैलों की जरूरत पड़ो थी। इसी उत्साही फार्म ने १८३६ में सर्वप्रथम रुई की गाठ बनाने का कारखाना खोला था। पर लम्बे अर्से तक यह काय किसी विशेष उन्नति के बिना चलता रहा।”

रुपये-पैसे की सस्ती के कारण, स्वमानतः मनुष्य खचौली आदतों में पस जाना है और उसके बाद सहसा मूल्यका पतन हो जाय तो मूल्य की वृद्धि की आशा पुनः किसानों को साहूकारों के द्वार का लालच उत्पन्न करती है। खास करके १८९९-१९०० के अकाल और १९३१-३२ के हास ने ग़रार के किसानों की रीढ़ ही तोड़ दी। १८९९-१९०० के भीषण अफ़ाल से इस शताब्दी का प्रारम्भ हुआ। किसानों ने अपने सोने चाँदी और जानवर बेच दिए तथा ज़मीन बन्धक रख दी। अफ़ले अकोला जिले में १८९९ और १९०० में १० लाख ३८ हजार रुपए की ज़मीन बिकी। १९३२ जाते जाते ज़मीन की कीमत आधी होगई।

कपास के मूल्य में हास और वृद्धि के अतिरिक्त कपास की कीमत का एक अच्छा भाग व्यवसायी साहूकारों द्वारा प्रायः हथिया लिया जाता था। निम्नतालिका शोषण तथा पूँजी के निर्माण का चित्र उपस्थित करती है।

अकोला

(१९०२ से ६ वर्षों का औसत, हजार में)

प्रधान निर्यात	रुपये	प्रधान आयात	रुपए+०
१. रुई	२,०३५०	१. पीस गुड्स	२०००
२. रुई का बीज	७५०	२. लोहा	१०००
३. शराब	४०००	३. भारतीय मिलोंके सामान	७००

किमानों की समस्याएं

४. चमड़ा	२५०	४. मैनुफैचरिंग लोहा	४००
५. त्रिनिध	१७५०	५. घात	१६००
	<hr/>		
	२७,९००	६. चीनी	१६००
		७. मशाले	७००
		८. क्रिसन तेल	४००
		९. नमक	४००
		१०. सुपायी	५००
		११. नारियल	४००
		१२. अन्य	५१००
			<hr/>
			१,४८,००

इस प्रकार आयात की अपेक्षा १२० लाख के निर्यात की औसत अधिकता हुई है। आर्थिक प्रश्न अत्यधिक उलझे हैं, लेकिन यह समझ है कि जिला के शोषण के लिए निदेशियों द्वारा नफा के रूप में प्राप्त धन को यह निर्यात का बड़ा हिस्सा स्पष्ट करे।

ऊपर दिये आंकड़ों को देखकर पता लगता है कि उनमें १० लाख से अधिक रुपये की मशीन मंगायी गयी है। ये कपास-व्यापारी धीरे-धीरे महाजन बने फिर काफी जमीन के मालिक हो गये और अन्तमें कारखाने के मालिक हुए। इस वर्ग में चार पेशे के लोग हैं—महाजन, व्यापारी, मालगुजारी पर जमीन देनेवाले और उद्योगधंधेवाले। इससे इनका प्रभाव सर्वव्यापी है। इनकी आमदनी की औसत तो ठीक नहीं बतायी जा सकती। अन्दाजन यह २० करोड़ के नीचे कमी नहीं होगी। इसका केवल अनुमान किया जा सकता है।

३. कृषि और खेन की आमदनी

१० करोड़ रुपये

२. रुई का व्यापार

५ " "

३. सूद पर रुपये लगाना	३ " "
४. कारखाने तथा अन्य उद्योग	२ " "

कुल—२० करोड़ रुपये

महाजनी, जमीन्दारी और व्यापारमें एक साथ लगे इस वर्ग की और पूँजीपति की आय तो इस प्रकार है, और इसके विपरीत खेतिहर वर्ग की कुल आमदनी ३० करोड़ रुपये है, जबकि वे कुल आबादी का ७५ प्रतिशत हैं। १९३२ की मदी इतनी भयंकर थी कि उस समय की सरकार को भी कर्ज सम्बन्धी कानून बनाने के लिये बाध्य होना पड़ा।

निम्न लिखित कानून इन ५ वर्षों में पास हुए।

१. १९३३ का मध्य प्रदेशीय ऋण सवधी कानून

२. १९३४ के चक्रवृद्धि ऋण विधान संशोधन

३. १९३६ का मध्य प्रदेशीय महाजनी कानून

४. १९३६ का मध्य प्रदेशीय औद्योगिक मन्दूरी कानून

५. १९३७ का मध्य प्रदेशीय कर्जदार सरक्षण कानून

ये सभी वास्तविक लाभ देने में असफल रहे, क्योंकि ये जमानन्दी की सुरक्षा की बुनियादी समस्या का स्पर्श भी नहीं कर सके। १८९६ में बरार भूमिहर कोड के निर्माण के साथ ही पहली गलती शुरू हुई। दर रैयती के अधिकारों की रक्षा के लिये बहुत थोड़ी कोशिश हुई। इस कार्य के लिये १८६६ में दर रैयती नियम बनाये गये। पर वह आरम्भ से ही व्यर्थ रहा। १८५५ और १८६५ के बीच बरार में जमींदारी और रैयतदारी की पद्धति चालू करने के सवाल पर स्थानीय अपसरों और भारत सरकार में बड़ा मतभेद रहा। स्थानीय अपसर रैयतदारी चालू करने के लिये बहुत लड़े और अन्त में उनकी विजय भी हुई। लेकिन बरार की कृषि बुरी स्थिति में थी। १८६६ के बरार के दर रैयती कानून में निम्नलिखित व्यवस्थाएँ हैं—

नियम ६, उपनियम ४—जो बटाई की जमीन जोतता है वह दररैयत है।

हिस्सानों की समस्याएँ

नियम ८—जिसकी ज़मीन में जमीन १२ साल से है, उस दररेख को दिगानोकी डिग्री के बिना जमीन से नहीं हटाया जा सकता ।

१८८८ के मालगुजारी विधान में ग्राम व्यवस्थाओं के बारे में अनुच्छेद ७१ में इस प्रकार लिखा हुआ है—

“जो कोई भी किसी तरह से जमीन पर अपना हक रखता है और इसने लिये यह जमीनार को रुपये या शारीरिक धन के रूप में भुगतान दिया करता है और इसके लिये सतीतन्नक प्रमाण प्राप्त हो, तो ऐसा समझा जाएगा कि उसे उस जमीन पर रैयती हक शामिल है ।” गद की व्यवस्था पूर्णरूप से ऊपर के संकल्प को वैधानिक रूप दे देती है । वर्तमान शताब्दी के आरम्भ के २० वर्षों में जागीरदारी क्षेत्र के रैयतों के संरक्षण के लिये कानून बनाये गये । रैयतदारी क्षेत्र के ग्राहदारा संरक्षण के लिये कोई एकास कोशिश नहीं की गयी । केवल १९५० का नगर रैयती कानून संशोधन विधान बना, जिसकी उपयुक्तता शकास्पद थी । १९४९ में पी० के० देशमुख ने एक मिन पेश किया था, जो पीछे वापस लेलिया गया । पिछले अधिवेशन में श्री वेनसारे ने एक मिन उपस्थित किया था, पर किसी को नहीं पता कि यह चुनाव की चाल थी, या इसका कोई प्रयोजन भी था । १९५० के सम्पत्ति-अधिकार-कानून के उन्मूलन ने अपने ३५वें अनुच्छेद के द्वारा मालिक मन्बूना अधिकार की पुष्टि की । इन छोटे-छोटे अधिकारों से गृहसंस्थक खेतिहरों का कोई खास लाभ नहीं हुआ ।

अन नये बरार का निर्माण तभी हो सकता है, जब यहाँ कर्ज देने, खेती, कपास-व्यापार और कारखानों को चलाने के लिये सहयोग समितियाँ बनाई जायँ । ये चारों कार्य संयुक्त रूप से चलना द्वारा सहकारी सभा के जरिये होने चाहिये । युग-युग से होनेवाले अन्याय की समाप्ति के लिये मत्तादारों, बगईदारों का स्थायी तौर पर उचित मालगुजारी निश्चित हो तथा हर तरह की बन्धोस्ती दूरत राकी जाय ।

चम्पारन में जमीनों का लूट

‘निलहे’ गये ‘मिलहे’ आये

पिछले डेढ़ सौ वर्षों से चम्पारन की जमीनों की लूट-खसोट जारी है। लन्दन, बम्बई, कलकत्ता, पटना, गया मुजफ्फरपुर, सभी जगहों के तरह-तरह के लोगों ने लाठी, पैसे और कानूनी दाय-पैच के जोर से चम्पारन के किसानों की जमीनों का अपहरण किया है। नील वालों के अत्याचार से गांधी जी ने उन्हें उभारा तो मिलनाले पहुँच गये,। मिलनालों से जमीन बची तो नेताओं ने लिया। इस तरह सारा चम्पारन आज कामों से मर रहा है। हाँ, गोरे-साहनों की जगह भूरे-साहनों ने ले ली है। परिस्थिति की इस भयकरता ने कानपुर के जलसे में सोशलिस्ट पार्टी को मजबूर किया कि वह डा० लोदिया, इस लेख के लेखक और रुशेंद बहन की एक जाँच कमीशन बहाल करे।

चम्पारन के किसानों की कहानी भारतवर्ष के, किसानों के शोषण की कहानी का एक दर्दनाक अध्याय है। किस तरह महाशक्तियाली मगध-सम्राट विजयनगर और अजानशत्रु की विजयवाहिनी को रोकनेवाले गौरवशाली

किमानों की समस्याएँ

लिच्छत्रियों की जमीन अष्टादहवीं सदी में स्थानीय मामलों-बेनिया, रामनगर, मधुवन और शिवहर—के हाथों में चली गयी, फिर किस तरह १९वीं सदी में ये जमीनें अंग्रेज कोठीवालों के हाथों गयी, फिर २० वीं सदी में किस तरह ये जमीनें कलकत्ता और बम्बई के पूजीगर्न और बिहार के नेताओं के हाथ में चली गयीं—इसका मिलित व्योरा गहरे अनुसन्धान और एज के बाद ही दिया जा सकता है।

१७९३ ई० में इस्ट इण्डिया कम्पनी ने चम्पारन की तीन चौथाई जमीनों की मिलिकियन बेनिया, मधुवन और रामनगर के राजाओं को दे दी। चम्पारन का कुल रफना ३५३१ वर्गमीड में से दो हजार वर्गमील आज बेनिया राज में है। चम्पारन को इन्हीं उर्बर जमीनों पर, सिन्धुवन के कोठी-वालों की गृहदृष्टि पड़ी। फर्नल दिक्क ने पहला फार्म १८०५ ई० द्वारा में सोना और १९ वीं सदी के अन्त होते होते अंग्रेजों के कोई सत्तर फार्म चम्पारन की भूमि पर मजबूती से जन गये। इन फार्मों के कच्चे में चम्पारन की करीब आधी जमीनें चली गयीं। इस तरह आप देखेंगे कि चम्पारन की जमीनों की मिलिकियन बेनिया, मधुवन और रामनगर के हाथों में रही और काश्तकारी का एक अंग्रेज कोठीवालों के पाम। इसका नतीजा यह हुआ कि किसान मजदूर ननकर दुखद जीवन व्यतीत करने लगे।

किन तरह के मयकर जुल्मों से अंग्रेज कोठीवानों ने चम्पारन के किसानों को उनकी जमीनों से बेदखल किया, उसकी लम्बी और दर्दनाक कहानी है। मुख्यतया नील की खेती के लालच ने अंग्रेज कोठीवालों को चम्पारन में खींचा। १९ वीं सदी के मध्य में निलहों के अत्याचार से किस तरह बिहार और बंगाल के किमान कॉप उठे थे, यह बिहार और बंगाल के किसान अभी तक भूले नहीं हैं। १८६० के लगभग फरीदपुर के जिला मैजिस्ट्रेट मि० टायर ने अपने मराहूर वयान में कहा था—“एक भी नील का नहीं पहुँचता है जो हिन्दुस्तानियों के खून से नहीं रंगा हो।”

इसी समय जांच कमीशन के सामने उन्होंने अपने वयान के सबूत में प्रमाण पेश करते हुए कहा—‘मैजिस्ट्रेट की हैसियत के कारण मेरे सामने किनने ऐसे आये हैं जिनके शरीर को कोठी वालों ने भाला से आर-पार छेद दिया है। बहुत से भाले से छेदे जाने के बाद गायन कर दिये गये हैं। इस तरह की खेती की प्रणाली को मैं रक्तपात की प्रणाली कहता हूँ।’

हिंसा और भूठी मुकदमेबाजी के बल पर कोठीवालों ने किसानों को जमीनों से बेदखल कर फार्म बनाये। समय समय पर किसान ऊब उठते थे और छिटपुट बगान्त कर बैठते थे। पहली बगान्त १८६७ ई० में हुई, फिर १८७७ में। दोनों बगान्तें बुरी तरह कुचली गईं। आखिरी और सनसे बड़ी बगान्त १९०७ ई० में हुई। यह बगान्त उसी साठी से शुरू हुई जिसकी बन्दोबस्ती के खिलाफ बिहार के हर कोने से आवाज उठ रही है। साठी के पास के रहनेवाले शेख गुलाम और सीतल राय नाम के दो अनपढ़ किसानों ने इस बगान्त का नेतृत्व किया और खुद इस बगान्त के साथ बर्गद हो गये। कलकत्ता के ‘स्टेड्समैन’ का निरोप संवाददाता जो इसी बगान्त की रिपोर्ट लेने बेनिया आया हुआ था, लिखता है—“बिहार के चम्पारन जिले में बेनिया की इस समय एक अजीब हालत हो रही है। कोठीवाले और रैयतों के झगड़े ने भीषण रूप धारण कर लिये हैं। अंग्रेजों के जानोमाल की हिंसा के लिये हथियारबन्द मिपाही और गुरखे लाये गये हैं। कुछ इलाकों ने मुद्र का रूप धारण कर लिया है।”

१९०७ ई० की बगान्त भी खून की घारा में डूबा दी गयी। परन्तु यहाँ के किसान आन्दोलन करते रहे। १९११ के दिसम्बर में जन बादशाह पंचम जार्ज इस इलाके से शिकार खेलने के लिये गुजरे, तो इस इलाके के किसानों ने बड़ी तादाद में इक्के होकर अपनी तक्लीफ जाहीर की। बादशाहने उनकी दरख्वास्त को भारत सरकार के पास जाँच के लिए भेजा किन्तु नतीजा कुछ नहीं निकला। इसके बाद ही चम्पारन के किसानों के

किमानो की समस्याएँ

सवाल को उस समय के पटने के मशहूर अखबार “निहारी” ने लिया, परन्तु उसका नतीजा सिर्फ यही हुआ कि “निहारी” के साहसी सम्पादक श्री मधेश्वर प्रसाद को सम्पादक के पद से हटना पड़ा। अन्त में चलकर १९१७ में महात्मा गांधी चम्पारन आये। चम्पारन में जो उन्हाने किया वह सभी को अच्छी तरह विदित है।

प्रत्यक्ष रूप से चम्पारन में शान्ति हुई। पर वह शान्ति ब्रिटिशान की शान्ति थी। पिछले सौ वर्षों में अँग्रेज कोठीगलों ने चम्पारन का खून चूस लिया था। वे चम्पारन से गये पर चम्पारन व किसानों को निजाव और निष्प्राण बनाकर गये। इसका नतीजा यह हुआ कि पिछले ३० वर्षों में तरह तरह के लोग आये और उनकी जमीनों को हड़प गये। वहाँ के किसानों में यह शक्ति नहीं रही कि वे अपनी जमीनों की रक्षा कर सकें। कांग्रेस मन्त्रिमण्डल आया, गया और फिर आया। देश की राज-निनिक आलोचना में आसमान जमीन का फरक हुआ। फिर भी उनकी हालत ज्यों की त्यों बनी रही।

आज सारा चम्पारन फार्मास बन रहा है। पूँजीपति, जमींदार, नेता, व्यापारी, तरह-तरह के लोग कलकत्ता, उम्बई, मुंबई, मुम्बईपुर, पटना, छपरा, शाहजहाँ से आकर चम्पारन के हर कोने में फार्मास बना कर बैठे हैं। किसी भी तरह कहीं भी गिरावटी पहुँच हो सकती थी, वह चम्पारन की अरखेज जमीनों के लालच में वहाँ जा पहुँचा है।

कलकत्ते के नेपाली साहू, उम्बई का पिच्ची परिवार, ब्रिन्दुस्तान के मशहूर बिडलाया के फार्मास वहाँ हैं। मैं इसे चम्पारन का चौर हरण कहना हूँ। आज तो हालत ऐसी है कि मालूम होता है, मानो, चम्पारन कोई अगला विधवा है, जो पाता है उसकी जमान को ले भागता है। महात्मा गांधी से लेकर देश के सभी बड़े नेताओं ने माना है कि किसान ही जमीन के मालिक हैं। फिर क्या काश्तकारीका भी नैतिक हक चम्पारनके किसानों को नहीं है ?

अब प्रश्न होता है कि गांधीजी के चम्पारन से जाने के बाद, किस तरह जमीनें किसानों के हाथों से निकल गयीं ? किस तरह पूँजीपतियों और दूसरों ने इतनी कीमती जमीनों पर कब्जा जमाया ? इसका सरल उत्तर है:

- (१) ईमानदारी और बेईमानी की खरीदगी से ।
- (२) सही और फरेब की बन्दोबस्तियों से ।
- (३) जोर और जुल्म से ।

पहले हम किसानों की बेदखली की पृष्ठभूमि को समझने का प्रयत्न करें। व्यापक और बड़े पैमानों पर फार्मों के बनने की कहानी १९३१ ई० से शुरू होती है। यह वही समय है, जब दुनिया एक भीषण आर्थिक संकट काल से गुजर रही थी। गल्ले का दाम नीचे से नीचे जा चुका था। किसानों के लिये ऊँची मालगुजारी चुकाना असंभव था। याद रहे, चम्पारन में मालगुजारी की दर काफी ऊँची है। औसत ५) बीघे के लगभग आ जाती है। पहले नील की खेती की बजह से किसान चढ़ी हुई मालगुजारी दे सकते थे। जब १९१२ के लगभग जर्मनवालों ने नकली नील का आविष्कार कर लिया, तो चम्पारन में नील की खेती खुद ब खुद गिर गयी। किसान उन जमीनों में धान बोने लगे। और धान से ऊँची मालगुजारी चुकाना सम्भव नहीं था। इसी समय जो चम्पारन की जमीनों पर गद्दहट्टि लगाये थे, उनके सौभाग्य से सत्याग्रह का आन्दोलन छिड़ा और किसानों ने मालगुजारी देनी बन्द कर दी। इसी की पीठ पर विहार का प्रसिद्ध भूकम्प आया जिसने यहाँ की जमीनों को बालू और मिट्टी से भर दिया। इन सगो का नतीजा यह हुआ कि बाकी मालगुजारी में हजारों-हजार जमीनें नीलाम हो गयीं। साधारणतया नीलामी के बाद भी जमीन को या तो किसान घट्टेया और मनराप पर जोतते थे या जमीन्दार अपनी जिरात करते अथवा दूसरे धनी किसान उसे बन्दोस्त ले लेते। पर इनमें से एक भी न हुआ। क्योंकि उसी समय मैदान में चीनी कम्पनियों ने प्रवेश किया। पहले

फिसानों की समस्याएँ

फहा जा चुका है कि चम्पारन के दो हजार वर्गमील पर बेनिया राज का अधिकार है। इस समय बेनिया राज के छोटे-छोटे अफसरों को पैसा देकर मिला लेना मिलवालों के लिए कोई मुश्किल बात न थी। इन्हीं अफसरों की मदद से मिलवालों ने नीलाम जमीनों को सस्ते दर पर बन्दोस्त लेना शुरू किया। फिर इन्होंने किसानों से भी बहुत सी जमीनें खरीद लीं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि चम्पारन की जमीन २० से ३० ४० तक प्रति गीचे दर पर खरीदी गयी। दर का इतना नीचा होना ही बताता है कि किसानों को मजबूर कर ये जमीनें ली गयीं। इस तरह जब मिल के छोटे-छोटे फार्म बन गये तब जमीन छीनने का दूसरा अध्याय शुरू हुआ। बीच में पड़नेवाला जमीनों के कास्तकारों को तरह-तरह के झूठे मुकदमों से तनाह किया गया। सरकारी रेकर्ड से पता चलेगा कि किस तरह एक-एक किसान पर दर्जनों गैर कानूनी प्रवेश (Tresspass) और चोरी के झूठे मुकदमे चलाये गये। दूसरी ओर, मिलवालों ने किसानों के लिये अपने-अपने खेतों पर आना-जाना मुश्किल कर दिया। चारों तरफ मिलवालों के छोटे छोटे फार्म बन चुके थे। इनके बीच में जिन किसानों की जमीनें पड़ती थी, उन्हें यदि अपने खेतों पर हल-चैल लेकर जाना हो तो वे मिलवालों के खेत होकर ही जा सकते थे। मिलवालों ने जब रास्ता बन्द कर दिया तो इन किसानों के सामने मिल-मालिकों को अपनी जमीन सौंपने के अलावा कोई दूसरा रास्ता न बच रहा।

अब फार्म बनाने का तीसरा अध्याय शुरू हुआ। जब मिलवालों के फब्के में गाँव की सभी खेती लायक जमीनें आ गयीं तब उन्होंने परती, चारागाह, नदी और भील के ऊपर नजर डाली। किसानों के लिये अपने जलबवरों को पानी पिलाना तक भी असम्भव हो गया। अभी भी कोई भ्रूलडा जाकर इस अवस्था को देख सकता है। इस तरह की नाकेबन्दी

ऊन कर, किसान अपने जानवरों को भी बेच डालता है। फिर मजदूरी छोड़ कर उसका कोई सहारा नहीं रहता। इसी पद्धति से मोतिहारी मिल ने जिले की 'राजधानी मोतिहारी के ईर्द-गिर्द छ. हजार बीघे का ५ फार्म बना लिया है।

इन बातों को देखते हुए क्या किसी भी जनता की सरकार के लिये इन फार्मों को सहयोगी प्रथा पर खेती करने के लिये किसानों को वापस करने में जरा भी हिचकिचाहट होनी चाहिए! समस्त डा० राजेन्द्र प्रसाद या प्रधान मंत्री बाबू श्री कृष्ण सिंह के फार्म जायज और मुनासिब तरीके से बने हों। परन्तु इससे हमारे दावे में कोई अन्तर नहीं पड़ता। हमारा तो नैतिक आधार पर यह दावा है कि चम्पारन की जमीन चम्पारन के किसानों की होनी चाहिये।

दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है बेतियाराज की जमीनों का, जिनकी बन्दो-बस्ती की नीति से आज जनता में सबसे ज्यादा खोम है। स्वर्गीय महाराजा हरिन्द्र किशोर सिंह बिना सन्तान के मर गये। उनकी विधवा धर्मपत्नी को सरकार ने पागल घोषित किया और राज को १८९७ ई० में कोर्ट और वार्डस के प्रबन्ध में ले लिया। तब से महारानी इलाहानाद में एक किस्म से नजरबन्द रह रही हैं और बेतिया राज का प्रबन्ध सरकारी विभाग द्वारा होता रहा है। जनमत ने महारानी के पागलपन की सत्यता को कभी स्वीकार नहीं किया। उनका बराबर यह विश्वास रहा कि अंग्रेजों ने कोर्ट और वार्डस के माफ़त गुलछुरें उड़ाने के लिये महारानी को पागल घोषित किया है। कांग्रेस मन्त्रिमण्डल के पहले कोर्ट और वार्डस के अधिनारियों का फ़ोरे व्यवहार और शाही रहन सदन जनता के संदेह की पुष्टि करता था। इन अपसरों का ज्यादा बक़ दास्त और शिकारमें जाना था। १९३७ में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल की स्थापना के बाद बेतिया कोर्ट और वार्डस का पद अंग्रेजों की ज़ारीरों नहीं रह सकी फिर भी जनता जो चाहती थी वह

किसानों की समस्याएं

उसे कमी नहीं मिली। अंग्रेज और हिन्दुस्तानी कोठीवालों ने पिछले डेढ़ सौ वर्षों में जो जुल्म किए थे, उनका थोड़ा सा भी निराकरण नहीं हुआ। अंग्रेज कोठीवाले एक एक कर अपने फार्म बेनिया राज को सौंप कर चले गये। याद रहे, ये फार्म १९ वीं सदी के खूनी हाथों से किसानों को बेदखल कर अंग्रेजों ने बनाये थे।

क्या इस समय सरकार का यह धर्म नहीं था कि वह कोर्ट और बार्ड्स के मारपट इन फार्मों को स्थानीय किसानों को वापस देकर पिछले डेढ़ सौ वर्षों के अत्याचार और शोषण का उन्हें आर्थिक मुआवजा देती! सत्तर बरस पहले जिन डागर और हरिजनों को लाठी और संगीन के हाथ अंग्रेज कोठीवालों ने साड़ी की जमीन से बेदखल किया था, उनकी किन्तु क्या सरकार ने की? साड़ी की बगावत का नेतृत्व करने वाले शेख गुलाम और सोनल राम के बराबरों को क्या सरकारने याद की? न्याय और धर्म का ठकाजा है कि पिछले चालीस वर्षों में जितनी गैरबसूली बन्दोबस्तियाँ हुई हैं, उन्हें रद्द कर दिया जाय और जमीनें किसानों को वापस की जाय। सरकार के लिये न्याय का एक ही रास्ता है, यानी चम्पारन के सभी फार्मों को कानूनी ढंग से दखल कर ले और उन्हें सान्त्विक प्रथा पर स्थानीय किसानों को खेती के लिये दे दे।

(२)

नई वेड़ियाँ

गौबीजी अपने पीछे एक महान जन-जाग्रति चम्पारण में छोड़ते गये। मरणासन्न समाज को नया जीवन मिला। केवल चम्पारण में ही नहीं सारे देश में उत्साह, और आशा की एक लहर दौड़ पड़ी। परन्तु फिर भी गौधीजी ने स्वयं महसूस किया—“यद्यपि रैयतों को थोड़ी सहूलियतें दिलाने में मैं सफल हुआ हूँ, लेकिन वे उन सहूलियतों से पूरा पायदा

नहीं उठा सकेंगे ; बल्कि दासता के नये बन्धनों में पुनः जकड़ जायेंगे ।”
(चम्पारण सत्याग्रह पृष्ठ २५५) । गाँधी जी की भविष्यवाणी सही निकली ।
आगे का इतिहास इन्हीं नयी बेड़ियों का इतिहास है ।

निलहों की पीठ पर चीनी मिल मालिकों का प्रवेश चम्पारण में हुआ । “निलहे गये, मिलहे आये”—यह कहावत आज चम्पारण के घर-घर में प्रचलित है । सन् १९२९ और ३४ के बीच एक एक कर ९ चीनी मिलें चम्पारण के विभिन्न हिस्सों में खुल गयीं । आज इन चीनी मिलों के फञ्जे में ४० हजार एकड़ जमीन है, जिस पर इनके फार्म हैं । इस थोड़े समय में चन्द व्यक्तियों के पास इतनी जमीन का इकट्ठा हो जाना, आश्चर्यजनक है । चीनी मिलों के आस-पास के किसानों के हृदय में तो इस बात की स्वाभाविक प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी कि वे अपनी जमीन पर अपना फञ्जा बनाये रखें, कारण मिल के खुल जाने से उन्हें पैदावार की कीमत अधिक मिलने की सम्भावना थी । बिहार के दूसरे जिलों में, जहाँ चीनी-मिलें हैं, वहाँ मिल-मालिक इस प्रकार के फार्म खड़ा कर सकने में सफल नहीं हो सके हैं । निर चम्पारण में ही उन्हें क्यों सफलता मिली ? क्या उन्होंने जमीन के लिये अधिक मूल्य दिये—ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं, जिन पर गम्भीरता से विचार करना होगा ।

इन प्रश्नों के उत्तर, किसानों के १० हजार बयानों में मिलेगा, जो फमीशन के सामने बेश किये गये । ये बयान बताते हैं कि किस प्रकार छोड़िया प्रायुक्तिक, ऐतिहासिक तथा आर्थिक कारणों की सहायता लेकर मिल मालिकों ने ३० ६० से २०० ६० एकड़ के हिसाब से चम्पारण के किसानों की उस जमीन को खरीद लिया, जिसकी औसत कीमत (१०००) ६० बीघा थी ।

निलहे गये, लेकिन चम्पारण के किसानों को बरबाद, पामाल तथा शक्तिहीन करके ।—सन् १८६७ से लेकर १९१७ तक लगभग ५० वर्षों

किमानों की समस्याएँ

तक, चलनेवाले निलहा किमान-संघर्ष ने किसानों के प्रतिरोध की शक्ति को चूर-चूर कर दिया। वे पूरे तौर पर थक चुके थे। फिर चलते समय शरीर वेशी और तामान के रूप में जो दोन्नी निलहों ने लगाई, उससे तो सारा चम्पारण ही मशजर्ना की चगुन में फँस गया।

अभी किसान दम भी नहीं ले पाये थे कि सन् १९३० की भयानक मन्दी सर पर सवार हो गयी। धान चम्पारण की मुख्य फसल है, उसकी कीमत ४५ प्रतिशत नीचे गिर गई। चावल जो सन् १९३८ में ७॥ सेर के भाव विक्रता था, सन् १९३१ में १३ सेर के भाव निकले लगा। ठीक उसी समय मार्च सन् १९३१ में सारे चम्पारण में ओले पड़े, जिससे रबी की फसल मारी गई। जिने के गीचोनीच दस मील की चौड़ाई में एक दाना भी नहीं बच पाया। उसी समय चम्पारण के मोतिहारी थाने में एक लगान बन्दी आन्दोलन भी चल पड़ा। कांग्रेस ने तो बीनोदारी टैक्स बन्दी आन्दोलन शुरू किया था; लेकिन जनता ने उसे लगानबन्दी का रूप दे दिया।

इन सभी घटनाओं के पीछे पीछे आया १९३४ का महानाराकारी भीषण भूकम्प। चम्पारण के कुछ इलाकों की आसद जमीन बाबुकाराशि से टक गई। घनि का कुछ अन्दाज नीचे के आकड़ा से लग सकेगा :—

(क) ७९,००० ६० प्राकृतिक दुर्घटना के लिए फर्ज के रूप में ४॥ ६० सैफटा सालाना सूद पर सरकार ने दिया।

(ख) १,२७,०००६० प्राकृतिक दुर्घटना के लिए फर्ज के रूप में ६॥ ६० सूद की दर पर दिया।

(ग) ४,६९,००० रुपये वायमराय ने भूकम्प विनि-कार से भवान आदि बनाने तथा मरम्मत करने के लिये दिया गया।

(घ) १०,७७,१३३ ६० बालू साफ करने के लिये ग्रान्डीय सरकार द्वारा फर्ज दिया गया।

इनके अलावा लाखों रुपये गैरसरकारी संस्थाओं की ओर से खर्च किये गये ।

व्यक्तिगत महाजनों तथा सहयोगी बैंकों ने, किसान की जमीन कर्ज में लेकर मिल-भालिकों के हाथ बेच दी । उदाहरण के लिये भोलादास, सा० लक्ष्मण दोला, थाना मोतीहारी की दस एकड़ जमीन एक सौ रुपये के कर्ज में लेकर सहयोगी-बैंक ने मोतिहारी-मिल के हाथ बेच दी । इतना ही नहीं, सरकारी कर्जा अदा करने के लिये भी किसानों को जमीन बेचने के लिए बाध्य किया गया । तपेश्वर सइनी, दोला गिण्णपुर, साकिन देकहा, थाना मोतीहारी ने अपने ध्यान में कहा कि दस से लेकर १५, २० बीघे की दर पर, उसने सरकार से बालू साफ करने के लिये रुपये कर्ज लिये थे । लेकिन बालू साफ करने में वह असफल रहा । सरकार द्वारा कर्ज अदा करने के लिये तकाजा आने पर, बाध्य हो उसे आठ आने से बारह आने कच्चे के हिसाब से अपनी जमीन मोतीहारी मिल के हाथ बेच डालनी पड़ी । इन्हीं कारणों से किसानों के हाथों से जमीन निकल कर, चन्द लोगों के पास जमा हो गई । गांधीजी के चम्पारण से जाने के बाद, करीब २॥ लाख एकड़ जमीन चम्पारण के किसानों के हाथों से निकल कर महाजनों, मिल-भालिकों और अन्य फार्म-भालिकों के हाथ चली गई । कलकत्ता, बम्बई, कानपुर और लन्दन के पूँजीपतियों ने चम्पारण के निवासियों की दुरवस्था से पूरा-पूरा लाभ उठाया ।

इनके अलावा अनेक प्रकार के बलप्रयोग का भी सहारा लिया गया । ग्राम-तरीका यह था कि मित्र-भालिक किसानों की जमीन के चारों ओर जमीन रखीद लेते थे और बाद में अपनी जमीन से होकर उनके हल-धैल का आना-जाना बन्द कर देते थे । इस प्रकार या तो किसानों को जमीन छोड़ने के लिये मजबूर हो जाना पड़ता था—या सली कीमत पर उनकी जमीन खरीद ली जाती थी । नीचे कुछ तरीकों का उल्लेख किया जा

किसानों की समस्याएँ

रहा है, जिनका सहारा लेकर मिल-मालिकों ने किसानों की जमीन बेचने के लिये बाध्य किया :—

- (१) जमीन पर आना-जाना बन्द करना ।
- (२) किसानों के खिलाफ झूठे मुकदमे चलाना ।
- (३) जबरदस्ती कब्जा करना ।
- (४) पानी का रास्ता रोकना ।
- (५) गैर-मजदूरा जमीन पर अधिकार करना ।
- (६) किसानों की फसल बर्बाद करना ।
- (७) जगहों जानवरों का मारना रोकना ।
- (८) राज के अमलों को मिलाकर किसानों की जमीन को निलाम पर चढ़ाना ।
- (९) किसानों के पारिवारिक भ्रगडा से लाभ उठाना ।

लौरिया-मुगर मिल्स ने, जो बालमिया-जैन-कन्सर्न के मानद्वत है किस प्रकार अपना फार्म खोला, उसका विवरण नीचे दिया जा रहा है :—

१९वीं सदी के उत्तरार्द्ध में मि० शा ने परसा कन्सर्न नाम से एक फार्म खोला । उनके उत्तराधिकारी मि० क्रान्सिड मिडियम ने गैर-मजदूरा जमीन को आबाद कर तथा जबरदस्ती आस-पास के गांवों में हरिजनों को उजाड़कर हारपुरा, बिरकहिया और भगिया में अपने फार्म की शाखा स्थापित की । हरिजनों द्वारा कनीशन के सामने बड़ी गई दर्द भरी कहानी इस प्रकार है :—“जोड़ी ने चार बीघे जमीन, जिसे हम दो पीढ़ियों से जोड़ आबाद करते आ रहे थे, बिना कोई कीमत दिये, छीन ली । सनूची दस्ती जला कर राख कर दी गई । एक सौ आदमियों को जमीन से बेदरतल पर अमोज निलहों ने अपने फार्म बनाए । तीन कुत्ते, जो उस समय भर दिये गये थे, आज भी चिह्न के रूप में मौजूद हैं । आने जाने का रास्ता बन्द कर दिया गया, और इस प्रकार अनेक तरह से लोगों को तंग दिया गया । (बयान सं० १३४)”

फ्रान्सिस विलियम के उत्तराधिकारी ने १९४३ में तीन लाख रुपये में इन फार्मों को डालमिया जैन के हाथ बेच डाला। फार्म खरीदने के बाद मिलमालिकों ने पयरी, किरंगो और जगिरहा; तीन बस्तियों को उजाड़ डाला। उनकी जमीन बिना मूल्य दिये जोत ली। इसके बाद कायमी रैयतों को सस्ते दर पर जमीन बेचने के लिये बाध्य किया जाने लगा। गैरमजदूरा जमीन जोत ली गई। मित्र के फार्मों के बीच जिस किसान की जमीन पड़ गई, उसे हल-बैल लेकर अपनी जमीन पर जाने से रोक दिया गया। किसानों के खिलाफ झूठे मुकदमे चलाये गये। छिटफुट ढंग से उनकी जमीन जबरदस्ती जोत ली गई। उदाहरणार्थ, बोगड़ा (धाना बगड़ा) फे रामफल कमरूर की मृत्यु के बाद, उसकी जमीन जबरदस्ती जोत ली गई। उसके परिवार में दो नाबालिग बच्चों के सिवाय और कोई नहीं था। उन्हें गांव छोड़कर भाग जाने के लिये मजबूर किया गया। विधवाओं और नाबालिगों से इस प्रकार की कहानियाँ हर जाँच-केन्द्र पर, कमिशन को सुनने का भौका मिता।

किसानों ने यह भी बताया कि मित्र की ओर से फार्मों में दीवने वाली रैजगाड़ियों से बचने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। हर वर्ष कुछ लोग कटकर मरते थे। यहाँ तथा अन्य जगहों में मिल मालिकों के व्यवहार के सम्बन्ध में और भी अनेक शिकायतें सुनने में आईं। मित्र द्वारा अधिक्त जमीन की हिस्से नीचे दी जा रही है :—

निलहों से खरीद कर	१८४०	एकड़
जबरदस्ती बच्चा करके	१५०	"
सस्ते दानमें खरीद कर	१९०	"
देविया-राज में बन्दोस्ती लेकर	२००	"
गैर-मजदूरा जमीन जोत कर	८००	"

कुल जोड़—२५८० एकड़

किमानों की समस्याएँ

इस प्रकार विभिन्न चीनी मित्रों ने चालीस हजार एकड़ जमीन पर अपना अधिकार जमाया, जिसके लिये उन्हें कुल बीस लाख रुपये से अधिक नहीं देने पड़े। इस सम्पत्ति की कीमत अभी चार करोड़ से कम नहीं होगी। हम इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि चम्पारण का चीनी भी उसी प्रकार मनुष्य के रक्त से बना है, जिन प्रकार आज से छत्तीस वर्ष पूर्व नील चम्पारण-बानियों के रक्त से बना रहता था।

विभिन्न चीनी मित्रों के नामों के आकड़े इस प्रकार हैं:—

१. चकिया, बृथि इन्डिया फारपोरेशन	— १२०० एकड़
२. मुगौली, श्री अहमद खली	— १२०० "
३. लीरिया, श्री शाहिप्रसाद जैन	— ३५०० "
४. ममौलिया, मेसर्स मोतीनाथ पदम पत	— ४००० "
५. चनपट्टिया, बृथि इन्डिया फारपोरेशन	— ३०० "
६. नरकटियागज, मिडला ब्रदर्स	— ३००० "
७. हरिनगर, राज नारायण लालपित्री	— १०,००० "
८. बगहा, खेतान ब्रदर्स	— ४,००० "
९. मोतीदारी, रामेश्वर लाल नेपाली	— १२,००० "

उपर्युक्त आँकड़ों से पता चलता है कि सरसे अधिक जमीन कलकत्ते के रामेश्वरलाल नेपाली के पास है। यह १२ हजार एकड़ जमीन मोतीदारी शहर की नारुके नीचे है, जो शहर भिले का सदर मुकाम है। गाँव के गाँव उजाड़ कर, वहाँ की जनता को गरीब और फटेदार मजदूर बनाकर, जिससे कि सदी मजदूरी पर उनका उपयोग किया जा सके, मोतीदारी—चीनी मित्रने १२ हजार एकड़ जमीन पर अपना फार्म खड़ा किया। यह पहले लिखा जा चुका है कि किस प्रकार जोर बुलन तथा जाल-पाशों से अंग्रेज निलहों ने फार्म बनाए। सपूची उन्नीसवीं सदी का इतिहास चम्पारण के किसानों के साथ किये गये अमानुषिक अत्याचार और निर्दयता का दर्दनाक

इतिहास है। किसानों के रूढ़ि के धनवाले इन्हें पानों को मित्र मालिकों ने सरीदा और बहुत कुछ इन्हीं तरीकों से इन्हें दबाया भी। ऐतिहासिक न्याय और समता दोनों का तकाजा है कि ये फार्म चम्पारण के किसानों को लौटा दिये जायें। जहाँ तक मुआयजे का सवाल है, इन लोगों ने लागू से अधिक उपार्जन कर लिया है। यद्यपि चीनी से आमदनी बहुत अधिक होती है, फिर भी अगर वी एकड़ एकसौ रुपये मान लिए जायें, तो चालीस हजार एकड़ जमीन की दस वर्ष की आमदनी चार करोड़ रुपये हुई। हम लोग फार्मों को तोड़कर पुनः छोटी छोटी एराजियों में जमीन बाँटने की सलाह नहीं देते। इन फार्मों को तोड़ कर छोटी एराजियों में बाँट डालने पर उत्पादन कम होगा तथा कार्य कुशलता भी घट जायगी। अतः जमीन की निष्क्रियता तो गरीबों, किसानों और फार्ममजदूरों को दे दी जाय, लेकिन खेती सहयोगी आधार पर ही हो। यही हम लोगों की राय है। इस प्रकार हम न्याय और कार्य-कुशलता दोनों की रक्षा कर सकते हैं। मित्र के फार्म चम्पारण के किसानों को अवश्य लौटा दिए जाने चाहिए। जब हम मित्र की जमीन कहते हैं, तब हम साधारण अर्थ में इस शब्द का प्रयोग करते हैं। केवल मुगौली मिल को छोड़ कर प्रायः सब जमीन अपने नाम से खरीदी है। इसके पीछे शायद इनकम्पैक्ट से खेती तथा शेयर होल्डरों को मुनाफे से बचाने रखने का इरादा छिपा हो। मैनेजिंग एजेंट को लाखों का मुनाफा होना हो, लेकिन सम्भव है मित्र घाटे में चलती हो। इस प्रकार तो एक तरफ शेयर-होल्डरों से अन्याय किया गया है तथा दूसरी ओर चम्पारण के १०,००० परिवारों को वे जमीन नष्ट दिया गया है।

गाँधीजी के चम्पारण छोड़ने के बीस वर्ष बाद, चम्पारण पुनः दासता की नई जर्जर में जकड़ गया है।

(लोडिया कमिशन की रिपोर्ट का एक अध्याय)

खेत पैदावार के दामों के जरिये किसानों का शोषण

दाम और सिक्का; ये दोनों आर्थिक संसार में खुलकर काम करने-वाले महत्वपूर्ण तथ्य हैं, परन्तु पूँजीवाद के कलावाज इन्हे ऐसा पेचीदा बना देते हैं कि बड़ों-बड़ों के लिये इनके काम रहस्यमय बन जाते हैं। जर्मनी के मशहूर सिक्का-जादूगर डा० शास्त्र ने किस तरह पन्द्रह वर्षों तक सिक्कों की जादूगरी से सारे यूरोप को चकाचौंध में रक्खा, यह सभी जानते हैं। साधारण जनता को इसे सरल भाषा में समझाना असंभव सा ही है और इस लेख का यह उद्देश्य भी नहीं है।

आज याजार में जाइये, २४ रु० मन चावल और ८ रु० जोड़ी घोड़ी है। याने ३ जोड़ी घोड़ियाँ एक मन चावल के बराबर हो गईं। यह किस सिद्धान्त पर हुआ कोई ठीक बता नहीं सकता। क्योंकि चावल और घोड़ी के भाव की गति के अलावे, रुपयों की एक स्वतन्त्र गति बन जाती है। रुपये अपनी मर्जों से भी अन्तर दो कस्तूरों का मेल बैठाने हैं।

किसानों की समस्याएँ

इसको को गति का खेल और गति और खरब-गति हो खेल सकते हैं । किस तरह इन बड़े पूँजीगतियों के ४० परिवार इस महायुद्ध के पहले सिक्कों के खेल से मंत्रमण्डलों को ढोड़ते और बनाते थे, यह १९२२ से १९३७ तक के फ्रान्स की राजनीति को जानने वाले जानते हैं । परन्तु दाम और मुद्रा के इस खेल का एक पहलू है, जिससे संसार के करोड़ों किसानों का जीवन प्रभावित होता है । यह है खेत-पैदावार के मूल्य का औद्योगिक पैदावार के मूल्य के साथ सम्बन्ध कायम करना ; क्योंकि खाने के अलावे रेत की सभी पैदावार बाजार में विक्राने, याने अतः में विनिमय के लिए जाती है । किसानों का मुख और समृद्धि तक, इस बात पर निर्भर है कि बहुत दूर खेत की पैदावार के दाम का सम्बन्ध औद्योगिक वस्तुओं की पैदावार के साथ क्या है ।

पूँजीवाद आन्तरिक विरोधों से चलनी सा हो रहा है । नफे की दर अपने नियम से घटती जा रही है । एसिया के पिछड़े भागों पर आर्थिक साम्राज्य कायम कर, अपने तैयार माल को, उनपर लाद और उनके कच्चे माल को उठा, पूँजीवाद इन छेदों को भरता रहा है । इसमें किसानों के अक्षय्यक्ष क्षोण का किनासा बड़ा दिखता रहा है, इस पर अभी नकार नहीं डाला जा सका है ।

आप हिन्दुस्तान के बाजार-मावों का अध्ययन करें, तो आपको पता चलेगा कि १९१५ ■ जो उद्योग-धंधे के माल के भाव का पल्ला भारी हुआ, वह बराबर महायुद्ध के पहले तक जारी रहा । भाव तेज या मन्दा हो, तो सभी वस्तुओं को दाम एक से बढ़ने-घटने चाहिए । परन्तु १९१५ के बाद, आप देखेंगे सभी भी रेतों की पैदावार के भाव का चढ़ाव, का रखानों के माल के भाव के चढ़ाव का साथ नहीं रख सका है । छोटे छोटे किसान सारे देश में बिखरे हैं, उनका कोई संगठन नहीं है ।

किमानों की समस्याएं

पूँजीवित्तों सस्तर कच्चा माल चाहिये, और सस्ते मजदूर चाहिये । इसलिए, इसने पिछले ३० वर्षों में, कभी उन्हें उचित दाम मिलने नहीं दिया ।

जरा नीचे के आँकों का अध्ययन हम गौर से करें । १९१२ के भाव को १०० मानकर हमने यह एका बनाया है । रेत के पैदावार में चावल, रोहू, चना, तेलहन, जूट, तथा कपास के भाव लिए गये हैं । कारखानों के माल में सूतीमाल, नमक, लोहा, और किरासन तेल के भाव लिए गये हैं ।

(इन आँकों के लिए लेखक श्री सरकार, डायरेक्टर खेत विभाग, बिहार सरकार का अनुग्रहीत है)

रेत के पैदावार के दाम का पूरा इंडेक्स नम्बर	कारखाने के दाम का इंडेक्स नं०	रेत की पैदावार की क्रय शक्ति का इंडेक्स नं०	कारखानों के माल की क्रय शक्ति का इंडेक्स नं०	कारखानों के माल की क्रय शक्ति का चढ़ाव
१९१२...१००	१००	१००	१००	०
१९१३...१०६	९६	११०	९०	०
१९१४...११५	९८	११९	८५	२०
१९१५...१०७	१२६	८६	११८	३२
१९१६...११०	१६०	६९	१४५	७६
१९१७...१११	२२२	५०	१००	१५०
१९१८...१२४	२५४	४९	२०५	१५६
१९१९...१८९	२७९	६०	१५०	८३
१९२०...१६४	२६६	६२	१६०	९२
१९२१...१५५	२२७	६८	१४६	७८
१९२२...१५५	२०९	७४	१३५	६१
१९२३...१२७	१९५	६५	१५०	८५
१९२४...१२९	२०२	६४	१५६	९२
१९२५...१४५	१७९	८१	१२३	४२
१९२६...१४५	१७८	८१	१२३	

किसानों की समस्याएं

१९२७...१२५	१७९	७०	१४३	७२
१९२८...१३२	१६३	८१	१२३	४२
१९२९...१३६	१५९	८६	११८	३२
१९३०...१०७	१५२	७१	१४२	७१
१९३१... ७१	१४२	५०	२००	१५०
१९३२... ७१	१४२	५०	२००	१५०
१९३३... ७२	१३७	५३	१९०	१३७
१९३४... ७०	१४८	५०	२००	१५०
१९३५... ७६	१२६	६१	१६६	१०५
१९३६... ७९	१२४	६४	१५७	९३
१९३७... ८७	१३७	६४	१५७	९३

ऊपर के आंकड़े ही किसानों के शोषण के बलन्त उदाहरण हैं । इन आंकड़ों में आप यह देखेंगे कि यद्यपि १९१९ का माद १८५ किसानों को किर कमी नहीं मिला, तो भी १९२० से १९२९ तक, याने १० वर्ष खेतों की पैदावार की कीमत की दर १४० के आस पास रही, परन्तु १९३१ में ७१ पर जाकर जो गया । वह किर कमी नहीं उठा, किसानों की दिपत्ति का अन्दाजा आप केवल इस बात से लगा सकते हैं कि १९२८-२९ में खेत की पैदावार की कीमत १०३० करोड़ रुपये थी, वह १९३३-३४ में घट कर ४७३ करोड़ मात्र रह गई । १९३१ और १९३७ के बीच किसानों की कसर टूट गई, जिससे वे कभी पूरे तौर पर उठ नहीं सके ।

इस महायुद्ध ने भी किसानों के एक छोटे हिस्से को ही फायदा पहुँचाया । १९४१ तक तो गलने का भाव बढ़ने नहीं दिया गया । उसके बाद बढ़ना शुरू हुआ, परन्तु भी वह कमी कारखानों के माल का कीमत के बढ़ाव के साथ कदम नहीं मिला सका । जूट और कपास के आंकड़ों को लेकर हम इसे समझने का प्रयत्न करें । हमारे मित्र श्री भाविन कुर्वे ने इस पहलू पर अपनी पुस्तिका में बहुत अच्छा प्रकाश डाला है ।

वाजार भाव

अगस्त १९३९;.....१०० (वाजार भाव)

	लूट कच्चा	लूट तैयार	कपास	सूती माल
४०-४१	११३	१३२	१२८	११८
४१-४२	१३७	१८२	१४५	१७८
४२-४३	१५३	१८७	१६१	११०
४३-४४	२०९	४९२	१२८	४०४
४४-४५	२०७	२५२	१८८	२६३
४५-४६	१८०	२५३	१८२	२७१

कपास का भाव ४३-४४ में २२८ है, तो सूती माल का ४२४। यह क्या बताता है १ कपड़े के कारखाने वालों ने जितनी कीमत बढ़ाई, कपास की खेती करने वाले किसान, कपास की कीमत उतनी नहीं बढ़ा सके। इस महान अभ्यास का प्रतिकार क्या राष्ट्रीय - सरकार करेगी ?

पाँच वर्ष के कटु - अनुभव के बाद भी, उनकी बुद्धि ठिकाने नहीं आई। दंगलोर में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने चुनाव की घोषणा को मंजूर कर फिर वही फैसला दिया जिस से भारत सरकार की नीति लगातार विफल हो रही है। चुनाव-घोषणा पत्र में लिखा है;

“लड़ाई के बाद के सन्तुष्ट, मूल्यों की नीति ने शहर और देहात के बीच के असंतुलन को कुछ अंश तक कम किया है।”

• श्री के० एम० मुखर्जी, खाद्य मंत्री, भारत सरकार, ने कुछ महीने पहले कहा था :-

“मेरे सौभाग्य से कम से कम किसानों की हालत पहले से अच्छी

किसानों की समस्याएँ

है। शहर तकलीफ में है। पर किसान आशान्वित हो ऊपर देख रहे हैं।”

गाँव की हालतों का यह निष्ठुर अकालन बड़ा ही दुःखद है। सरकारी कागजात से बार बार यह सिद्ध कर दिया गया है कि लड़ाई के बाद मुठ्ठी भर धनी-किसानों को छोड़ समस्त देहाती जनता को लाम के बदले हानि ही हुई है। भारत सरकार द्वारा खेतिहर मजदूरों की हालतों की जाँच की रिपोर्ट में भी घाटे के पारिवारिक-बजट और उसके परिणाम का अंदाजा लगाया जा सकता है। सरकार की जाँच से साफ हो जाता है कि एक खेतिहर मजदूर-परिवार की औसत सालाना आमदनी १९४९ में ४४४.४ रु० थी और खर्च ६१५.८ रु०।

सरकारी जाँच के अनुसार खर्च का व्योम निम्न लिखित है :

१. भोजन	५२१.७ रु०
२. वस्त्र और जूता	३०. ,,
३. जलापन और रोशनी	१०.१ ,,
४. घर का किराया	३. ,,
५. विविध	५१. ,,
कुल		६१५.८ ,,

इसका मतलब यह हुआ कि भोजन - खर्च भी नहीं चल सका और परिणाम स्वरूप कुछ को छोड़ सभी परिवार कर्ज में डूब गये।

कर्ज का प्रधान कारण खर्च का नहीं जुटना ही है। छोटा किसान बटाईदार बन जाता है। बटाईदार खेतिहर-मजदूर और खेतिहर - मजदूर कर्ज की गुलामी में बुरी तरह पस जाता है। आशान्वित होकर ऊपर देखनेवाले किसानों को यही सच्ची तस्वीर है।

विहार सरकार द्वारा प्रकाशित चतुर्मासिक रिपोर्ट (१९५०) से जमीन की बिक्री और बंधक के निम्न लिखित आकड़े इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं :

३१ मार्च ५१ को समाप्त
होनेवाला चतुर्मास

जिला	बिक्री रुपये	बंधक रुपये
१. पटना	५०,६८,२४७	२९०,०,३०८
२. गया	२७,६६,४९१	१२,५६,२११
३. शाहाबाद	२८,०७,९६८	२४,८४,४०७
४. मुगफरपुर	६३,३४,१२८	३६,८१,९६८
५. दरभंगा	६५,५४,६१३	२५,६८,८९८
६. सारन	३०,७३,८१३	४७,६१,५७६
७. चम्पारण	४२,७३,६४१	३३,७६,६८४
८. मुंगेर	३८,१३,०६६	२३,७५,६४६
९. भागलपुर	३९,०८,७००	१५,१८,५९२
१०. पूर्णिया	४,४६,५२०	१०,०४,०३१
११. संधालपरगना	३,७८,३६९	२९,२३६
१२. रांची	६,८८,२१३	३,८०,३५९
१३. पलामू	३,६४,९१८	९९,४१९
१४. हजारीबाग	१२,७९,४८७	१,९८,७८८
१५. मानभूमि	७,४८,३१७	१,७७,५९५
१६. सिद्धभूमि	१६,९०,२५४	४,४६,४०५
जोड़	४,४२,२०,१३९	२,७२,९१,१२९

किसानों की समस्याएं

३० जून ५० को समाप्त
होनेवाला चतुर्माह

बिक्री
रुपये

६४,०९,४०४
२९,७२,५९२
४९,००,९६१
८०,३४,६५३
६९,८६,७६८
४०,३९,९७०
५९,०७,१२२
४७,७८,०५०
६४,५१,७८९
४२,६१,०७४
४,४२,२६८
७,३५,९०७
४,६५,३७७
१४,०२,९१३
५,९०,४७८
२,३६,८७२

बंधक
रुपये

६६,२५,१६१
१७,५५,५७८
८५,८५,२७८
६५,७८,०२३
५८,०३,१७६
१२४,३९,४९९
६८,८७,४२७
४६,५८,३१८
२५,७८,८१७
१६,६०,०६१
३८,७५८
४,६७,७८८
१,३०,८१५
२,६१,३९०
६,११,५२२
१०,००,९९६

५,८६,६८,१०७

१,९४,२४,९५

उपर्युक्त आंकड़ों का साफ साफ मतलब यह होता है कि
लकाई के बाद से बिहार के गरीब-किसानों के हाथ से बिक्री और

बंधक के जरिये, प्रत्येक साल ३० करोड़ रुपये की जमीन निकलती चली जा रही है।

विहार सरकार द्वारा प्रकाशित विहार की राष्ट्रीय आय ने कृता है कि १९४६ से १९४७ में करीब दो करोड़ एकड़ जमीन की कुल आयदनी २०० करोड़ रुपये हुई। इस हिसाब से प्रति एकड़ लगभग १०० रुपये का उत्पादन हुआ। आज तक की रिपोर्टों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पाँच एकड़ से कम जमीन जोतने वाले खेतिहरों की संख्या ७० प्रतिशत है। इसके अनुसार, इस तरह के औसत खेतिहरों की खेत से सालाना आयदनी ३०० या १५० रुपये से अधिक नहीं है। उसे इसी आयदनी से खेती का खर्च भी चलाना पड़ता है। गत वर्ष उत्तर प्रदेश की सरकार ने जाँच पड़ताल कर, यह साबित कर दिया है कि खेतिहरों को, रबी को खेती में घाटा लगता है। यह साधारणतः नज़र अंदाज़ कर दिया जाता है कि देहाती आबादी के ६० प्रतिशत से अधिक भाग को बिक्री से उपादा खरीद करनी पड़ती है। खेती के अधिकांश उत्पादन (७० प्रतिशत तक ही सकता है) का सरकारी उपयोग हो जाता है। इस उत्पादन पर मूल्य का कोई असर नहीं पड़ता है। दूसरी ओर, वे अन्य आवश्यकताओं की बढ़ी हुई कीमत के भार से तबाह होते रहते हैं। अतः कृषि और आधुनिक वस्तुओं का मूल्य संतुलन देहाती जनता के लिये अत्यधिक महत्व रखता है।

यह राष्ट्रीय ही नहीं, अन्तर्राष्ट्रिय समस्या है। आज भी दुनिया की अधिकांश आबादी का प्रधान पेशा खेती है। खेतिहरों की तरक्की पर दुनिया की समृद्धि निर्भर है। आज तो उनका जीवन निर्वाह भी मुश्किल से हो पाता है। उन्हें जबतक इस अवस्था से ऊपर नहीं उठाया जाता, तब तक विश्व सुखी नहीं हो सकता। बहुत से सुधारों के बावजूद, उत्पादन भूमि-सम्बन्ध और कृषि तथा उद्योगमय वस्तुओं की कीमत के संतुलन

किसानों की समस्याएँ

सम्बन्धी मूल प्रश्न, ज्यों के त्यों पड़े हैं। खेतिहरों की तरफ ही इन प्रश्नों को हल किये बिना नहीं हो सकती।

गत शताब्दी में एक ओर दुनियाँ की आबादी बढ़कर दुगुनी हो गई है, दूसरी ओर अन्न और वस्त्र की समस्या पहले ही की तरह ज्यों की त्यों गम्भीर बनी हुई है। पूँजीवादी समाज व्यवस्था में मांग और पूर्ति की जबरदस्त शक्ति काम करती है। फिर भी यह विशाल जनसमूह की प्राथमिक आवश्यकताओं का पूर्ति भी नहीं कर पाता है। जन साधारण की क्रय-शक्ति नहीं के बराबर है। पूँजीवाद क्रय-शक्ति को ऊँचा उठा सकने में तिलकुल असमर्थ है। दुनियाँ के किसान आधा पेट खाकर जी रहे हैं। जोसिया स्टाम्प ने ठीक ही कहा है “दुनियाँ को लागत से भी कम दाम पर भोजन मिल रहा है।” उन्होंने फिर लिखा है कि “१९ वीं शताब्दी में उद्योगपति गिरे हुए गेहूँ के भाव के कारण ही जीवन-निर्वाह धन्य को अपेक्षाकृत कम कर अधिक मुनाफा कमा सका।”

“यूरोप के खेतिहरों ने १९२७ के “विश्व आर्थिक सम्मेलन” में इस बात की बड़ी शिकायत की कि उन्हें औद्योगिक वस्तुएँ ऊँचे भाव में खरीदनी पड़ती हैं और कृषि की वस्तुएँ बहुत ही कम दाम में बेचनी पड़ती हैं। इसकी वजह यह है कि उद्योगपतियों का तो कार्टेल, ट्रस्ट आदि के मार्फत विश्वव्यापी संगठन है, पर खेतिहर विश्व भर में बिखरे पड़े हैं। यही वजह है कि खेतिहर, उद्योगपतियों को बनिस्वत अधिक बुरी अवस्था में हैं।” विश्व कृषि रायल इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्टरनेशनल अफेयर्स नामक संस्था ने १९२५ से १९२७ ई० तक में जर्मनी के एक ऐसे जिले के छोटी पराजी वाले खेतिहरों की आर्थिक स्थिति की जाँच पड़ताल की, जिसमें ९८ प्रतिशत खेतिहर जमीन के मालिक हैं। अधिकांश खेतिहरों की आमदनी नकद मजदूरी करने वाले मजदूरों से कहीं कम थी और शत प्रतिशत खेतिहर औद्योगिक मजदूर से कम ही पाते थे। खेतिहर और

उनकी श्रीरत के दस घंटे रोज से ज्यादा और पतवार को भी घटने पर उनकी यह घुरी हालत है ।

सिद्धान्ततः किसी भी समय सर्वत्र एक ही दाम रहना चाहिये, किन्तु वस्तु-स्थिति यह है कि कहीं भी सच्ची मंडी नहीं है । मुद्रानीति, व्यापार एकाधिकार और राजकीय दस्त-शाली ने अग्र-व्यवस्था पर प्राधिपत्य तथा अनुशासन स्थापित कर रखा है । कृषि-जन्य-वस्तुओं का कम दाम प्रति की माँग से अधिक हो जाने के कारण नहीं होता है । पूँजीवाद को अपने आन्तरिक विरोध का मुकाबला करना पड़ना है और अपने गिरते हुए मुनाफे को रोकने के लिये कुछ न कुछ तात्कालिक युक्ति निकालनी पड़ती है तथा ग्रेटिहर पैदावार के उचित दाम को गिराकर, पूँजीवाद मुनाफा कायम रखता है ।

शुरू में दिये गये आँकड़ों को हल्ले कर नीचे दिया जा रहा है । यह तालिका प्रमाणित करती है कि रोटी की चीजों के दाम का स्तर कितना अन्यायपूर्ण ढंग से गिराकर रखा गया है :

१ १९४२ का दाम.....१०० :

खेतों की पैदावार की क्रय शक्ति का इन्डेक्स नम्बर

१९०१.....	९२	१९२०.....	६२
१९०२.....	१०५	१९२१.....	६८
१९०३.....	९७	१९२२.....	७४
१९०४.....	९४	१९२३.....	६५
१९०५.....	११०	१९२४.....	६४
१९०६.....	१२५	१९२५.....	८१
१९०७.....	११५	१९२६.....	८१
१९०८.....	१२५	१९२७.....	७०

किसानों की समस्याएँ

१९०९.....११७	१९२८.....८१
१९१०..... ९८	१९२९.....८६
१९११..... ९५	१९३०.....७१
१९१२.....१००	१९३१.....५०
१९१३.....११०	१९३२.....५०
१९१४.....११९	१९३३.....५३
१९१५..... ८६	१९३४.....५४
१९१६..... ६९	१९३५.....६१
१९१७..... ५०	१९३६.....६४
१९१८..... ४९	१९३७.....६४
१९१९..... ६७	

सत्य तो यह है कि खेतीहरों को १८७० से अबतक कुछ समय छोड़ कर उचित दाम मिला ही नहीं। बहुत से देशों के "रजत मान" की जगह स्वर्णमान स्वीकार कर लेने तथा दुनिया के खेती के कुल उत्पादन में कमी के कारण पिछले २० वर्षों से लेकर १८९६ तक दाम लगातार प्रतिशत गिरता रहा है। (रायल इन्स्टीट्यूट आफ इन्टरनैशनल अफेयर्स:) १९३० की मंदी ने तो किसानों की रीढ़ही तोड़ दी। हिन्दुस्तान में दाम गिरने का जिक्र पहले आ चुका है। अमेरिका में भी खेती की पैदावार का दाम उद्योग की पैदावार के दाम से कहीं ज्यादा तेजी से गिरा। अमेरिका के खेतीहरों ने जो दाम पाया और उन्हें जो दाम चुकाना पड़ा, उन दोनों का अनुपात १९०९ से १९१४ के आचार पर ४४ प्यान्ट गिर गया। राष्ट्रपति कुलिज ने दाम सतुलन के आभावको गिराने को लिये दो-दो बार वोटो का इस्तेमाल किया। आखिर राष्ट्रीय औद्योगिक-सम्मेलन-समिति द्वारा बनाया गया खेती के लिये व्यापारिक कमोशन और अमेरिका के "चैम्बरस आफ कामर्स" के सम्मेलन के वादही खेती के दामों को स्थिर करना

प्रारम्भ हुआ। अमेरिका की सरकार ने १९३८ में कानून बनाकर मूल्य संतुलन के सिद्धान्त को कबूल कर लिया।

अब तो दुनिया के प्रमुख राष्ट्रों ने मूल्य के संतुलन सिद्धान्त को मान लिया है। दंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत "आर्थिक प्रोग्राम कमिटी" की रिपोर्ट में भी, जिसे उन्होंने १९४८ की ए० आइ० सी० की बैठक में पेश किया था, लिखा है :-

"ऐसे साधनों का विकास हो, जिन से रोटी और गैर खेतों की पैदावारों का बराबरी के आधार पर परस्पर विनिमय चल सके। इसके लिये एक ऐसा संतुलित माप दंड तैयार करना चाहिये, जिससे रोटी, उद्योग, व्यापारिक तथा अन्य सामानों के दाम बराबरी के आधार पर निश्चित हो सके और रोटी की पैदावार को उचित दाम मिल सके।

इसकेलिये प्रो० रंगा, श्री जयप्रकाश नारायण और प्रो० दांत-वाला की इफ उपसमिति भी गठित की गई थी। सोशलिस्ट पार्टी ने पटना सम्मेलन में, अपने नौ-सूत्री कार्यक्रम को स्वीकार करते हुए मूल्य संतुलन के बारे में लिखा था, रोटी और औद्योगिक दामों के संतुलन के सिद्धान्त को स्वीकार करना चाहिये। फिर सोशलिस्ट पार्टी ने अपने चुनाव-मंच में, जिसे जेनरल कौन्सिल ने जुलाई ५१ को राची में कबूल किया, इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं: रोटी और औद्योगिक दामों के संतुलन की जिम्मेदारी राज्य पर होगी जिससे कि देश का शहर के द्वारा शोषण बन्द किया जा सके। जनता के अधिकार पत्र में भी, जो जनवाणी दिवस के अवसर पर भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति को पेश किया गया था, मूल्य-संतुलन की मांग रखी गयी।

यह स्मरण रखना चाहिये कि न तो यह गिरते हुए दामों को रोकने के लिए करोड़ रुपये खर्च करने का वादा है और न केवल मूल्यों को स्थिर रखने का ही। यह नीति सम्बन्धी घोषणा है। १९४७ में भी हुवर

किमानों की समस्याएँ

के आदेश पर अमरीकी सरकार के अन्न-विभाग के बयान के अनुसार यह रुपये की गारंटी नहीं है। यह व्यापारियों के चाहे की पाबन्दी भी नहीं है। यह सरकारी अन्न विभाग की रूखा नीति कि घोषण है कि खेतिहरों के प्रति रूपाय होगा। भारत सरकार की मौजूदा नीति के मुताबिक यह एक किस्म की “नकारात्मकता की नकारात्मकता” है। सरकार को खेतिहर दामों को जबरदस्ती गिराने की नीति छोड़ देनी चाहिये। डा० रामनोहर लोहिया ने अपने लेख “काम करने का प्रोग्राम” (जो १९४९ के मई महीने की अंग्रेजी जनता में प्रकाशित हुआ था) में इस विषय पर प्रकाश डाला है-

“चीजों के दाम, खास तौर से खेतिहर और औद्योगिक दामों के सम्बन्ध का सवाल कठिन है। व्यापार की शर्त हमेशा खेती के खिलाफ रहती है। चूंकि उद्योग के मालिक मुझे भर पूँजीपति है, उनमें एकता है और वे अपने दामों को गिराने से रोकते हैं। परन्तु खेतिहर चुप्पी साधकर अपने दामों की घटती बढ़ती देखते रहते हैं। खेतिहरों के पास कम मिल-कियत है और वे देश भर में बिखरे पड़े हैं। इस कारण खेतिहर के माल की कीमत में तेजी से गिरावट आती है। इस देश में वस्तुओं के दाम हाल के वर्षों में बहुत ऊँचे रहे हैं। जनता के शरीर और मन को सुख और सुविधा पहुँचाने के लिये दामों का गिरना अत्यावश्यक है। परन्तु दामों के गिरने में विषमता देखी जाती है। खेतिहर-दाम औद्योगिक दामों के मुकाबले में बड़ी तेजी से गिर रहे हैं। प्रांतीय सरकारों का यह रुख बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि किसी न किसी रूप में कम दाम पर जवरिया गल्ला बसूली जोरों से चल रही है। अमाव्यस्त क्षेत्रों में जरिया गल्ला बसूली करके तो अंधेरा ही दाढ़ा जा रहा है। औद्योगिक दामों के मुकाबले खेतिहर दामों के कम होने से, खेती की लागत का खर्च भी नहीं निकल सकेगा। यह केवल किसानों को ही तबाह नहीं करेगा, राष्ट्र

की अर्थ व्यवस्था को भी अस्त-व्यस्त कर देगा। तोड़-फोड़ करने वाली पार्टियाँ इस राजनीति से लाभ उठाकर, देश में अराजकता फैलायेंगी, इस संकट को टालने के लिये खेतिहर तथा औद्योगिक दामों के संतुलन के सिद्धान्त को अवश्य ही कबूल कर लेना चाहिये। और दाम कम करते समय इस संतुलन को हरगिज न तोड़ा जाय। यद्यपि मूल्य-संतुलन के लिये समुचित और लगातार खोज की जरूरत है, फिर भी यह काफी औचित्य के साथ कहा जा सकता है कि कपड़े के भाव को छः आने गज लाकर ही धान तीन चार आने सेर, और गेहूँ चार पाँच आने सेर के भाव से घसूना जाय। दूसरी औद्योगिक चीजों के साथ भी ऐसा ही संबंध स्थापित किया जाय। दस वर्ष पहले कपड़े और धान के दामों में ब्योढ़ा का फर्क था, आज यह तिगुना हो गया है। ऐसी हालत में औद्योगिक दामों को ही कम करना चाहिये था। किन्तु इसका उल्टा मुकाब हो रहा है। यह निश्चय ही उद्योगों को घूस देकर खुश करने की नीति है। मूल्य संतुलन तत्काल लागू हो।”

यह स्मरण रहे कि हमलोग पूरी या आंशिक रूप से योजनाबद्ध अर्थ प्रणाली की बात कर रहे हैं। रूस को कौन रोकता है? दुर्भाग्य से यूरोपीय समाजवाद उद्योग की देन है और वह उद्योगों का पक्ष लेता है। यही जबरदस्त बाधा है, जो खेतिहरों को न्याय से वंचित रखती है। प्रो० प्रीकोपोमिज के अनुसार रूस के खेतिहर भी औसत आमदनी, वहाँ के औद्योगिक मजदूर की औसत आमदनी से ५० प्रतिशत कम है। मूल्य के संतुलन-सिद्धान्त को मान लेने का अर्थ होता है दुनिया की अर्थ व्यवस्था में प्रधानता रखने वाले खेतिहरों को, पिछड़ी हुई स्थिति से उठाकर विज्ञान के प्रकाश में लाना।

जो व्यक्ति यह दलील देते हैं कि सस्ता गन्ना खेतिहर-मजदूरों तथा सीमान्तक खेतिहर के लिये जरूरी है और बढ़े हुए, दाम के आंतरिक गन्ना बेचने वाला का ही फायदा होता है, वे यह भूल जाते हैं कि हमारी

किसानों की समस्याएं

मांग दाम को बढ़ाने की नहीं है, बल्कि खेतिहर और औद्योगिक दामों को संतुलित करने की है। उनका कहना भी तभी सार्थक हो सकता है जब खेती को इस लायक बना दिया जाय कि किसान खेत में खटने वालों को ज्यादा मजूरी दे सके, नहीं तो उनके कथन में कोई जोर नहीं।

कुछ लोग ऐसी दलीलें भी देते हैं कि मुख्य-संतुलन को लागू करने से पूँजी की वृद्धि पर कुछ असर पड़ेगा। इस कथन के तर्क और औचित्य मेरी समझ में नहीं आते। अगर इसका यह अर्थ है कि खेतिहरों को आधा पेट खाना इसलिये दिया जाय कि उद्योगों को मुनाफा बढ़ाने के लिये कम मजदूरी देनी पड़े और सस्ते कच्चे माल मिल सकें, तब यह कम दाम के जाल में दिहात को फँसाकर उसका अधिक शोषण करना होगा। यह विनाशोन्मुख पूँजीवाद के लिए, अपने गिरते हुए मुनाफे को बढ़ाने की एक चाल है। इतना तो सत्य है कि भारत जैसे देश में उद्योग बढ़ाने के लिये उपभोग को उन्मूलक कम करने की सख्त जरूरत है। इसका मतलब होता है दस या अधिक वर्षों तक कठिन जीवन व्यतीत करना और अपनी जरूरतों को जबरन दबाना। इसके सिवा समाजवाद लाने का कोई दूसरा रास्ता भी मौजूद नहीं है। किन्तु पूँजी की वृद्धि का यह अर्थ हरगिज नहीं होता है कि बम्बई के उद्योग फर्म के लाखों मजदूरों को शहरी पगडण्डियों पर मुलायम और उनकी मंहमाई का भत्ता तथा घोनस छद्म कर दे। सच किसी को बराबरी के आधार पर त्याग करना होगा। खेतिहर ही समाज के अन्य हिस्सों से ज्यादा तकलीफ क्यों उठावें ?

यह सत्य है कि खेतिहरों के जीवन-यापन का स्तर केवल मूल्य संतुलन से ही ऊँचा नहीं उठेगा। खेती में सुधार, नयी खेती, पैदावार की वृद्धि, खेती पर के बोझ की कमी आदि बातें सत्काल जरूरी हैं। साथ ही बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या का, जिसके कारण जीवन यापन के स्तर को उठाने के समस्त आर्थिक प्रयत्न विफल हो रहे हैं, शीघ्र समाधान होना चाहिये।

समाजवाद और किसान

समाजवादी पुनर्निर्माण के साथ किसान-आन्दोलन का क्या सम्बन्ध है, इसे सिद्धान्त और व्यवहार, दोनों दृष्टियों से समझना प्रत्येक समाजवादी के लिये अत्यन्त आवश्यक है। एक तो यह प्रश्न यों ही पेचीदा है और फिर हिन्दुस्तान की परिस्थिति ने इसे और भी गम्भीर बना दिया है। पिछले १०० वर्षों के दरम्यान इस प्रश्न के ऊपर में यूरोप के समाजवादियों में बराबर मतभेद रहा है। याद रहे समाजवाद रचना और संघर्ष दोनों है। समाजवादी समाज की रूपरेखा क्या होगी, इसके साथ-साथ यह भी सोचना पड़ता है कि समाजवादी क्रान्ति के संघर्ष में कौन-कौन सी जमातें क्रान्ति में शामिल होंगी। क्रान्तिकारी-संघर्ष की आवश्यकता को छोड़ कर केवल सिद्धांत का निर्णय निरपेक्ष होता है। मुख्य प्रश्न समाजवादी समाज का चित्र बताना नहीं, बल्कि संघर्ष के मैदान में उतर कर 'समाजवादी' समाज का निर्माण करना है।

यूरोप की औद्योगिक-क्रान्ति के बीच समाजवाद का जन्म हुआ। यों तो जब से आदिम समाजवादी-समाज दृष्ट, तब से ही स्वप्नों के रूप

किसानों की समस्याएँ

में समानता की भाषना मनुष्य के हृदय को हिलाती रही, परन्तु ऐसे समाज की आर्थिक सम्भावना नहीं रहने के कारण, ये स्वप्न कवियों और महा-पुरुषों की छाँह बन कर विश्व के अन्तरिक्ष में विलीन होते रहे। १९ वीं सदी के मिशन और औद्योगिक विकास ने मानव के इस चिर-स्वप्न के मूल होने की सम्भावना पैदा की। इस सदी के प्रारम्भ में पहिले इंग्लैंड होर्सेड और फ्रान्स के कुछ हिस्सों में, पीछे चलकर क़रीब-क़रीब सारे यूरोप ने इस स्वप्न को गढ़ने वालों की पीढ़ को कारख़ानों के मजदूरों के रूप में स्थापित कर दिया। क्रांतिकारियों ने देखा एक और करोड़पति; दूसरी ओर कारख़ाने के मजदूरों का जन समूह। १९ वीं सदी का पूरा १०० वर्ष एक तरह से यूरोप के किसानों को कारख़ानों के मजदूरों में परिवर्तित करने का काल कहा जा सकता है। इंग्लैंड में पूरा चक्का ठरल गया। सदी के प्रारम्भ में किसानों की आबादी जो ९० प्रतिशत थी, वर सदी के समाप्त होते-होते १० प्रतिशत रह गयी।

यूरोप के समाजवादी क्रांतिकारियों ने यह ठीक ही समझा कि यही कारख़ाने के मजदूर समाजवाद के बाइक होंगे। मजदूर पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी पदार्पणची शब्द बन गये। समाजवादी क्रांतिकी पद्धति में प्रधान ही नहीं, क़रीब-क़रीब सब कुछ ही मजदूरों की जमात रही। इसलिये, उनके सामने किसानों का प्रश्न गौण ही था। फिर भी पूर्वीय यूरप और कुछ ऐसे देशों में जहाँ किसानों की बड़ी क़दाद थी, वहाँ के लिये किसान नीति सम्बन्धी प्रश्न उठते रहे। परन्तु ऐसे प्रश्नों का एक ही दृष्टिकोण था। मजदूरों के समाजवादी दृष्टिकोण में कौन उनका सहायक बनेगा—? इस दृष्टिकोण से मोटे तौर पर लेनिन ने किसानों को निम्न लिखित दृष्टिकोणों में विभाजित किया:—

- (१) बड़े ज़मींदार या जागीरदार
- (२) चली किसान

- (३) मध्यम किसान
- (४) अर्ध किसान,
- (५) खेत मजदूर

पहला टुकड़ा हमारा दुरमन है, अन्तिम हमारा साथी, यह मोटे तौर पर सभीने मान लिया है। बीच वाले ३ टुकड़ों के बारे में बहस चलती रही, और आज भी जारी है। इनमें भी धनी किसान को दुरमन की कतार में रखा जाय और गरीब किसान तथा अर्ध किसान को साथी बनाया जाय, यह भी अधिकतर लोगोंने मान लिया है। परन्तु मध्यम-किसान के साथ समाजवादी पार्टियों का कैसा नाता हो, इस बारे में भूख के समाजवादियों में कभी भी एकता नहीं हुई, हमारे देश के समाजवादियों में भी इस प्रश्न पर काफी यहल चल रही है। खेत मजदूरों से, गरीब-किसानों से और मध्यम-किसानों से हमारा कैसा नाता हो, इस पर हिन्दुस्तान के सभी हिस्सों में हृदय-मंथन हो रहा है। इसलिये इस प्रश्न को अच्छी तौर से समझ लेने की आवश्यकता पैदा हो गई है।

सबसे पहिले हमें इस बड़े अन्तर को याद रखना है कि हिन्दुस्तान के समाजवादियों को सिर्फ मजदूर पार्टी नहीं बनानी है। यहाँ की समाजवादी पार्टी किसान, मजदूर और क्रांतिकारी बुद्धिजीवियों की पार्टी होगी। एशिया के किसी भी हिस्से में कोई भी सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट पार्टी विद्युद्ध मजदूरों की पार्टी नहीं है। क्रांति की दृष्टि से ऐसा प्रयास करना पूरे तौर पर निरर्थक होगा। इस बात को माथोत्सेव्स्की ने बहुत पहिले समझा था और साहस के साथ कम्युनिस्ट-आन्दोलन को किसान क्रांति के ढाँचे पर ढालने का प्रयत्न किया था। हिन्दुस्तान के समाजवादियों के साथ यह प्रश्न नहीं है कि मजदूरों का कौन सहायक बनेगा। प्रश्न है मजदूर और गरीब किसानों के सम्मिलित माथे के साथ समाजवादी निर्माण में उनका कौन सहायक होगा? चीन और हिन्दुस्तान में गाँव

किसानों की समस्याएँ

के गरीबों का बड़ा हिस्सा किसी का सहायक बन कर नहीं, कान्ति का आधार बन कर खड़ा है। एशिया में पूँजीवाद की कत्र खोदनेवाला सबसे बड़ा समूह खेत-मजदूरों का है। इस अन्तर को याद रख कर ही हमें इस देश की समाजवादी क्रांति की नीति (पालिसी) और पद्धति (स्ट्रेटजी) का निर्माण करना चाहिये।

याद रहे, कारखानों के मजदूरों का, चाहे उनकी तादाद कितनी भी छोटी हो, एक निर्णायक स्थान है। इनको छोड़कर समाजवादी क्रांति की कल्पना ही नहीं की जा सकती। परन्तु हिन्दुस्तान के किसानों को भारतीय समाजवादी क्रांति में कारखानों के मजदूरों के साथ प्रधान स्थान लेना होगा।

किसान व्यक्तिवादी होता है और दृढ़पुट तरीके से सपर्य करता है। लेकिन इन कमजोरियों के बावजूद इतिहास में उसका पाठ निर्णायक रहा है। यही व्यक्तिवादी भावना एक अप्रति किसान को अराजकतावादी बना देती है। राजस्व और शक्ति के केन्द्रीयकरण की वह भृष्टा की दृष्टि से देखता है। समाजवादी चेतना-सम्पर्क किसान आगे चलकर समूहवाद और स्वतन्त्रता के बीच सच्चा संतुलन कायम रख सकेगा। परन्तु यह भी याद रखना होगा कि किसानों का समुदाय एक भावना से प्रेरित बग नहीं है। किसानों का घनी झुंझ हमारे साथ किसी तरह भी नहीं रह सकता। बल्कि उसके साथ विरोध की भावना तीव्र ही होती जायगी। यह घनी और शोषक ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान की विरोध परिस्थिति में व्यापक हिस्सों में सामाजिक दृष्टि से भी उँचा स्थान रखता है। यह भी आग्रह कामेसी सरकारों की नुम्यवस्था से असन्तुष्ट है, परन्तु वह समाजवाद का साथ नहीं दे सकता। उसको अपने साथ रखने के प्रयत्न में गाँव के गरीबों का बड़ा समुदाय हम से अलग हो जायगा। नतीजा होगा, न तो गाँव के गरीब हमें अपना समझेंगे और न गाँव के घनी

ही। त्रिशंकु की तरह गांव के, सामाजिक-जीवन में समाजवादी पार्टी लटकती रहेगी। इसलिये निश्चित रूप से समाजवादी कार्यकर्ताओं को इनका साथ छोड़ देना चाहिये।

लेनिन के विभाजन के अनुसार और उनके विचारों के मुताबिक नीचे की सतह की तीन टुकड़ों को यानी खेत-मजदूर, गरीब किसान और अर्थ-किसान को, जिनकी तादाद गांव की ८० प्रतिशत से कम नहीं है, हमें अपना आचार बनाना चाहिये। हमारा किसान-संगठन दर असल ईन्हीं की संस्था हो। धीरे-धीरे किसान संगठन के रूप को हमें इस तरह बदलना है कि वह गांव के गरीबों की संस्था बन जाय। इसका अर्थ होगा, पुराने अर्थ में किसान-समा जैसी कोई चीज न रहेगी। पुरानी किसान-समा या हिन्द-किसान-पंचायत और नये संगठन में बड़ी गहरी खाई होगी।

कोई यह पूछ सकता है कि फिर इसे किसान समा या किसान पंचायत कहने का क्या हक है और किसान पंचायत कह कर गांव के गरीबों के बड़े समुदाय को हम क्या अपने से अलग नहीं करते हैं? यह एक प्रायज प्रश्न है। सही अर्थ में जब हिन्द किसान पंचायत खेत समझीवियों की संस्था बन जायगी तब इसका नाम भी बदल कर खेत-मजदूर-पंचायत या खेत समझीवि पंचायत रखा जाना चाहिये।

परन्तु यहाँ प्रश्न यह है कि गांव के गरीबों की कतार को तोड़ देना क्या उचित होगा, और उन्हें तोड़ कर क्या हम क्रांति की शक्ति को देश में मजबूत बना सकेंगे? इसी प्रश्न को सामने रख कर हिन्द किसान पंचायत के समापति डा० राममनोहर लोहिया ने रीवा में कहा था:—

“किन्तु इस विशाल ऐतिहासिक-जनता के सम्बन्ध में वर्ग संघर्ष नहीं है। जो है वह दलगत तनावनी है, जो अक्षर अत्यन्त निर्मम रूप ले लेती है। गरीबों के बीच की यह तनावनी गांवों को वर्णहीन और सह-

किसानों की समस्याएं

कारिता के आधार पर संगठित किये जाने से काफी दूर तक दूर की जा सकती है। यदि यह वनावनी बड़े संघर्ष का काल्पनिक रूप ले लेगी और किसानों के हितों के लिये आंदोलन करने वाले यदि कारखानों के मजदूर-धंदों की परम्परा की नकल करेंगे, तो इससे बहुत बड़ी क्षति होगी। उदाहरण के लिये चेतिहर मजदूरों के संगठन की व्यापक किसान आंदोलन का ही अंग बनाना होगा। यह सही है कि आदर्श गांव की स्थापना के इन दोनों सिद्धान्तों को (क), खेत जोतने वाले का और (ख) 'बर्ष' का अस्तित्व नहीं रहना चाहिये, कमी दृष्टि से ओम्फन नहीं करना चाहिये।

सच पूछा जाय, तो आर्थिक दृष्टि से गरीब किसानों में और खेत मजदूरों में कोई अन्तर नहीं। इनमें शोषक और शोषित की भावनाओं को पैदा करना क्रांति की शक्ति को कमजोर करना होगा। हमारे चारों मशहूर नारे—

- (१) जमीन को फिर बाँटेंगे
- (२) जात-पात को तोड़ेंगे।
- (३) मिल कर खेत को जोड़ेंगे, और
- (४) जोतने वाला काटेंगा

ऐसे हैं जो गांव के सभी गरीबों के लिये लागू होंगे। इस प्रोग्राम को, गरीबों के डुकड़ों को संगठन की एक दारी में बांधे बिना, पूरा नहीं किया जा सकता। इसी नतीजे पर माओसेतु ग भी चीन में पहुंचे थे और इसी नतीजे पर सोशलिस्ट-पार्टी और हिन्द किसान पचायत की सम्मिलित बैठक भी पहुंची, जो रीवा में २६ फरवरी, १९५० में हुई थी।

इस सम्मिलित बैठक का यह मुद्दा फैसला था—

‘गिन गांवों में गरीब किसानों तथा खेत मजदूरों की मिली-जुली आवादी हो, वहाँ उनका संगठन हिन्द किसान पचायत के नीचे किया जाना चाहिये।’

अन्य प्रकार के खेत मजदूरों के संगठन के सम्बन्ध में सम्मिलित बैठक में यह निश्चय हुआ था कि —

(१) औद्योगिक फ़ार्मों के मजदूरों को अलग से संगठित कर उस संगठन को हिन्दू-मजदूर-सभा से सम्बद्ध करा दिया जाय ।

(२) सरकारी तथा अन्य बड़े फ़ार्मों पर काम करनेवाले मजदूरों का संगठन भी अलग से ही किया जाय, लेकिन उनके संगठनों को हिन्दू-किसान पंचायत से सम्बद्ध करा दिया जाय ।

(३) जिन गाँवों में मजदूरों की ६० प्रतिशत या इससे अधिक संख्या हो, वहाँ खेत-मजदूर-पंचायतें संगठित की जायँ तथा उन्हें हिन्दू-किसान पंचायत से सम्बद्ध करा दिया जाय ।

खेत मजदूरों की कुल संख्या का, १० प्रतिशत से कम ही उपर्युक्त तीन विभागों में रहता है । अतः इस फैसले के आधार पर खेत मजदूरों की बहुत बड़ी संख्या सीधे किसान संगठन के दायरे में चली आती है । इसलिये किसान मोर्चे पर काम करने वाले समरजवादियों की यह नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि वे किसान संगठन के स्वरूप को इस प्रकार बदल दें कि खेत मजदूर और गरीब किसानों के हृदय में यह भावना पैदा हो सके कि किसान संगठन उनका अपना संगठन है ।

इस दृष्टिकोण को मान लेने पर किसान संगठन और मजदूर संगठन में एक जीवित सम्बन्ध कायम हो जाता है और इस सम्बन्ध को वैधानिक रूप देने के प्रश्न पर भी हमको सोचना पड़ेगा परन्तु इस मौलिक दृष्टिकोण को यदि समाजवादी छोड़ देंगे, तो क्रांति, की ओर इस देश की तेजी से नहीं बढ़ा सकेगी ।

अब प्रश्न उठता है कि मध्यम किसानों के साथ कौन-सा ठाठलुक रखा जाय ? यह प्रश्न काफी पेचीदा है — “ — — — — — ”
 डकड़ों के बीच, जिनमें एक तरफ़ लमी

बिस्तानों की समस्याएँ

दूसरी ओर गरीब किसान, अर्ध किसान और खेत मजदूर हैं, मध्यम किसान सटकता हुआ है। यह कमी धनियों की ओर देखता है और कमी गरीबों की ओर। इसके सम्बन्ध में २३ मार्च १९१९ को रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए लेनिन ने कहा था :—

“मध्यम किसानों के साथ कैसा व्यवहार रखा जाय, इसकी सफाई बहुत जरूरी है। परन्तु यह प्रश्न बहुत पेचीदा है, इसलिये कि परिस्थिति में ही पेचीदापन है। अब तक यह प्रश्न सुलभता नहीं, और न सुलभता वाला ही है।.....परन्तु यह स्पष्ट है कि इनके साथ किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती आज नहीं की जा सकती। सामूहिक कामों में आने से वे घबकाते हैं, यह उनकी गलती है। परन्तु उन्हें धीरे-धीरे समझाना होगा और सामूहिक कामों में लाने को राजी करना होगा। यदि कोई समाजवादी यह समझता हो कि इनके साथ आर्थिक सम्बन्ध में हम शक्ति प्रयोग कर अपने उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं।”

यह सत्य है कि यह प्रश्न व्यवहार में ही सुलभ होगा जैसा कि लेनिन ने कहा था। परन्तु आज की परिस्थिति में इनसे भ्रम का मोल लेकर देश में हम क्रांति की शक्ति को कमजोर करेंगे। इस लिये गाँव के गरीबों की संस्था जिस नाम से खड़ी हो, उसे इन किसानों को भी अपने साथ ले चलने का पूरा प्रयत्न करना होगा। इस दृष्टि से गाँव के गरीबों की संस्था का नाम हिन्द किसान पंचायत रहे, तो हमारे काम में ज्यादा सुविधा होगी। साथ साथ हम जिस व्यवस्था की कल्पना कर रहे हैं, उस व्यवस्था में या तो सभी किसान होंगे अथवा खेत मजदूर। सहयोगी-देवी ही यदि हमारा प्रधान आधार हो, तो उसमें काम करनेवालों को हम क्या कहेंगे? क्या यह बेहतर नहीं होगा कि आज से ही गाँव के करोड़ों गरीबों के दिल में इस बात को बैठाया जाय कि जिस ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था

की कल्पना हम कर रहे हैं उसमें सहयोग-समिति के वे ही प्रतिष्ठित सदस्य होंगे, जो सहयोग-समिति द्वारा जमीनों के मालिक होंगे और खेतिहर मजदूर की उनकी जिन्दगी सदा के लिये खत्म हो जायगी। यदि यह हमारी कल्पना है, तो किसान-पञ्चायत के नाम से ही देश के करोड़ों गरीबों का संगठन करना क्या अच्छा नहीं होगा ? परन्तु, जैसा मैंने ऊपर कहा है, यदि इस संस्था का नाम खेत-मजदूर-पञ्चायत रहे, तो इसमें मुझे कोई एतराज नहीं होगा। परन्तु, गांव के गरीबों की दो संस्थाएँ अलग अलग हों और उनमें आपस के संबंध की कल्पना और सम्भावना हो, तो यह क्रान्ति के लिए खतरनाक चीज है। किसान-आन्दोलन को शक्तिहीन बनाने के उद्देश्य से ही विभिन्न राज्यों में खेत-मजदूरों का अलग संगठन खड़ा करने का कार्य कांग्रेसी-मन्त्रियों ने आरम्भ कराया है।

उपयुक्त दृष्टिकोण का अर्थ होगा, किसान-पञ्चायत के कार्य-कर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा खेत मजदूरों और गांव के अघपेटे, अघ-नंगे गरीब किसानों के पास जाना और उनके दिल में बैठाना कि हिन्द-किसान-पञ्चायत उनकी संस्था है। यह काम आज कठिन मालूम पड़ता है, परन्तु याद रहे, इतिहास सस्ते रास्तों से मुहन्वत नहीं करता है।

उपयुक्त दृष्टि से सही किसान नीति के निम्नलिखित आधार होंगे—

(१) देश की जनशक्ति की तीन चौथाई और प्रारम्भिक साधनों की दो-तिहाई के खेती में लगे रहने के कारण, कृषि हमारे जीवन का आर्थिक केन्द्रबिन्दु बन गई है। विदेशी-साम्राज्यवाद के लगान, सूद और मुनाफे के त्रिविध शोषण, गृह-उद्योगों के विनाश और आन्तरिक कमजोरियों के कारण विगत २०० वर्षों से हिन्दुस्तान के किसान इस कदर पामाल हो गये हैं कि उनके लिये अपने प्राण और प्रतिष्ठा की रक्षा करना आज कठिन हो गया है। कार्यकुशलता एवं न्याय, दोनों दृष्टियों

विमानों की समस्याएँ

से हमारे सामाजिक-जीवन के इस हिस्से का जीवन-स्तर बहुत ही नीचे गिर गया है। इनके अघ-पतन ने राष्ट्र के आर्थिक ढाँचे को, पतन की गहरी खाई में डाल दिया है। समाजवाद की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि वर्तमान राजनीति की अस्वाम्याधिक शहरी - सभ्यता को पलट कर गाँव तथा गाँव के गरीबों की ओर कर दिया जाय।

(२) हिन्दुस्तान की गरीबी की समस्या बढ़ती हुई आबादी और गिरते हुए उत्पादन की समस्या है। दुनिया के १५^५ प्रतिशत आबादी की समस्या को दुनिया के कुल रकबे के २^४ प्रतिशत हिस्से में हल करने की मौलिक समस्या हमारे सामने है।

दुनिया की जमीन का रकबा	३२६० करोड़ एकड़
दुनिया की आबादी	२२६ करोड़ ,,
हिन्दुस्तान का रकबा	८० करोड़ ,,
हिन्दुस्तान की आबादी	३५ करोड़ ,,

इस भयानक असंतुलन को संतुलित किये बिना राष्ट्रोद्धार की कोई भी नीति सफल नहीं हो सकती। जनता के जीवन-स्तर को ऊपर उठाने के लिये किये गये सभी प्रयत्न तब तक असफल होते रहेंगे जब तक आबादी की बढ़ती को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाय। गत ५० वर्षों में एक और जहाँ कुल एक करोड़ एकड़ जमीन खेती के अन्दर लायी गयी है, वहीं दूसरी ओर इस अर्ध में देश की आबादी आठ करोड़ बढ़ गई है। इस प्रकार प्रति व्यक्ति ७/१० एकड़ भूमि आज खेती के अन्दर है। आज हमारे सामने गरीबी की नहीं, बल्कि बढ़ती हुई है गरीबी की समस्या है।

(३) देश की बढ़ती हुई आबादी की समस्या के अतिरिक्त औपनिवेशिक पूँजीवाद ने हिन्दुस्तान के औद्योगीकरण को रोक रखा है। प्राकृतिक तथा आर्थिक कारणों से मजबूर होकर, देश की जनता की अधिकाधिक संख्या को जमीन की ओर जाना पड़ा। जमीन पर

आवादी का बोझ बढ़ता गया और उसके साथ-साथ जनता की गरीबी भी बढ़ती गई। नीचे के आंकड़ों से यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है:-

आंकड़ा

साल	जमीन पर जन-संख्या का बोझ
१८९१	६१.१ प्रतिशत
१९०१	६५.५ "
१९११	७२.२ "
१९२१	७३.० "
१९३१	७५.० "

(४) लेकिन इतने से भी किसानों की गरीबी का सच्चा चित्र हमारे सामने नहीं आता। ७५ प्रतिशत कृषककारों के पास अपनी कोई जमीन नहीं है। खेती पर निर्भर रहनेवाली विभिन्न श्रेणियों का एक खाका हम नीचे दे रहे हैं। (१९३१ ई० की जनगणना के आधार पर)

वर्गश्रेणी	१९३१ में प्रतिशत	आज का अनुमानित प्रतिशत	अनुमानित प्रतिशत के आधार पर जनसंख्या करोड़ लाख
(१) कृषककारी नहीं करनेवाले जमीन-मालिक	२.३	५	१.७५
(२) कृषककारी करनेवाले जमीन-मालिक	१७.४	१६	५.६०
(३) रैयत	२२.१	२५	८.७५
(४) खेतिहर-मजदूर	२०.१	२२	७.७०
(५) अन्य	४५	४	१.४०

कुल:- ६६.४

७२

२५.२०

(प्रतिशत तथा जनसंख्या मोटे तौर पर दिये गये हैं)

(१५) जमीन की मालगुजारी का एक रास्ता हिस्सा या जहाँ कहीं सम्भव हो, मालगुजारी की पूरी रकम तक ग्राम-पंचायतों के हवाले कर देनी चाहिये । आयकर के आधार पर मालगुजारी भी वसूल की जानी चाहिये । आमदनी के आधार पर, कम आमदनी वाले को मालगुजारी की मफ़ी और बढ़ती हुई आमदनी पर मालगुजारी की रकम अनुपाततः बढ़ा कर बाँधनी चाहिये ।

(१६) यह बात साबित हो चुकी है कि पूँजीशक्तियों ने मुनाफ़े की गिरती हुई दर को रोकने के लिये खेती की पैदावार के मूल्य को कारखाने की पैदावार के मूल्य के मुकाबले में कम करके रखा है । इस प्रकार के मूल्यों द्वारा किसानों का भयकर शोषण किया गया है । दूसरी ओर कारखाने के मजदूरों तथा निम्न मध्यम वर्ग के लोगों की मलाई के लिये आवश्यक वस्तुओं के मूल्य को कम करना जरूरी है । इसका निदान सिर्फ़ इसी में है कि खेती की पैदावार और औद्योगिक पैदावार के मूल्य में ग्याम्यवुक्त संतुलन कायम किया जाय ।

(१७) राज, समाज और ईश्वर द्वारा उपेक्षित खेत-मजदूर जिन्हें हम समाज की रीढ़ मानते हैं, आज दासता की अवस्था में पशुधत जीवन व्यतीत कर रहे हैं । गुलामी के बन्धनों के सिवा उनके पास और अपना है ही क्या ! भगवान के मन्दिर का दरवाजा भी उनके लिये बन्द है । जमीन तो उनके पास है ही नहीं । उनकी भोपड़ी भी दूसरों की मर्जी पर खड़ी है । समाज के इन परित्यक्त पुत्रों को अधःपतन की गहरी खाई से ऊपर उठाने के लिये आज सभी सम्भव कोशिशें होनी चाहिये ।

(१) इनके सभी नये पुराने कर्ज मंखूख कर दिये जायँ,

(२) इन्हें काम करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिये,

(३) इनकी कम से कम मजदूरी तय कर देनी चाहिये,

(१८) सदियों की उपेक्षा और अत्याचार ने आज वनवासी आदिवासियों को युग की प्रगति से बहुत पीछे छोड़ दिया है । इस

किसानों की समस्याएं

की हुई स्थिति से उन्हें आगे बढ़ाने के लिये शिक्षा-प्रचार, सामाजिक सांस्कृतिक आन्दोलन आदि हर सम्भव प्रयत्न करना चाहिये।

(१६) इनके सामाजिक संगठनों को तोड़कर पुनः समूहवाद के धार पर उन्हें संगठित करने का प्रयत्न करना समय और शक्ति का अप्रयोग होगा। इसका सामाजिक संगठन अभी भी अद्विष्ट है। अतः इन्हें सामाजवादी व्यवस्था की ओर ले जाना चाहिये। केवल इसी प्रकार इनकी सुन्दर संस्कृति और सामाजिक मनोवृत्ति की रक्षा कर सकते हैं।

(२०) जंगल की सुरक्षा के लिये हर प्रकार की सम्मवचेष्टा होनी हिये। साथ ही उस पर आश्रित लोगों को उनकी जीविका की रंटी मिष्टानी चाहिये। सभी प्रकार की जंगली-पैदावार के व्यापार को दिवासियों की सहयोग समिति के अधिकार में देकर, इस समस्या की आसानी से हल कर सकते हैं।

(२१) हिन्दुस्थान के गांवों की स्थिति आज अत्यधिक सोचनीय एवं कलहपूर्ण है। जो थोड़ा भी सामाजिक जीवन अवशिष्ट रह गया है वह गांव की गैर-मजदूरा जमीन पर ही देखने को मिलता है। गांव के पारिवारिक-जीवन तथा गांव के रहनेवाले की आदतों पर गैर-मजदूरा-जमीन का बहुत ही गहरा असर पड़ता है। इसी गैर-मजदूरा जमीन पर गांव वाले अपनी भवेशियों को चराते हैं। गांव के बच्चे यहाँ खेलते हैं। यहाँ के तालाब में लोग स्नान करते तथा भवेशियों को जलाते हैं। इसी जमीन पर उगनेवाली घास से लोग अपने घोड़ों कावनी करते हैं तथा यहीं लायें बलाई तथा दफनायी जाती हैं। गांव के बच्चों, चारपायों, और बगीचों में जब गांव के नरनारी एकत्र होते हैं, उस समय गांव के सामूहिक-जीवन का थोड़ा आनन्द तो उन्हें मिल जाता है। लेकिन इस आनन्द को मात्र तालाबों, बगीचों, और चारपायों की संरक्षा तथा रक्षक पर निर्भर करती है। यदि

किमानों की समस्याएँ

(५) काश्तकारों में भी ७५ प्रतिशत वे लोग हैं जिनके पास ५ एकड़ से कम ज़ोत की जमीन है। आबाद जमीन का २५ प्रतिशत ऊपर के ५ प्रतिशत लोगों के हाथ में है। जमीन पर भारी बोझ के साथ-साथ जमीन के इस अंशम बँटवारे से स्थिति और भी असह्य बन गई है।

(६) उपर्युक्त समस्याओं के अलावे देश में प्रचलित काश्तकारी कानून के फलस्वरूप सरकार तथा जमीन जोतने वालों के बीच मध्यवर्तियों का एक जबरदस्त तबका बन गया है, तथा जमीन की लगान में असाधारण वृद्धि हो गई है। मार से लदी हुई इस देश की जमीन में अब ऐसी ताकत नहीं रह गई है कि यह काश्तकार और जमीन के मालिक दोनों का बोझ ढो सके।

(७) उपर्युक्त स्थिति तथा राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारणों के चलते किसान पूँजी और साधन विहीन हो गये हैं। उनके पास न तो खेती के लायक औजार हैं, न अच्छी खाद की व्यवस्था और न सिंचाई का ही कोई अच्छा प्रबन्ध है। वे आकाश के भरोसे खेती करते हैं और किसी तरह अपना दिन काटते जाते हैं।

(८) किसान केवल वर्ग मात्र ही नहीं, बल्कि राष्ट्र की आबादी का ७२ प्रतिशत है। उसका उत्थान राष्ट्र का उत्थान है। अतः आज हमें पुष्पनी प्राणियों से अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर राष्ट्र के नव-निर्माण के लिये नयी पद्धतियों का अनुसरण करना चाहिये।

(९) काश्तकारी कानून के जाल को ढोक कर हमें जमीन जोतने वालों तथा सरकार के बीच एक नया और छिपा सम्बन्ध स्थापित करना होगा। सभी प्रकार के मध्यवर्तियों को समाप्त करना आज अनिवार्य आवश्यक है। उन्हें मुआवजा देना, न तो उचित ही है और न सम्भव ही। देश का मौजूदा-विधान इस रास्ते में रुकावट पैदा करता है इसलिये उसमें भी आमूल-परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

(१८) प्रत्येक परिवार पर कम से कम १० एकड़ और अधिक से अधिक ३० एकड़ जमीन का पुनर्विभाजन इस प्रकार करना होगा कि हर परिवार को कम से कम १०० रुपये और अधिक से अधिक ३८० रुपये की मासिक आमदनी हो।

(१९) हम उपर्युक्त कार्यक्रम तब तक पूरा नहीं कर पायेंगे, जबतक जमीन पर आश्रित आबादी के एक हिस्से को वहाँ से हटा कर, कृषि तथा अन्य सहयोगी-उद्योगधंधे खोल कर, उन में नहीं लगा दें।

(२०) फिर भी गैर आबाद जमीन के एक बड़े हिस्से को जय शंकर खेती के अन्दर नहीं लाया जायगा, तब तक न तो अन्न समस्या हल होगी न जमीन की मांग ही पूरी की जा सकेगी और 'न लोगों का जीवन-स्तर ही ऊपर उठाया जा सकेगा। इस काम को पूरा करने के लिये खेतिहर-पलटन संगठित करना निवन्त आवश्यक है।

(२१) इसी प्रकार खेती के अन्दर की चौबीस फरोड़ एकड़ जमीन की पैदावार बढ़ाने के लिये पानी, खाद तथा अच्छे बीज आदि की व्यवस्था करनी भी जरूरी है। पूँजी विहीन वर्तमान कृषि व्यवस्था में काफी पूँजी लगा कर ही हम इस उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं।

(२२) संक्रमण काल में जबतक कि जमीन को षट्-बटाई पर लगाने से रोकना सम्भव नहीं हो, फास्टकारों के लिये दराली का हक और उचित लगान निर्धारित करना आवश्यक है। जहाँ जमीन का मालिक खेती में कोई हिस्सा नहीं रखा है, वहाँ उसे मालगुजारी की रकम के दुगुना से अधिक नहीं मिलना चाहिये। जमीन सम्बन्धी सभी प्रकार के झगड़ों का अन्तिम निर्णय करने का अधिकार ग्राम पंचायत को मिलना चाहिये।

(१५) जमीन की मालगुजारी का एक हिस्सा या जहाँ कहीं सम्भव हो, मालगुजारी की पूरी रकम तक ग्राम-पंचायतों के इवाले कर देनी चाहिये । आयकर के आधार पर मालगुजारी भी वसूल की जानी चाहिये । आमदनी के आधार पर, कम आमदनी वाले को मालगुजारी की मफ़ी और बढ़ती हुई आमदनी पर मालगुजारी की रकम अनुपाततः बढ़ा कर बाँधनी चाहिये ।

(१६) यह बात साबित हो चुकी है कि पूँजीशक्तियों ने मुनाफ़े की गिरती हुई दर को रोकने के लिये खेती की पैदावार के मूल्य को कारखाने की पैदावार के मूल्य के मुकाबले में कम करके रखा है । इस प्रकार के मूल्यों द्वारा किसानों का भयंकर शोषण किया गया है । दूसरी ओर कारखाने के मजदूरों तथा निम्न मध्यम वर्ग के लोगों की भलाई के लिये आवश्यक वस्तुओं के मूल्य को कम करना जरूरी है । इसका निदान सिर्फ़ इसी में है कि खेती की पैदावार और औद्योगिक पैदावार के मूल्य में न्याययुक्त संतुलन कायम किया जाय ।

(१७) राज, समाज और ईश्वर द्वारा उपेक्षित खेत-मजदूर जिन्हें हम समाज की रीढ़ मानते हैं, आज दासता की अवस्था में पशुवत जीवन व्यतीत कर रहे हैं । गुलामी के बन्धनों के सिवा उनके पास और अपना है ही क्या ? भगवान के मन्दिर का दरवाजा भी उनके लिये बन्द है । जमीन तो उनके पास है ही नहीं । उनकी भौपड़ी भी दूसरों की मज़ी पर खड़ी है । समाज के इन परित्यक्त पुत्रों को अधःपतन की गहरी खाई से ऊपर उठाने के लिये आज सभी सम्भव कोशिशें होनी चाहिये ।

(१) इनके सभी नये पुराने कर्ज मंखल कर दिये जायँ,

(२) इन्हें काम करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिये,

(३) इनकी कम से कम मजदूरी तय कर देनी चाहिये,

(१८) सदियों की उपेक्षा और श्रमत्याचार ने आज बनरासी आदिवासियों की युग की प्रगति से बहुत पीछे छोड़ दिया है । इस

पिछड़ी हुई स्थिति से उन्हें आगे बढ़ाने के लिये शिक्षा-प्रचार, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आन्दोलन आदि हर सम्भव प्रयत्न करना चाहिये ।

(१९) इनके सामाजिक-संगठों को तोड़कर पुनः समूहवाद के आधार पर उन्हें संगठित करने का प्रयत्न करना समय और शक्ति का अप-व्यय होगा । इसका सामाजिक संगठन अभी भी अक्षिप्त है । अतः इन्हें सीधे सामाजवादी व्यवस्था की ओर ले जाना चाहिये । केवल इसी प्रकार हम इनकी सुन्दर संस्कृति और सामाजिक मनोवृत्ति की रक्षा कर सकते हैं ।

(२०) जंगल की सुरक्षा के लिये हर प्रकार की सम्भव चेष्टा होनी चाहिये । साथ ही उस पर आश्रित लोगों को उनकी जीविका की गारंटी मिलनी चाहिये । सभी प्रकार की जंगली-पैदावार के व्यापार को आदिवासियों की सहयोग समिति के अधिकार में दे कर, इस समस्या की हम आसानी से हल कर सकते हैं ।

(२१) हिन्दुस्तान के गांवों की स्थिति आज अत्यधिक सोच-नीय एवं कलहपूर्ण है । जो थोड़ा भी सामाजिक जीवन अवशिष्ट रह गया है वह गांव की गैर-मजदूरा जमीन पर ही देखने को मिलता है । गांव के पारिवारिक-जीवन तथा गांव के रहनेवाले की आदतों पर गैर-मजदूरा-जमीन का बहुत ही गहरा असर पड़ता है । इसी गैर-मजदूरा-जमीन पर गांव वाले अपनी मवेशियों को चराते हैं । गांव के बच्चे यहीं खेलते हैं । यहीं के तालाब में लोग स्नान करते तथा मवेशियों को जल पिलाते हैं । इसी जमीन पर उगनेवाली घास से लोग अपने घरों की छ्दावनी करते हैं तथा यहीं लाये जलाई तथा दफनायी जाती हैं । गांव के तालाबों, चारागाहों, और बगीचों में जब गांव के नरनारी एकत्र होते हैं, उस समय गांव के सामूहिक-जीवन का थोड़ा आनन्द वो उन्हें मिल जाता है । लेकिन इस आनन्द की मात्रा तालाबों, बगीचों, और चारा-गाहों की संस्था तथा रकवे पर निर्भर करती है । लेकिन आज गांव की

किसानों की समस्याएँ

गैर-मजदूरा-ग्राम जमीन, जमीन की बढ़ती हुई भूल तथा जमींदारों की आर्थिक लिप्सा का शिकार बन चुकी है। इस प्रकार की समग्र गैर-मजदूरा-जमीनों को फिर से लौटाना जरूरी है।

(२२) पूंजी, खरीद-बिक्री तथा खेती की आवश्यकता की पूर्ति के लिये गांवों में समग्र गांव-सहयोग-समितियों का जाल बिछाना होगा।

(२३) सहयोग समितियों के साथ मिलकर ग्रामपंचायतें गांव की जनता को स्वायत्त-शासन दे सकेंगी। समी प्रकार के शोषण एवं उत्पीड़न का अन्त कर प्रजातन्त्र के आधार पर संगठित ग्रामीण-जीवन का धारम्भ, सहयोग-समिति और ग्राम पंचायत के झंडे के नीचे ही होगा।

(२४) लेकिन यह भी सत्य है कि सदियों से उपेक्षित भारतीय कृषि-व्यवस्था में शक्ति तथा नवजीवन संचार करने का कार्य केवल सरकार के बल पर ही पूरा नहीं किया जा सकता। नये हिन्दुस्तान के निर्माण के लिये गांव की जनता को प्रति दिन एक घंटा शारीरिक श्रम देना होगा। शिक्षा, रचना, संगठन, और संघर्ष के कार्यक्रम को एक साथ लेकर चलना होगा।

(२५) इस महान कार्य को पूरा करने के लिये किसानों की एक स्वतंत्र वर्ग-संस्था की आवश्यकता है।

(२६) समाजवादीसर्दों और किसान संगठन दोनों संस्थाओं में एक पारस्परिक जीवित सम्बन्ध स्थापित करना होगा जिससे दोनों को एक दूसरे से बल मिले।

(२७) किसान अगर कुछ करना चाहता है, तो उसे भी पूरे तौर पर संगठित होना होगा तथा अपने घरों की सफाई करनी होगी। आज जो समाज में ऊंच-नीच का भेद-भाव है, उसे पूरे तौर पर भुला देना होगा। नये समाज की रचना के लिये जिसमें सामाजिक भेद-भाव न हो, समाजवादियों को जोरदार संघर्ष करना पड़ेगा। वर्ग-विहीन, तथा जाति-विहीन समाज की स्थापना के अनन्तर ही नयी संस्कृति पैदा हो सकती है।

कल्पना

साहित्यिक तथा साम्प्रतिक मासिक पत्रिका

(मद्रास, राजस्थान, मध्यप्रदेश, बिहार एवं हैदराबाद की सरकारों द्वारा
मान्य एवं स्वीकृत)

८३१ चैगमवाजार, हैदराबाद दक्षिण

वार्षिक १२) शारदा—२०, हमाम स्ट्रीट बम्बई १ एक प्रति १)

सोशलिस्ट पार्टी का प्रमुख साप्ताहिक पत्र—

संघर्ष

हर सप्ताह संघर्ष में पढ़िये सवाल जवाब, राजनीतिक सचरें, राजनीतिक
झगरी, अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा, विभिन्न प्रान्तों की चिठियां

संघर्ष का चन्दा—८) सलाना ।

— जफ रोड, लखनऊ

आपकी सेवा के लिये एकमात्र—

साही फार्मैसी

हॉस्पिटल रोड, लहेरियासराय ।

अंग्रेजी दवाखाना ।

स्टाकिस्ट—डी० डी० टी० ।



हमारे यहां स्ट्रैप्टामाईसीन,
पेनिसिलीन, ए० बी० टी० एच०,
आदि सब प्रकार की नई नई दवाएं
उचित मूल्य पर बिकती हैं ।

परीक्षा प्रार्थनीय—

(दवाखाना रात दिन खुला रहता है ।)

नयासमाज

गामी विशेषांक

“परिवार-नियोजन अग्र”

दिसम्बर १९५२ में प्रकाशित होगा ।

इसमें विश्व की आगामी और उमके
अनुपातम ग्याय की कमी, जीवन-तार
के गिरने, अवाध जन्म-संख्या का
रोकने और वैज्ञानिक दृष्टिसे परिवार-का
नियोजन करनेके सम्बन्धम अधिकारी
विद्वानों की रचनाएँ रहेंगी । ८)
वार्षिक मूल्य मेजरर ग्राम्य मननेराली
को यह अक मुफ्त दिया जायगा ।

३३, नेताजी सुभाष रोड

समाजवादी ग्रंथमाला की पुस्तकें
के मिलने का पता :—

१ सोशललिस्टपार्टी ६ तुलौकरोड बम्बई

२ श्री टी०आर० राव, ११४बी०

जे० पटेल रोड, बम्बई ४

३ आधुनिक पुस्तक भवन १३०/२१

कलाकार स्ट्रीट कलकत्ता

४ दिग्विजय चौधम (दक्षिण भारतके

सभी रेलवे स्टेशनों पर) मद्रास ।

५ बालकृष्ण बुक शोप

हजरत गज, लखनऊ ।

६ श्री परमेश्वर साहु-५३ न्यू होस्टल

३, बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी ।

७ श्री नागरमल जैन, जैन एजड सन्ध

पो० पिलानी, राजस्थान ।

८ गोपाल कृष्ण जोशी, डबकरोका

५, श्री, मोती चौक पो० जोधपुर

९ समाजवादी साहित्य सदन

४४ सीवला माता बाजार

इन्दौर सिटी, मध्य भारत ।

१० गोमल सदर ८२/३५३ चौदू

गुच्छा टोला, काठमाडौं, नेपाल

११ वैद्यनाथ पुरतक मन्दिर

लहेरियासराय—दरभंगा ।

१२ कालेज स्टोर—टावर चौक, दरभंगा

१३ ठाकुर रामेश्वर शर्मा इकबाल,

होस्टल पटना कालेज, पटना

१४ श्री मनमोहन चटर्जी,

एजेन्ट, मोतीभील

१५ सच्चू बाबू, ८

मरावा